



भारत का राजपत्र The Gazette of India

शासक द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 12, 1994/ कार्तिक 21, 1916

No. 46]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 12, 1994/KARTIKA 21, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government
of India (other than the Ministry of Defence)

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधि, कार्य विभाग)

न्यायिक खण्ड

सूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1994

का.प्रा. 3133 :—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री एफ.ए. खान, एडवोकेट के उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(132)/94—न्यायिक]
पी.सी. कन्नन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

NOTICE

New Delhi, the 4th October, 1994

S.O. 3133.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri F. A. Khan, Advocate for appointment as a Notary to practise in N.C.T. of Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5(132)/94-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

गृह मंत्रालय
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3134 :—इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थान कहा गया है) की बाबत जानकारी या उसे होने वाला नुकसान शत्रु के लिए उपयोगी होगा और केन्द्रीय सरकार इसे समीचीन समझती है कि उक्त स्थान का संरक्षण करने के लिए पूर्वावधानियां बरती जानी चाहिए :

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 की उपधारा (8) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त स्थान को प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है।

अनुसूची

संस्था/उपन का नाम	स्थान का नाम	क्षेत्र/ग्राम	पुलिस थाना	जिला	वाउण्डरी या स्थान का अन्य विवरण
सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद	सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद	टकसाल अहाता सैफाबाद खैराता- बाद, हैदराबाद-4	सैफाबाद पुलिस थाना लकड़ी का पुल, हैदराबाद-4	हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश	1. भवन 5 मीटर ऊंची अहाता दीवार से घिरे हुए है। प्रेस परिसर का कुल क्षेत्र 9960 वर्ग गज है। इसका परिवेश निम्नानुसार है : (1) उत्तर में बिजली घर और आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड भवन। (2) दक्षिण में लेखा अपार्टमेंट्स और आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड भवन। (3) पश्चिम में भारत-सरकार टकसाल। (4) पूर्व में आन्ध्र प्रदेश राज्य सचिवालय के अहाते की पिछली दीवार।

[फा.सं. II/17017/6/94-आई.एस. (यू एस डी-II)]

सी. फुसाग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th October, 1994

S.O. 3134 :—Whereas information with respect to, or damage to, the Security Printing Press, Hyderabad, fully described in the Schedule annexed hereto (thereinafter referred to as the said place) would be useful to an enemy and the Central Government considers it expedient that precautions should be taken to protect the said place;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923), the Central Government hereby declares the said place to be a prohibited place for the purposes of the said Act.

Schedule

Name of the installation	Name of Place	Locality/Village	Police Station	District	Boundary or other description of the place
Security Printing Press, Hyderabad.	Premises of security Printing Press, Hyderabad.	Mint. Compound, Saifabad, Khairatabad Hyderabad-4.	Saifabad Police Station Lakdika Pul, Hyderabad-4.	Hyderabad-1, Andhra Pradesh.	Buildings are surrounded by compound wall of 5 meter height. The total area of the Press Premises is 9960 Square yards. Its surroundings are as follows :— (i) in North—Power House and Andhra Pradesh State Electricity Board Buildings. (ii) in South—Lekha Apartments and Andhra Pradesh State Electricity Board Buildings. (iii) in West—India Government Mint. (iv) in East—Back compound Wall of Andhra Pradesh State Secretariat.

[F. No. II. 17017/6/94.IS(US D-II)]
C. PHUNSOOG, Jt. Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3135.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य सरकार की सहमति से, जो उनके द्वारा गृह (पुलिस) विभाग की अधिसूचना सं. 3/सी-4-1038/94-एच. (पी) 3791, तारीख 2-6-94 द्वारा दी गई थी, धनबाद के धनसौर पुलिस थाना बिहार में रजिस्ट्रीकृत मामला सं. 159, तारीख 1-3-93 में भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 436, 427, 120-ख और 201, तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 4 के अधीन अपराध (अपराधों) के और पूर्वोक्त मामले के संबंध में वैसे ही संव्यवहारों के अनुक्रम में किए गए और/या वैसे ही तथ्य या तथ्यों से उद्भूत उक्त अपराध (अपराधों) के संबंध में या उससे (उनसे) संबंधित किन्हीं अन्य अपराधों, प्रयत्नों, दुष्प्रेरण और

पड़्यंत्र के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य पर करती है।

[संख्या 228/42/94-ए.बी.डी. (II)]
आर.एस. बिष्ट, अव्वर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 26th October, 1994

S.O. 3135.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government, with the consent of the State Government of Bihar in their Notification from Home (Police) Department bearing No. 3/C4-1038/94 H(P) 3791 dated 2-6-94, accorded by them, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Bihar for investigation of offence(s) u/s 457, 436, 427, 120-B and 201 IPC and Section 4 of Prevention of Damages to Public Property Act, 1984 registered at Dhanbad P.S. Dhanbar, Bihar, in their Case No. 159 dated 1-3-93 and any other offences, attempts, abetment and conspiracy in relation to or in connection with the said offence(s) committed in the course of same transactions and or arising out of the same fact or facts in relation to the aforesaid Case.

[No. 228/42/94-AVD. II]
R. S. BISHT, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

महानिदेशक (आयकर छूट) का कार्यालय

कलकत्ता, 2 मार्च, 1992

आयकर

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 599/फा.सं. डी.जी./एम-16/कल./35/
(1) (ii)/89-आ.कर (छूट)]

ए. के. विश्वास (उपनिदेशक)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF INCOME
TAX (EXEMPTIONS)

Calcutta, the 2nd March, 1992

INCOME TAX

का.आ. 3136.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम 1962 के नियम 6 के अधीन विहिा प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग औद्योगिक भवन न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने-अपने आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

निम्बकर ऐग्रिकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एम.ए.आर.आई.)

पो. बाक्स नं. 44, फल्टन-415523

जिला-सतारा, महाराष्ट्र।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदित की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र

S.O. 3136.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research :
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year. and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Nimbkar Agricultural Research Institute (NARI),

P.O. Box 44, Phaltan-415523,

Dist.-Satara, Maharashtra.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE: The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemption), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 599/F. No. DG/M-16/Cal./35(1)(ii)/89-IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 2 मार्च, 1992

आयकर

का.आ. 3137—सबसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है की निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(पेंतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के अण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "सब" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिय प्राप्त धन के लिय एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने अध्यक्ष, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सोसायटी आफ न्यूक्लीयर मेडिसिन इण्डिया,
मार्फत, रेडिएशन मेडिसिन सेंटर,
टाटा मेमोरियल सेंटर, एनेक्स
जरबाई वादिया रोड, परेल,
बम्बई-400012

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन का अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिय सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आवेदन उपयुक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिय आवेदन करें। अनुमोदन की

अवधि बढ़ाने के लिये संबंध में किये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की प्रस्तुत करना है।

[सं. 600 (फा.स. डी. जी./ एम-26/कल./35/(1)
(ii) 89-आ.कर(छूट)]

ए.के. बिस्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 2nd March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3137.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Society of Nuclear Medicine, India,
C/o, Radiation Medicine Centre,
Tata Memorial Centre, Annexe,
Jerbai Wadia Road, Parol, Bombay-400012.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1992.

NOTE : The organisation is advised to apply (in triplicate for the further extension of the approval, of the Director General of Income-tax (Exemptions) Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 600/F. No. DG/M-26/Cal/35(1)(ii)/80]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 2 मार्च, 1992

आयकर

का.आ. 3138—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा (35 पेंतीस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” प्रवर्ग के के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग औद्योगिक भवन न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इन्स्टिट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेन्ट,
पोस्ट बाक्स नं.-60
आनन्द-388001
गुजरात।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सूझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन करें।

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करता है।

[सं. 601/फा. सं. डी. जी./जी-6/कल./35/(1)
(iii)/89 आ. कर (छूट)]

ए. के. बिस्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 2nd March, 1992

INCOME-TAX.

S.O. 3138.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category Institution subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, “Technology Bhawan”, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Institute of Rural Management,
Post Box No. 60,
Anand-388001,
Gujarat.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE: The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisations, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 601/F. No. DG/O-6/Cal/35(1)(iii)/89]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 6 मार्च, 1992

आयकर

का.आ. 3139—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संस्थान/संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग औद्योगिक भवन न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

वि बिडला इन्स्टिट्यूट आफ साइप्रनटिफिक रिसर्च,
78, सैयद अमीर अलि एवेन्यू,

कलकत्ता-700019

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में जहां अनुमोदित आदेश उपयुक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र

की 6 प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 602/फा. सं. डी. जी./डब्ल्यू. बी.-11/कल./35/(1) (ii)/89 आ. कर (छूट)]

ए. के. बिशवास, उप निदेशक

Calcutta, the 6th March, 1992

INCOME TAX

S.O. 3139.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

The Birla Institute of Scientific Research,
78, Syed Amid Ali Avenue,
Calcutta-700019.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

Note.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 602/F. No. DG/WB-11/Cal/35(1)(ii)/89 I.T.(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 2 मार्च, 1992

Calcutta, the 6th March, 1992

आयकर

(INCOME-TAX)

का.आ. 3140—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(पेंतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान-संव” प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग औद्योगिक भवन न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने-अपने आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

विवेकानन्द मेडिकल रिसर्च सोसाइटी,
लातूर, महाराष्ट्र।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सूझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में जहां अनुमोदित आदेश उर्पयुक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में कि एआवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 603 /फा. सं. डी. जी./एम-15/कल./35]

(1) (ii) /89 आ. कर (छूट)]

ए. के. विश्वास, उप निदेशक

S.O. 3140.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category “Association” subject to the following conditions:

(i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, “Technology Bhawan”, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Vivekanand Medical Research Society,
Latur, Maharashtra.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

Note.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 603/F. No. DG/M-15/Cal/35(1)(ii);89-I.T.(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता 2-3-92

आयकर

का.आ. 3141-सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्न-लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(पैकीस/एक/दो) को उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित गतों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति आय-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को भेजना करेगा।

संगठन का नाम

फार्मिस्बर्ग इनस्टिट्यूट,
गंगानगर, पो. आ.- इचालकराजी,
पिन-416416, महाराष्ट्र।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदन आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन करें।

2471 GI/94-2

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 604 / डा. सं. डॉ. आ./एम-74/का./33]

(1) (ii)/89]

ए. के. बिश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 17th March, 1992

INCOME-TX

S.O. 3141.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Fic Research Institute,
Ganganagar, P.O. Ichalkaranji,
Pin-416416, Maharashtra.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

Note.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[सं. 604/डा. सं. डॉ. आ./एम-74/का/35(1)(ii)/89]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 17 मार्च, 1992

Calcutta, the 17th March, 1992

आयकर

INCOME-TAX

का.आ. 3142—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (नोत/एन/दो) को उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संव" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई, तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों को एक प्रति आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

आनम साइंटिफिक एण्ड टेक्नोलॉजिकल
अप्लाइड रिसर्च फाउंडेशन,
काडियाम-533126,
ईस्ट गोदावरी जिला
(ए. पी.)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में जहाँ अनुमोदन आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अवकाश उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 605/फा. सं. जी. पी. 6/कल./35/

(1) (ii)/89]

ए. के. बिश्वास, उप निदेशक

S.O. 3142.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five) one/two of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research :

(i) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Anam Scientific and Technological
Applied Research Foundation,
Kadiyam-533126,
East Godavari Distt. (A.P.).

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

Note.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 605/F. No. DG/AP-6/Cal/35(1)(ii)/89]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 17 मार्च, 1992

आयकर

का.आ. 3143:—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्न-लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैरॉन/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अर्धीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्न-लिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अर्धीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियाँ एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महा-निदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

टेक्नोलॉजिकल नर्सरी आप्टिकल
रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट (टी एन ओ आर डी)
15/17, बहुमंजिल भवन,
एन. पी. एल. कालोनी,
नई दिल्ली-110060

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए मुहताव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आवेदन उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर पश्चात् उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आवेदन

प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करनी है।

[सं. 606/फा. सं. डी. जी./एन. डी 100/कल. 35 (1) (ii) / 92)]

ए. के. बिश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 17th March, 1992

(INCOME-TAX)

S.O. 3143.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five) one/two of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Technological Nursery Optics
Research and Development (TNORD),
15/17 Multistoreyed Building,
NPL Colony, New Delhi-110060.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1993.

Note.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 606/F. No. DG/ND-100 Cal/35(1)(ii)/92]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 17 मार्च, 1992

आयकर

क्र.आ. 3144 :—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्-द्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन का, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैरोस/एक/तीन) का उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अर्थात् विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रयोग के अर्थात् अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने-अपने, शक्तियों एवं दैनिक-कार्यों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संस्था का नाम

पैन एशिया मैनेजमेंट एंड रूरल रिसर्च सोसाइटी प्राइवेट लि.,
30/22, Rohtak Road, नई दिल्ली-110005.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अर्थात् के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अर्थात् बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अर्थात् की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अर्थात्

बढ़ाने के लिए आवेदन करे। अनुमोदन की अर्थात् बढ़ाने के संबंध में लिए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 607 (पा. सं. डॉ. जी./एन. डॉ.-65/कल./
35.(1) (iii)/90/आ. कर (छूट)]

ए. क. बिस्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 17th March, 1992

(INCOME-TAX)

S.O. 3144.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five)one(three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions ;

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016, for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Pan Asian Management and Rural
Research Organisation,
30/22, Rohtak Road,
New Delhi-110005.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

Note.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension or approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 607/F. No. DG/ND-65/Cal/25(1)(iii)/90]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 17 मार्च, 1992

आयकर

क्र.प्र. 3143:—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (वैतिस एक तीन) की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अर्धीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्न लिखित शर्तों पर "भंडारण" प्रवर्ग के अर्धीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यवाहियों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 'औद्योगिक भवन', न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आयस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महा निदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च,
धर्मा मार्ग,
चानक्यपुरी,
नई दिल्ली-110021

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन का अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझा दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदन आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पर्याप्त यथाशीघ्र अनुमोदन की

अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 608/फा. सं. डॉ. ऑ./एन डी-60/फा./35/
(1) (iii) (90)]

ए. के. बिश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 17th March, 1992

(INCOME-TAX)

S.O. 3143.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Centre for Policy Research,
Dharma Marg,
Chanakypuri,
New Delhi-110021.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1993.

Note.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the approval. In exceptional cases or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 608/F. No. DG/ND-60/Cd/35(1)(iii)/90]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 19 मार्च, 1992

आयकर

का.आ. 3146—सर्वसाधारण की सूचना के त्रिवे एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(पैर्तीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के त्रिवे सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहभाति से, आयकर नियम 1962 के नियम 6 के अधीन शिक्ति प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदन किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के त्रिवे प्राप्त धन के त्रिवे एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के त्रिवे प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, आयोगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेकों की एक प्रति अपने-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

जय रिसर्च फाउंडेशन,
आफ नेशनल हाइवे नं. 8
पी. ओ. बलवदा-396108,
तल-उमरगांव, डिस्ट्री बलसद
गुजरात, भारत

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के त्रिवे अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के त्रिवे सुझाव दिया जाता है। त्रिवेस मामलों में जहां अनुमोदन आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अवकाश वन अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो संगठन अनुमोदन आवेदन प्रार्थना करने के पश्चात् यथासंभव अनुमोदन को अवधि बढ़ाने के त्रिवे आवेदन करे।

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र को 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 609/फा. सं. डी. जी./जी-3/कल./35
(1) (ii)/(89)]

ए. के. बिस्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 19th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3146.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Jai Research Foundation,
Off National Highway No. 8,
P.O. Valvada-396108,
Tal. Umargaoi, Dist. Valasad,
Gujarat, India.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE : The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemption), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 609/F. No. DG G-3/Cal 35(iii)/89]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 19 मार्च 1992

आयकर

क्र.आ. 3147-96साधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (तीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के तहत, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संव" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदन किया गया है।

(1) साठह बीज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान मंडली कार्यालयों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सौरभ इन्स्टिट्यूट फॉर रीजिया रिसर्च फाउंडेशन,
सरोश भवन, 16 बी/1,
डा. अम्बेकर रोड,
पूणे-411001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सूचित किया जाता है। विभिन्न मामलों में, जहां अनुमोदन आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अवकाश उत्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदन आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन करें

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[नं. 610/फा. सं. डा. जे. एम-41/कल./35/
(1), (ii)/89]

ए. के. बिस्वास, डी. निदेशक

Calcutta, the 19th March, 1992

INCOME TAX

S.O. 3147.-It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

(i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Sorun Institute of India Research Foundation,
Sarosh Bhawan, 16-B/1, Dr. Ambedkar Road,
Pune-411001.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE: The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 610 F. No. DG/M 41/Cal/35(1)(i)/89]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 19 मार्च, 1992

आयकर

क्र.अं. 3148.—वैज्ञानिकों की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिष्ठाता आगे किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 का धारा 35 को उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी श्री वी. महाविदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अला देखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यालयों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी वर्य, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महाविदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

क्रिष्णामूर्ति फाउन्डेशन,
हण्डिया, वसन्त विहार,
64-65, ग्रीनवेज रोड,
मद्रास-600028

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-92 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महाविदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदन आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अवस्था उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथा-संभव अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करे।

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 611 (फा. सं. अं. जी./टी. एन.)/कल./35
(1) (iii)/89]

ए. के. बिश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 19th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 4148.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (iii) of subsection (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category 'Institution' subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year of 31st May of each year ; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income-expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Krishnamurti Foundation
India Vasanta Vihar,
64-65 Greenways Road,
Madras-600028.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-92.

NOTE : The organisation is advised to apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemption), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 611/F. No. DG/TN-7/Cal/35(1)(iii)/89]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 20 मार्च, 1992

आयकर

का.आ. 3149.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैंतीस/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक आयकर (छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली 110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक, आयकर, (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

शंकर विद्या केन्द्र,
पश्चिम मार्ग,
वसन्त विहार,
नई दिल्ली-110057

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदन आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[स. 612 /फा.सं. डी.जी./एन.डी.-24/कल./35/(1)(iii)/89]

ए.के.बिश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 20th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3149.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five)(three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year, and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Shankara Vidya Kendra,
Paschim Marg,
Vasant Vihar,
New Delhi-110057.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1992.

NOTE: The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval, in exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 612/F. No. DG/ND-24/Cal/35(1)(iii)/89]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 24 मार्च 1992

आयकर

का.आ. 3150.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्-द्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयक अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

टाटा एनर्जी रिसर्च इनस्टिट्यूट,
7, जोरबाग,
नई दिल्ली-110003.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1989 से 31-3-1990 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 613 / फा.सं.डी.जी./एन.डी.-82/कल./35/
(1) (ii)/90]

ए. के. बिस्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 24th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3150.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Tata Energy Research Institute,
7, Jorbagh,
New Delhi-110003.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

NOTE : The organisation is advised to apply (in triplicate) for the further extension of the approval to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 613/F. No. DG/ND-82/Cal/35(1)(ii)/90]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 24 मार्च, 1992

आयकर

का० आ० 3151.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग औद्योगिक भवन, न्यू मेहरीली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक आयकर (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

कैवल्यधाम श्रीमन् माधव
योग मन्दिर समिति,
लोनावाला-410403.
महाराष्ट्र।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1989 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिय प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन को अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 614/फा.सं.डी.जी./एम-19/कल./35(1)
(ii)/89-आ. कर (छूट)]

ए० के० बिश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 24th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3151.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Kaivalyadhama Shriman Madhava
Yoga Mandir Samiti,
Lonavala-410 403,
Maharashtra.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1992.

NOTE : The organisation is advised to apply (in triplicate for the further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval, in exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 614/F. No. DG|M-19/Cal|35(1)(ii)(89-IT(E))]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 21 मार्च, 1992

आयकर

कां.आ. 2152.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एन.द्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्न-लिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकल्पों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने व्यवस्थापकों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और, (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट,
बन्नारघाटा रोड,
बैंगलूर-560076

यह अधिसूचना दिनांक 30-7-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करे। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 615/फा. सं. डी. जी./के.टी.-39/कल./35/
(1) (iii)/91]

ए.के. बिश्वास, उर निदेशक

Calcutta, the 24th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3152.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian Institute of Management
Bannorghatta Road,
Bangalore-560076.

This Notification is effective for the period from 30-7-1991 to 31-3-1992.

NOTE : The organisation is advised to apply in (triplicate) for the further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval, in exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 615/F. No. DG/KT-39/Cal/35(1)(iii)/91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 25 मार्च, 1992

आयकर

का. आ. 3153.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान/संघ” प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिय प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

द इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च एण्ड ऐक्शन,
बी-4/22, आजाद अपार्टमेंट,
नई दिल्ली-110016

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अवधि उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनु-

मोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 616/फा.सं.डी जी./एन.डी.-10/कल./35
(1)(iii)/89]

ए.के. विश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 25th March, 1992

(INCOME-TAX)

S.O. 3153.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, “Technology Bhawan”, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

The Institute of Peace Research and Action
B-4/22, Azad Apartments,
New Delhi-110 016.

This notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

Note.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the receipt of the order of approval. Six copies the organisation may make an application for extension or approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No 616/F. No. DG/ND-10/Cal/35(1)(iii)/89]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 25 मार्च 1992

आयकर

का.आ. 3154.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (तैतीस/ एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, ऑद्यो-औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इण्डियन स्टैटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट,
203, बी.टी. रोड,
कलकत्ता-700036.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन

अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथा-शीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 617/फा.सं. डी.जी./इन्त्यु.बी.-40/कल./35/
(1) (iii)/90]

ए.के. विश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 25th March, 1994

(INCOME-TAX)

S.O. 3154.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income/expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian Statistical Institute,
203, B.T. Road,
Calcutta-700036.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

Note.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 617/F. No. DG/WB-40/Cal./35(1)(iii)/90]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 25 मार्च 1992

आयकर

का०आ० 3155—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उप धारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विश्लेषण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक, (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

चारुतर आरोग्य मण्डल मेडिकल
रिसर्च सोसाइटी,
वल्लभ विद्यानगर-388120,
पो. बाक्स नं.-7 जिला खेदा,
गुजरात।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त

अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 618 /फा.सं.डी.जी./जी-13/कल./35/(1)
(ii)/89-आ. कर (छूट)]

ए.के. बिस्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 25th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3155.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five[one]two) of the Income-tax Act, 1961 under the category “institution” subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, “Technology Bhawan”, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Charutar Arogya Mandal Medical Research Society, Vallabh Vidyanagar-338 120, P.B. No. 7, Distt. Kheda, Gujarat.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE: The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 618/F. No. DG/G-13/Cal/35(1)(ii)/89]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 25 मार्च, 1992

आयकर

का.आ. 3156:—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद द्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैरिस/एक/दो/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महारौली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रतिलिपि अपनी व्यय, प्राप्तियों एवं देन-दारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इण्डिया,
नेशनल इनस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन,
पो.आ. -जमाल ओसमानिया,
हैदराबाद-500097 (ए.पी.)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए बुसाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आवेदन उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आवेदन

प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करेगा।

[सं. 619 /फा.सं.डी.जी./ए.पी. 13/कल/35/(1)
(ii)/90-आ. कर (छूट)]

ए. के. बिस्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 25th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3156.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category Institution” subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary Department of Scientific & Industrial Research, “Technology Bhawan”, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Nutrition Society of India, National Institute of Nutrition, P.O. Jamal Osmania, Hyderabad-500 07 (A.P.)

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE: The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 619/F. No. DG/AP-13/Cal./35(1)(ii)/90]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 25 मार्च, 1992

आयकर

का.आ. 3157:—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(पैतीस/एक/दो/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान/संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने-अपने, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ना है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

गांधी लेबर इन्स्टीट्यूट,
थालटेज रोड,
अहमदाबाद-380052.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता की तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सूचाव दिया जाता है। विभिन्न मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें।

2471 GI/94-4

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 620 (फा.सं.डी.जी./जी-5/कल./35/(1)
(iii)/89-आ. कर(छूट)]

ए.के. बिश्वास, उप निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 25th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3157.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five) one (three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income-expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Gandhi Labour Institute, Thaltej Road, Ahmedabad-380052.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE: The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemption), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 620 (F. No. DG/G-5/Cal/35(1)(iii)/89]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 25 मार्च, 1992

आयकर

का.आ. 3158.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्द्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैनीस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित-प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महा-निदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इनस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट इन गवर्नमेंट,
बार्टन हिल,
त्रिवेन्द्रम-695037.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की

अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करे। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 621/फा.सं.डी.जी./के-3/कल./35/ (1)
(iii)/89]

ए.के. बिशवास, उप निदेशक

Calcutta, the 25th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3158—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Institute of Management in Government, Barton Hill,
Trivandrum-695037.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE : The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 621/F. No. DG/K-3/Cal/35(1)(iii)/89]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 25 मार्च, 1992

आयकर

का.आ. 3159.—सर्वसाधारण की भूचना के लिये एनद्वाय यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की एक प्रति अपनी-अपनी, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सोशल पालिसी रिसर्च इनस्टीट्यूट
नं. 5-डी, इनस्टीट्यूशनल एरिया,
झालाना-डूंगरी सिटी एक्सटेंशन स्कीम,
नैग्रर आर.टी.ओ. कार्यालय,
जायपुर-302004 (राजस्थान)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिये प्रभावी है

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए गुहाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अवकाश उक्त अवधि

की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात यथा-शीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 622 /फा.सं.डी.जी./आर.-2/कल./35/(1)
(iii)/89]

ए.के. बिश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 25th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3159.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific and Industrial Research for the purpose of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Social Policy Research Institute, No. 5-D, Institutional Area, Jhalana-doongri City Extension Scheme, Near R.T.O. Office, Jaipur-302004 (Rajasthan).

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE : The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 622/F. No. DG/R-2/Cal/35(1)(iii)/89]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 25 मार्च, 1992,

आयकर

का.आ. 3160—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैरीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "विश्वविद्यालय प्रवर्ग" के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य-कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहराली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों को एक प्रति अपनी व्यय, प्राप्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक, (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

गुजरात एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी,
सरदार क्रुशिनगर-385506,
जिला-बानसकन्था (गुजरात)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए

आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 623 (फा.सं. डी.जी./जी-40/कल./35/ (1) (ii)/90-आ. कर (छूट)]

ए.के. विश्वास, उप निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 25th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3160.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "University" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Gujarat Agricultural University, Sardar Krushinagar-385 506, Distt.-Banaskantha (Gujarat).

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1993.

NOTE : The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 623 /F. No. DG/G-40/Cal./35(1)(ii)/90]

A. K. BISWAS, Dy. Director
of Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 25 मार्च, 1992

आयकर

का.आ. 31.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैरोस/एक-दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन निहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदन किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों के लिए एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महरौली रोड नई दिल्ली 110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यवस्थापिकाओं एवं दारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

साइ टेक सेंटर,
131, कान्दिवली-इन्डस्ट्रियल इस्टेट,
कान्दिवली वेस्ट,
बम्बई-400067.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सूझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदन आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदन आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करे।

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[म. 624 फा.सं. डी.जी./एम-98/कल./35/ (1)
(ii)/90 आ. कर (छूट)]

ए०के० बिश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 25th March, 1992

INCOME TAX

S.O. 3161.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Sci—Tech. Centre, 131, Kandivli Industrial Estate, Kandivli West, Bombay-400 067.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE : The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid of shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 624/F. No. DG/M-98/Cal/35(1)(ii)/90]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 26 मार्च, 1992

आयकर

का.आ. 3162.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए, पत्र-द्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैनीम/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "विश्वविद्यालय" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महरौली रोड नई दिल्ली 110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की एक प्रति अपने-अपने, आयक्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

मैंगलोर विश्वविद्यालय,
मंगलागंगोत्री-574199,
कर्नाटक।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए, सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदन आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अवधि उबल अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन-पत्र

की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 625 (फा.सं.डो.जी. /क.टी. 25/कल./35/ (1) (ii)/90-आ. कर (छूट)]

ग. के. बिस्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 26th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3162.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five) of the Income-tax Act, 1961 under the category "University" subject to the following conditions :

- The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION :

Mangalore University, Mangalagangothri-574199, Karnataka.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 625]F. No. DG/KT-25/Cal./35(1)(ii)/90/IT(E)
A. K. BISWAS, Dy. Director.

कलकत्ता, 26 मार्च, 1992

(आयकर)

का.आ. 3163 :—मर्यादाधारण की सूचना के लिये एनद्द्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन का, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीम/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परोक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने-स्वयं, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

कल्याणी गोरक्षण ट्रस्ट,
240-ए, शानिवर पथ,
कल्याणी बिल्डिंग,
कराड-415 110 जिला-सतारा।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदन आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदन आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की

अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 626 (फा.यं 4 डी.जी./एम-125/कल./35/(1)
(ii)/90-आयकर (छूट)]

ए. के. बिश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 26th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3163.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, “Technology Bhawan”, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Kalyani Gorakshan Trust, 240 F, Shaniwar Peth, Kalyani Building, Karad-415110 Dist. Satara.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE : The organisation is advised to apply in (triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemption), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 626/F. No. DG/M-125/Cal/35(1)(ii)/90-IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 26 मार्च, 1992

(आयकर)

का. आ. 3164.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्न-लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीम/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की समाप्ति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्न-लिखित शर्तों पर “संस्थान/संघ” प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई, तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक, भवन न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने—व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

अलकेमाई रिसर्च सेंटर,
क्रेसेन्ट हाउस,
19, बालचंद हीराचंद मार्ग,
वर्ल्ड इस्टेट, बम्बई-400038.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदित की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए मुलाखत किया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें।
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[मं. 627 (फा.सं. डी.जी./एम-88/कल./35/(1)
(ii)/90-आ. कर (छूट)]

ए. क. बिश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 26th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3164.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category “Association” subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, “Technology Bhawan”, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Alchemic Research, Centre, Crescent House, 19, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate Bombay-400038.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE : The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemption), Calcutta through the Commissioner of Income-tax, Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 627/F. No. DG/M-88/Cal/35(1)(ii)/90-IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 25 मार्च, 1994

आयकर

का.आ. 3165—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्-द्वारा यह अधिनियम जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की अधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान/संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई, तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक, भवन न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने—अध्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

आई एन आई एल मेडिकल रिसर्च सोसाइटी,
16वां के.एम. टुमकुर रोड,
बैंगलूर-560073.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1994 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदित की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें।

2471 G1/94—5

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करता है।

[सं. 628/का.सं. डी.जी./के.टी. 12/कल./35,]

(1) (ii)/89/आ.कर. (छूट)]

ए. के. बिस्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 25th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3165.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific and Industrial Research for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

INYS MEDICAL Research Society, 16th K.M. Tumkur Road, Bangalore-560073.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1994.

NOTE: The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 628/F. No. DG/KT-12/Cal/35(1)(ii)/89]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 26 मार्च, 1994

आयकर

का० आ० 3166—उत्तरेन्द्राण को प्रस्ताव के लिए एन.डी.आर. द्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/दो) की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था/संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, म्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-अपनी, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट,
7, जोरबाग,
नई दिल्ली-110003

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:—संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता की तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अवधि उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक

पूर्व प्राप्त, आपत्ति, संयुक्त अनुमोदित आवेदन प्राप्त करने के पश्चात यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 629 (फा. सं. डी. जी. एन.डी. 82 कल./
35 (1) (ii) 90 आ. कर (छूट)]

ए. के. बिस्वास, उप निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 26th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3166.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific and Industrial Research for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Tata Energy Research Institute, 7, Jorbagh, New Delhi-110003.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE : The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 629/F. No. DG/ND-82/Cal/35(1)(ii)90-JT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 26 मार्च, 1992

आयकर

का.आ. 3167—सर्व साधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संव" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-130016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

जी.एस.एफ.बी. साइंस फाउन्डेशन,
पो.आ. फर्टिलाइजर नगर-391750
जिला-बरौदा

यह अधिसूचना दिनांक 22-1-1992 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन को समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आवेदन उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें।

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 630 (फा.सं. डी.जी. बी/55/कल./35/(1)
(ii)/91-भा. कर (छूट)]

ए. के. बिस्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 26th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3167.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific and Industrial Research for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

ASPC Science Foundation, P.O. Fertilisernagar-391750
Dist. Baroda.

This Notification is effective for the period from 22-1-1992- to 31-3-1993.

NOTE : The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 630/F. No. DG/G-55/Cal/35(1)(ii)/91-IT(E)]
A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 30 मार्च, 1992

आयकर

का. आ. 3168 :—सर्वसाधारण की सूचना के लिए
एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित
संघटन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35
(पैसीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए
सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की
सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम, 6 के अधीन
विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा
निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" वर्ग के अधीन अनुमोदित
किया गया है।

- (1) संघटन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के
लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों
का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वर्ष के
लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव,
वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक
भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016
को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लिखा-परीक्षित
वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-जब, आस्तियों
एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क)
महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव,
वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और
(ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट)
जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संघटन का नाम

भगवान महावीर मेडिकल रिसर्च सेंटर,
10-1-1, महावीर मार्ग,
हैदराबाद-500004 (ए.पी.)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992
तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी:—संघटन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के
लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर
आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में
संघटन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट)
कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव
दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश
उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अवकाश उक्त अवधि की
समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संघटन अनुमोदित आदेश

प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने
के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध
में किए आवेदनपत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और
औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 631 (फा.सं. डी.जी./ए.पी.-4/कल./35/(1)
(ii)/89 आ क (छूट)]

ए.के. बिश्वास, अप निदेशक

Calcutta, the 30th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3168.—It is hereby notified for general information that
the organisation mentioned below has been approved by the
Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules,
1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions)
in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific and
Industrial Research for the purpose of clause (ii) of sub-
section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the In-
come-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject
to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account
of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific
research activities to the Secretary, Department of
Scientific & Industrial Research, "Technology Bha-
wan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for
every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-
tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scien-
tific & Industrial Research and (c) Commissioner of
Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) hav-
ing jurisdiction over the organisation, by the 30th
June each year a copy of its audited annual accounts
showing its income expenditure and its assets and
liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Bhagwan Mahavir Medical Research Centre, 10-1-1,
Mahavir Marg, Hyderabad-500004(A.P.).

This Notification is effective for the period from
1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE : The organisation is advised to apply (in triplicate)
for further extension of the approval, to the Director General
of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commis-
sioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions)
having jurisdiction over the organisation, three months before
the expiry of the approval. In exceptional cases where the
order granting approval is received after the expiry of the
period of three months aforesaid or shortly before the expiry
of the said period, the organisation may make an application
for extension of approval as soon as possible after the
receipt of the order of approval. Six copies of the applica-
tion for extension of approval should be sent directly to the
Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 631/F. No. DG/AP-4/Cal/35(1)(ii)89-JT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 30 मार्च, 1992

आयकर

का. आ. 3169:—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (वैसीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लब्धाभरोक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

पेट्रोलियम कान्सर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन,
1008, न्यू दिल्ली हाउस,
27, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली-110001.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1994 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन को अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करे

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 632 (फा.स. डी.जी./एन.डी.-30/कल./35/
(1) (ii)/89-आ. कर (छूट)]

ए.के. बिश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 30th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3169.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five) on two of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research :
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research. "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Petroleum Conservation Research Association 1008, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1994

NOTE : The organisation is advised to apply in (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemption), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 632/F. No. DG/ND-30/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 30 मार्च, 1992

आयकर

का.आ.3170.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-11 0016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

पोटाश रिसर्च इनस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया,
सेक्टर-19, दुन्देहरा,
दिल्ली गुरुगांव रोड,
गुरुगांव-122001 (हरियाणा)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आवेदन उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आवेदन प्राप्त करने के पश्चात यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए

आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 633 / फा.सं. डी.जी./एच-1/कल./35/ (1)
(ii)/89-आ. कर (छूट)]

ए. के. बिस्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 30th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3170.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of the scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the: (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Potash Research Institute of India, Sector-19, Dundehra,
Delhi Gurgaon Road Gurgaon-122001 (Haryana).

This Notification is effective for the period from: 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE: The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 633/F. No. DG/H-1/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 30 मार्च, 1992

आयकर

का. आ. 3171.—सर्व साधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैरोस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इण्डकेम रिसर्च एण्ड डिवलपमेंट लैबरेटरी,
47, डिवलपड प्लाट्स फॉर इलेक्ट्रिकल एण्ड
इलेक्ट्रॉनिक्स इण्डस्ट्रीज, सेवारा विलेज,
पेरुंगुडी पोस्ट, मद्रास-600096.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 634 /फा.सं. डी.जी./टी.एन.-15/कल./35/
(1) (ii)/89-आ. कर (छूट)]

ए.के. बिश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 30th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3171.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Indchem Research and Development Laboratory, 47, Developed Plots for Electrical & Electronics Industries, Sevaram Village, Perungudi Post, Madras-600096.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE: The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemption), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 643/F. No. DG/TN-15/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 30 मार्च, 1992

आयकर

के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

35 -फा.सं.डी.जी./टी.एन. 27/6 कल. 35

(1) (iii) 89प्रो. कर (छूट)]

ए. के. बिस्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 30th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3172.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Madras Institute of Development Studies,
70, Second Main Road,
Gandhi Nagar, Adyar,
Madras-600020.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

Note.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 635/F. No. DG/TN-27/Cal/35(1)(iii)]89 I.T.(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कल.आ. 3172.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्-द्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैरीस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित अधिकारी प्रवीन् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनु-मोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आव-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

मद्रास इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज,
79, सेकण्ड मेन रोड,
गंधी नगर, अदियार,
मद्रास-600020.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुसाध दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ, हों संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने

कलकत्ता, 30 मार्च, 1992

आयकर

को. आ. 3173.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एवम् द्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रशर्ग के अर्थात् अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यक्रमों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, अस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

द मदर सर्विस सोसाइटी,
प्लॉट-4, वेंकट नगर एक्सटेंशन,
पण्डितबेरी-605011.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पण: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए

आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[नं. 636 /फा.सं. डी.जी./पौन-4/कल./35/(1)
(iii)/89]

ए. के. बिस्वास, डी. निदेशक

Calcutta, the 30th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3173.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

The Mother's Service Society,
Plot-4, Venkate Nagar Extension,
Pondicherry-605 011.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1992.

Note.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 636]F. No. DG[Pon-4/Cal]/35(1)(iii)/89
A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1992

आयकर

का.आ. 3174.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्न-लिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैनी 1/एफ/डी) को उपधारा (1) के बंड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्न-लिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित लेखों की एक प्रति अपनी-अपनी आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सीताराम भारतीय इनस्टीट्यूट ऑफ साइंस
एण्ड रिसर्च,
फ्लैट नं. 1-ई
216, ए.जे.सी. बोस रोड,
कलकत्ता-700017

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन करे। अनुमोदन

अवधिबढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करता है।

[गं. 637 /फा.सं. डी.जी./डक्यू.बी-38/कल./35
(1) (ii)/90-आ. कर (छूट)]

ए.के. बिश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 31st March, 1992
INCOME-TAX

S.O. 3174.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income, expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Sitaram Bharti Institute of Science & Research, Flat No. 1-E 216, A.J.C. Bose Road, Calcutta-700017.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992

Note.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension or approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 637/F. No. DG/WB-38/Cal/35(1)(ii)/90/IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1992

आयकर

का. आ. 3175.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 को धारा 35 (पैरोस/एक/वो) की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों के लिये एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरीली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने-अपने, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

अस्पेसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट,
प्लॉट नं.-1, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी,
माला रोड नं.-2, मलाद (वेस्ट)
बम्बई-400064.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतिशों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह के समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन करें अनुमोदन की अवधि बढ़ाने

के संबंध में किए आवेदन-पत्र को 6 प्रतियाँ सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 638 /का. सं. डी. जी./एम-6/कल./35/(1)
(ii) 89 भा. कर (छूट)]

ए. के. बिस्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3175.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Aspec Research Institute, Plot No. 1, Adarsh Housing Society, Cross Road, No. 2 Malad (West) Bombay 400064.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE : The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemption), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No 638/F. No. DG/M-6/Cal/35(1)(ii)/89/IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1992

सायकार

का.आ. 3176:—उत्पत्तिप्रमाण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के तहत निम्नलिखित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर 'विश्वविद्यालय' प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए मुक्त कराना लेना रहेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित खाशिका लेखों की एक प्रति अपनी व्यवस्थापिकाओं एवं निदेशकों के निरक्षण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ए) सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन आता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बिड़ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
मेसरा—835215
रांची—बिहार।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:—संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन आता है, के अधीन या आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सूचना दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदन आवेदन उक्त दो माह की समाप्ति पर अवकाश प्राप्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आवेदन प्राप्त करने की परामर्श दशाधीन अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन

करे। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में लिए आवेदनपत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करनी हैं।

[सं. 639 /फा. सं. डी. जी./बी.—1/कल./35 (1)
(ii)/89] अ. क. बिड़

ए.के. बिड़वास, उप निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3176.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "University" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Birla Institute of Technology Mesra-835215. Ranchi, Bihar.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

NOTE: The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemption), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 639/F. No. DG/B-1/Cal/35(1)(ii)89]
A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1992

आयकर

का. भा. 3177.—वर्षसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (वैशेष/एच/डो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर विभाग, 1962 के नियम 6 के अधीन सिद्धा प्रमाणित अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक प्रत्येक लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यालयों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रती अपने आयकर, प्रतियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महा-निदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

नागरी आई रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट,
मार्फत, सी. एच. नागरी मूनि. आई अस्पताल,
इलिसब्रिज, अहमदाबाद-380061,
भारत।

यह अधिसूचना दिनांक 9-12-1991 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी.—संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियाँ में आवेदन करने के लिए मुद्राव दिया जाता है। विवेक मामलों में, जहाँ अनुमोदित आवेदन उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर पत्रा डात अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् असाक्षीय अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन

करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियाँ सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करनी हों।

[सं. 640 /फा. सं. डी. जी./जी. 46/कल./35/(1)
(ii) 91]

ए. के. बिस्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3177.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Nagri Eye Research Foundation Trust, C/o, C.H. Nagri Muni. Eye Hospital Ellisbridge, Ahmedabad-380061, India.

This Notification is effective for the period from 9-12-1991 to 31-3-1993.

NOTE: The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 640/F, No. DG/G-48/Cal/35(1)(ii)91-IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1992

आयकर

का. आ. 3178:—संयसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम, 6 के अधीन बिहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "विश्वविद्यालय" प्रयोग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लिखों की एक प्रति अपने आव-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

गुलबर्गा विश्वविद्यालय,
"ज्ञान गंगा"

गुलबर्गा-585106.

यह अधिसूचना दिनांक 9-12-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की

अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 641 /फा. सं. डी. जी./के. टी. 29/कल./35/(1)
(ii)/90 आ. कर (छूट)]

ए. के. बिस्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3178.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five[one]two) of the Income-tax Act, 1961 under the category 'University' subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Gulbarga University, "Jnana Ganga" Gulbarga-585106.

This Notification is effective for the period from 9-12-1991 to 31-3-1992.

Note.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions) Calcutta through the Commissioner of Income tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid of shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 641/F. No. DG/KT-29/Cal/35(1)(ii)/90-IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1992

आयकर

का.आ. 3179 :—नर्वेसाधारण की सूचना के लिए एनद्द्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैराम/एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने-अध्य, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महा-निदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बिरला इकनोमिक रिसर्च फाउंडेशन,
9/1, आर. एन. मुखर्जी रोड,
कलकत्ता-700001.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पण: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महा-निदेशक (छूट), कलकत्ता की तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अवकाश उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की

अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 642/का. सं. डी. जी./उत्क्यू. बी.-8/कल./35 (1)
(iii)/89 आ. कर (छूट)]

ग. के. विश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1992

INCOME-TAX

S. O. 3179.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Birla Economic Research Foundation, 9/1, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700001.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

Note: The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemption) Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 642/E. No. DG/WB-8/Cal/35(1)(iii)/89-IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 20 मार्च, 1992

(आयकर)

का. आ. 3180.—संस्थापना की सूचना के लिये एन.आर. यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्न-विवरित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (देवास/एक/दो) की उपधारा (1) खण्ड (ii) के लिये, मानव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की महमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्न-लिखित शर्तों पर "नव" श्रेणी के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई, तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने—अध्यक्ष, भारतियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च फाउंडेशन,
5 ए/1, 2 व 3, अन्सारी रोड, दरियागंज,
नई दिल्ली-110002।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आवेदन उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 643/फा. सं. डी. जी./एन. डी. 2/कल./35(1)
(ii)/89-आ. कर (छूट)]

ए. के. बिस्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 20th March, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3180.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research :
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Associated Electronics Research Foundation, 5A/1, 2 & 3, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002.

This Notification is effective for the period from 1-4-92 to 31-3-95.

Note : The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions) Calcutta through the Commissioner of Income-tax/ Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 643/F. No. DG/ND-2/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 22 अप्रैल, 1992

आयकर

का.आ. 3181.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्-द्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैरिस/एक/दो) की उपधारा (i) के खंड (iii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-अपनी, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एण्ड डिवलपमेंट सेंटर,
225 ई, आचार्य जे. बी. बोस रोड,
कलकत्ता-700020.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1994 की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमानित आवेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उसकी अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[मं. 644/का. मं. डी. जी./इल्सू. बी. 46/कल./35 (1)
(ii)/91 आ. कर (छूट)]
ए. के. बिस्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 22nd April, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3181.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Electronics Research and Development Centre,
225E, Acharya J. C. Bose Road, Calcutta-700020.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1994.

Note: The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions) Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 644/F. No. DG/WB-46/Cal/35(1)(ii)/91-IT(E)]
A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 22 अप्रैल, 1992

आयकर

क्र.आ. 3182.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्न-लिखित संगठन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैरिस/एक/दो/तीन) की, उपधारा (i) के खंड (ii) के लिये सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्न-लिखित शर्तों पर "संस्थान/संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-अपनी आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सेन्टर फॉर रिसर्च इन मेंटल रिटार्डेशन - (क्रिमिअ)
खुशलदास दगाड़ा हाउस,
ऑफ कस्तूरबी रोड, मालाड (वेस्ट)
बम्बई-400064।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1994 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये मुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदन आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन करें। अनुमोदन

की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करनी हैं।

[क्र. 645/फा. सं. डी. जी./एम. 21/कल./35/(i)
(ii)/89/आ. कर (छूट)]

ए. के. विश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 22nd April, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3182.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Centre for Research in Mental Retardation (Cremere)
Khusaldas Bagara House, Off. Kasturba Road, Malad
(West), Bombay-400064.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1994.

Note : The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions) Calcutta through the Commissioner of Income-tax, Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 645/F. No DG/M-21/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 22 अप्रैल 1992

आयकर

का.आ.3183.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये
एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्न-
लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा
35 (पैरामीटर/एक/दो) की उपधारा (1) के खंड (ii) के
नियम, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की
सहमति में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन
लिखित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा
निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनु-
मोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन
के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों
का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक
वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनु-
संधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-
110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा-परीक्षित
वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-व्यय, आस्तियों एवं देन-
दारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट)
(ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग,
और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके
क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर,

अमरगढ़-364210

गुजरात—इण्डिया।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1993 तक
की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये
अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर
आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्रा-
धिकार में संगठन पड़ता है, माध्यम से
आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन
प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया
जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित
आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा
उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ
हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के
पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने
के लिये आवेदन करेगा। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने

के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां
सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
को प्रस्तुत करना है।

[सं. 646/फा. सं. डी. जी./जी-2/कल./35/(i)

(ii)/89-आ. कर (छूट)]

ए. के. बिस्वास, उप निदेशक (छूट)

Calcutta, the 22nd April, 1992

INCOME-TAX

S.O. 3183.—It is hereby notified for general information
that the organisation mentioned below has been approved by
the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax
Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions)
in concurrence with the Secretary, Department of
Scientific and Industrial Research for the purposes of clause
(ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two)
of the Income-tax Act, 1961 under the category Institution
subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain a separate account
of the sums received by it for Scientific Research;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific
research activities to the Secretary, Department of
Scientific and Industrial Research, "Technology
Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016
for every financial year by 31st May of each year ;
and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-
tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of
Scientific and Industrial Research and (c) Commis-
sioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions)
having jurisdiction over the organisation, by
the 30th June each year a copy of its audited
annual accounts showing its income expenditure
and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Tuberculosis Research Centre, Amargadh-
364210, Gujarat—India.

This Notification is effective for the period from
1-4-92 to 31-3-93.

Note : The organisation is advised to apply (in triplicate)
for further extension of the approval,
to the Director General of Income-tax (Exemptions)
Calcutta through the Commissioner of Income-tax/
Director of Income-tax (Exemptions) having juris-
diction over the organisation, three months before
the expiry of the approval. In exceptional cases
where the order granting approval is received after
the expiry of the period of three months aforesaid
or shortly before the expiry of the said period,
the organisation may make an application for exten-
sion of approval as soon as possible after the
receipt of the order of approval. Six copies of
the application for extension of approval should
be sent directly to the Secretary, Department of
Scientific and Industrial Research.

[No. 646]F. No. DG/G-2/Cal/35(1)(ii)/89;
A. K. BISWAS, Dy. Director.

कलकत्ता, 24 अप्रैल, 1992

Calcutta, the 24th April, 1992

(आयकर)

(Income-tax)

का.भा. 3184.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्द्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैरोस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष को 31 मई तक, [सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016] को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

विजन रिसर्च फाउन्डेशन,

18, कालेज रोड, मद्रास-600006।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-1994 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पण : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करनी हैं।

[सं. 647/फा. सं. डी. जी./टी. एन.-3/कल./35/ (1)
(ii)/89]

ए. के. विश्वास, उप निदेशक

S.O. 3184.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category Institution subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Vision Research Foundation, 18, College Road,
Madras-600006.

This Notification is effective for the period from
1-4-92 to 31-3-94.

NOTE.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 647/F. No. DG/TN-3/Cal. 35(1)(ii)/89]
A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 24 अप्रैल, 1992

(आयकर)

का. आ. 3185.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्द्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी—अध्य, आगिनियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

द इण्डियन सोसाइटी ऑफ एग्रिकल्चरल ईकनामिक्स,
46/48, एस्प्लानेड, एम. जी. रोड,
बम्बई-400001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन कर अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करनी हैं।

[सं. 648/फा. सं. डी. जी./एम-33/कल./35 (1)

(ii)/89]

ए. के. बिस्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 24th April, 1992
(Income-tax)

S.O. 3185.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five) one[two] of the Income-tax Act, 1961 under the category 'Institution' subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

The Indian Society of Agricultural Economics,
46/48, Esplanade, M.G. Road, Bombay-400001.

This Notification is effective for the period from 1-4-92 to 31-3-93.

NOTE.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 648/F. No. DG|M-33|Cal|35(1)(ii)|89]
A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 29 अप्रैल, 1992

Calcutta, the 29th April, 1992

आयकर

INCOME-TAX

का.आ. 3186:—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एनडॉर यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन की, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो/तीन) की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष को 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

वॉलन्टरी हेल्थ सर्विसेस,

आद्वर, मद्रास-600113

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1994 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करनी है।

[सं. 649/फा. सं. डी. ओ./टी. एन.-17/कल./35/(1)]

(ii)/89-आयकर (छूट)]

ए.के. विश्वास, उप निदेशक

S.O. 3186.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category 'Institution' subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintaining a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income, expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Voluntary Health Services, Adyar, Madras-600113.

This Notification is effective for the period from 1-4-92 to 31-3-94.

NOTE.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 649/F. DG/TN-17/Cal/35(1)(ii)/89]
A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 29 अप्रैल, 1992

Calcutta, the 29th April, 1992

आयकर

INCOME-TAX

का.प्रा. 3187.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एनडू द्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को महमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित; (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

कामायनी उद्योग केंद्र सोसाइटी,
1187/64, शिवाजी नगर,
पुणे-411005.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् बशर्तों अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करे। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करनी हों।

[मं. 650/फा. सं. डी. जी./एम-45/कल/35/ (1)
(ii)/89]

ए. के. शिवासा, उप निदेशक

S.O. 3187.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category Institution subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Kamayani Udyog Kendra Society, 1187/64,
Shivaji Nagar, Pune-411005.

This Notification is effective for the period from 1-4-92 to 31-3-95.

NOTE.—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of this period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 650/F. No. DG/M-45/Cal/35(1) (ii) 89]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 29 अप्रैल, 1992

आयकर

Calcutta, the 29th April, 1992

INCOME-TAX

क्र.सं. 3188:—सर्वसाधारण की सूचना के विधे
पुनर्द्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित
संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35/(पैंतास/
/एक/दो) की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के लिये,
सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की
सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन
विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा
निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान/संघ" प्रवर्ग के अधीन
अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के
लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों
का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के
लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव,
वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्यो-
गिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-
110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित
वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने-जय, आस्तियों
एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महा-
निदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक
व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर
आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार
में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

डाइबिटीज रिसर्च सेंटर फाउण्डेशन

नं.-4, मैन रोड, रयापुरम,

मद्रास-600013

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1993
तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए
अनुमोदन को गमावि के तीन माह पूर्व आयकर
आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार
में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर
महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में
आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है।
विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त
तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की
समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन
अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् पश्चात्प्राप्त
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करे।
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-
पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक
अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 651/क्र. सं. डी. जी./डी. एन.-18/कल./35/(1)

(ii)/89-आ. कर (छूट)]

ए.के. बिस्वास, उप निदेशक

S.O. 3188.—It is hereby notified for general in-
formation that the organisation mentioned below has
been approved by the Prescribed Authority under
Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Direc-
tor General of Income-tax (Exemptions) in concu-
rrence with the Secretary, Department of Scientific &
Industrial Research for the purposes of clause (ii) of
sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two)
of the Income-tax Act, 1961 under the category
Institution subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate
account of the sums received by it for
Scientific Research:
- (ii) It will furnish the Annual Return of its
scientific research activities to the Secretary,
Department of Scientific & Industrial Re-
search, "Technology Bhawan", New Meh-
rauli Road, New Delhi-110016 for every
financial year by 31st May of each year:
and
- (iii) It will submit to the (a) Director General
of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary,
Department of Scientific & Industrial Re-
search and (c) Commissioner of Income-
tax|Director of Income-tax (Exemptions)
having jurisdiction over the organisation, by
the 30th June each year a copy of its audited
annual accounts showing its income, ex-
penditure and its assets and liabilities

NAME OF THE ORGANISATION

Diabetes Research Centre Foundation, No. 4
Main Road, Royapuram, Madras-600013.

This Notification is effective for the period from
1-4-1992 to 31-3-1993.

NOTE.—The organisation is advised to apply
(in triplicate) for further extension of the
approval, to the Director General of
Income-tax (Exemptions), Calcutta through
the Commissioner of Income-tax|Director of
Income-tax (Exemptions) having jurisdic-
tion over the organisation, three months
before the expiry of the approval. In ex-
ceptional cases where the order granting
approval is received after the expiry of the
period of three months aforesaid or shortly
before the expiry of the said period, the
organisation may make an application for
extension of approval as soon as possible
after the receipt of the order of approval.
Six copies of the application for extension
of approval should be sent directly to the
Secretary, Department of Scientific & Indus-
trial Research.

[No. 651/F. No. DG|TN-18|Cal|35(1)(ii)|89-IT(E)|
A. K. BISWAS, Dy. Director

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

बम्बई, 5 अक्टूबर, 1994

अधिसूचना सं० एफ०ई०आर०ए० 159/94-आरबी

का०आ०3189. -विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 29 की उप-धारा (1) और धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसरण में रिजर्व बैंक एतद्वारा निम्नलिखित की अनुमति देता है।

(1) भारतीय राष्ट्रिकता अथवा मूल के किसी अनिवामी (एन आर आई) तथा किसी विदेशी निगमित निकाय (सीसीबी) का प्रत्यावर्तन के आधार पर खरीद,

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का अपनी पंजियों अथवा बहियों में, जिनमें प्रतिभूतियां पंजीकृत अथवा अभिलिखित की जाती हैं, केन्द्र सरकार द्वारा विनिवेश के माध्यम से बेचे गए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के किसी शेयर की खरीद के फलस्वरूप शेयरों के धारक का भारत के बाहर का पना निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंकित करने,

(क) किसी भी समय अनिवामी भारतीय अथवा विदेशी निगमित निकाय द्वारा धारित शेयरों की राशि संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की चुकता पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) खरीद प्रतिफल/बोली मूल्य सामान्य बैंकिंग माध्यम से अथवा निवेशक द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा में कारोबार करने हेतु प्राधिकृत बैंकों अथवा भारत स्थित प्राधिकृत सहकारी/बाणिज्यिक बैंकों में रखे गये अनिवामी विदेशी (एन आर आई) विदेशी मुद्रा अनिवामी (एफ सी एन आर) खाने में धारित निधियों के अंतरण द्वारा विदेश से प्रेषण के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए,

(ग) बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में संबंधित प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा नामोविदित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में बोली राशि/खरीद प्रतिफल के साथ आबंटन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

स्पष्टीकरण :

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ :-

I. कोई भी व्यक्ति (जो पाकिस्तान अथवा बंगला देश का नागरिक नहीं है) "भारतीय मूल" का समझा जाएगा, यदि--

(i) वह, किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट का धारक रहा हो, अथवा

(ii) वह अथवा उसके माता-पिता में से कोई अथवा उसके पितामह-पितामही में से कोई भारतीय

2471 GI/94-8

संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम 1955 (1955 का 57) के आधार पर भारत का नागरिक था, अथवा

(iii) वह व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल (पाकिस्तान अथवा बंगला देश का नागरिक नहीं) के किसी व्यक्ति का पति/की पत्नी है।

II. "सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम" का अर्थ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (36ए) में दी गयी परिभाषा के अनुसार "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी" से है।

III. "विदेशी निगमित निकाय" का अर्थ किसी विदेशी कंपनी, भागीदारी फर्म, सोसाइटी अथवा अन्य निगमित निकाय से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से न्यूनतम 60 प्रतिशत की सीमा तक अनिवामी भारतीयों के अधिस्वामित्व वाली हो अथवा उसमें ऐसा विदेशी न्यास (ट्रस्ट) शामिल हो जिसमें प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से अनिवामी भारतीयों का न्यूनतम 60 प्रतिशत लाभकारी हित अपरिवर्तनीय रूप से शामिल हो।

[सं० 54(65)सीसीआई/94-1745]

डी०आर० मेहता, उप गवर्नर

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

Bombay, the 5th October, 1994

[NOTIFICATION NO. F.E.R.A. 159/94-RB]

S.O. 3189.--In pursuance of sub-section (1) of Section 29 and sub-section (4) of Section 19 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973), the Reserve Bank hereby permits.

(1) a non-resident of Indian nationality or origin (NRI) and an Overseas Corporate Body (OCB) to purchase on repatriation basis;

(2) The Public Sector Enterprise to enter in its register or books, in which securities are registered or inscribed, an address outside India of a holder of any shares, consequent on his purchase of a share of Public Sector Enterprise (PSE) sold by way of disinvestment by the Central Government, subject to the conditions, that :--

(a) the holding of shares by a NRI or by an OCB, at any time does not exceed one per cent of the paid up capital of the Public Sector Enterprise concerned;

(b) the purchase consideration/bid money is received by way of remittance from abroad through normal banking channels or by transfer of funds held in investor's NRE/FCNR account maintained with banks authorised to deal in foreign exchange in India or with authorised co-operative commercial banks in India;

(c) the application is submitted, along with deposit of bid money/purchase consideration at the branch of State Bank of India designated by the Central Government for that purpose in the notice inviting the bids.

EXPLANATIONS :

For the purpose of this Notification—

1. A person (not being a citizen of Pakistan or Bangladesh), shall be deemed to be of 'Indian Origin', if—

- (i) he, at any time, held Indian passport, or
- (ii) he or either of his parents or any of his grand parents was a citizen of India by virtue of the Constitution of India or the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955); or
- (iii) that person is the spouse of an Indian citizen or of a person of Indian origin (not being a citizen of Pakistan or Bangladesh).

II. A 'Public sector enterprise' means "a public sector company" as defined in sub-section (36A) of Section 2 of the Income Tax Act, 1961.

III. 'Overseas Corporate Body' means any overseas company, partnership firm, society and other corporate body predominantly owned directly or indirectly to the extent of at least 60 per cent by NRIs and includes any overseas trust in which not less than seventy percent beneficial interest is held by NRIs, directly/indirectly but irrevocably.

[No. 54(65)/CC/94-1745]

D. R. MEHTA, Dy. Governor

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1994

आयकर

का०आ० 3190.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "श्रीमद सज्जयिनी सद्धर्म सिंहासन श्री तरलाबालु जगद्गुरु ब्रह्ममठ, सीरीगेरे-कर्नाटक" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभि-

लाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग में लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं० 9625 (फा० सं० 197/41/94-आयकर नि०-1)]

साधना पवाडिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 11th October, 1994

(INCOME-TAX)

S.O. 3190.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Srimadujyini Suddharma Simhasana Sri Taralabalu Jagadguru Brihanmath, Sirigere-Karnataka" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9625(F. No. 197/41/94-ITA-D)]

SADHNA PAVADIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1994

आयकर

का०आ० 3191.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "डाओसीज आफ कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-

रखाव में स्वच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारित के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं० 9628/फा० सं० 197/90/94-आयकर नि०-1]
साधना पवाडिया, अवर सचिव

New Delhi, the 11th October, 1994

(INCOME-TAX)

S.O. 3191.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Diocese of Calcutta" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9628(F. No. 197/90/94-ITA-I)]
SADHNA PAVADIA, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1994

का आ 3192.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशकों के रूप में नामित करती है:—

धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत:

1. श्री आर.वी. गुप्ता, केन्द्रीय सरकार
विशेष सचिव, के प्रसाद पर्यन्त
बैंकिंग प्रभाग,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय।

2. श्री एम.सी. गुप्ता, केन्द्रीय सरकार
सचिव, के प्रसाद पर्यन्त
औद्योगिक विकास विभाग,
उद्योग मंत्रालय

धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत:—

3. श्री ए. बेसेट सी. राज, 18 अप्रैल, 1977
प्रबंध निदेशक, तक
बेसेट राज कन्सल्टेंट्स (प्रा.) लि.,
35. दूसरा आस स्ट्रीट,
आर.के. नगर,
मद्रास-600028
4. डा. एस.के. गुप्ता, 18 अप्रैल,
भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 1977 तक
मेटालार्जिकल इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स
(इंडिया) लि.,
5/6, शांति निकेतन,
नई दिल्ली-110021
5. श्री रामप्रसाद गोयनका, पहली जून,
"गोयनका निवास", 1977 तक
19, बेलवेडेयर रोड,
अलिपुर,
करकता-700027

धारा (6) की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के अन्तर्गत:—

6. श्री डी. बामू, चयनित निदेशक
अध्यक्ष, के कार्यभार ग्रहण
भारतीय स्टेट बैंक, करने तक
बम्बई।
7. सुश्री टी.एम. वकील, चयनित निदेशक
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, के कार्यभार ग्रहण
भारतीय निर्यात-आयात बैंक, करने तक
बम्बई।
8. डा. शंकर एन. आचार्य, चयनित निदेशक
मुख्य आर्थिक सलाहकार, कार्यभार ग्रहण
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, करने तक
(आर्थिक प्रभाग)
9. श्री एन. विश्वास, चयनित निदेशक
सचिव और महानिदेशक के कार्यभार
(तकनीकी विकास), ग्रहण करने तक
उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक विकास विभाग।

[फा सं 7/12/94-वी प्रो -1]
के.के. मंगल, अवर सचिव

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

(Banking Division)

New Delhi, the 24th October, 1994

S.O. 3192 —In pursuance of sub-section (1) of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby nominates the following persons as Directors of the Industrial Development Bank of India :—

Under clause (c) of sub-section (1) of section 6 :—

1. Shri R.V. Gupta, During the pleasure of the Central Government.
Special Secretary,
Banking Division,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance.
2. Shri M.C. Gupta, During the pleasure of the Central Government.
Secretary,
Department of Industrial Development,
Ministry of Industry.

Under clause (d) of sub-section (1) of Section 6 :—

3. Shri A. Besant C. Raj, Upto 18th April, 1997.
Managing Director,
Besant Raj Consultants (P) Ltd.,
35, 2nd Cross Street, R.K. Nagar,
Madras-600 028.
4. Dr. S.K. Gupta, Upto 18th April, 1997.
Former Chairman and Managing Director,
Metallurgical Engineering Consultants (India) Ltd.,
5/6, Shanti-Niketan,
New Delhi-110 021.
5. Shri Rama Prasad Goenka, Upto 1st June, 1997.
"Goenka Niwas",
19, Belvedere Road, Alipore,
Calcutta-700 027.

Under clause (e) of sub-section (1) of Section 6 :—

6. Shri D. Basu, Until assumption of charge by elected director.
Chairman,
State Bank of India, Bombay.
7. Ms. T.M. Vakil, Until assumption of charge by elected director.
Chairman & Managing Director,
Export-Import Bank of India,
Bombay.
8. Dr. Shankara N. Acharya, Until assumption of charge by elected director
Chief Economic Adviser,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
(Economic Division)
9. Shri N. Biswas, Until assumption of charge by elected director
Secretary and Director General
(Technical Development),
Ministry of Industry,
Department of Industrial Development.

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3193.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के उपबंध पञ्जाब नेशनल बैंक पर 31 दिसम्बर, 1994 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक इस बैंक से दिनांक 31 मार्च, 1994 तक की स्थिति के अनुसार, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखाओं और तुलनपत्र को निर्धारित ढंग में प्रकाशित करने और उसकी तीन प्रतियां भारतीय रिजर्व बैंक को 30 सितम्बर, 1994 तक की बड़ाई हुई अवधि के अन्दर-अन्दर विवरणियों के रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

[सं. 12/9/93-बी ओ ए.]

बी.एल. सचदेव, अवर सचिव

New Delhi, the 26th October, 1994

S.O. 3193.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Sec. 31 of the said Act shall not apply to Punjab National Bank upto 31st December, 1994 in so far as it is required to publish the accounts and balance sheet as at 31st March, 1994 together with auditors' report in the prescribed manner and submit three copies thereof as returns to the Reserve Bank of India within the extended period upto 30th September, 1994.

[No. 12/9/93-BOA]

B. L. SACHDEVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3194.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्वारा श्री के.सी. चौधरी, वर्तमान महाप्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक के रूप में परामर्शित) के रूप में नियुक्ति करती है।

[सं. एफ. 9/3/94-बी.ओ. आई.]

के.के. मंगल, अवर सचिव

New Delhi, the 26th October, 1994

S.O. 3194.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri K. C. Chowdhary, presently General Manager, Bank of Baroda as a whole-time Director (designated as the Executive Director) of Central Bank of India for a period of five years from the date of his taking charge.

[F. No. 9/3/94-B.O.I]

K. K. MANGAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3195.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के उपबंध काशीनाथ सेठ बैंक लि. पर 30 नवम्बर, 1994 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक इस बैंक से दिनांक 31 मार्च, 1994 तक की स्थिति के अनुसार, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखाओं और तुलनपत्र को निर्धारित ढंग में प्रकाशित करने और उसकी तीन प्रतियां भारतीय रिजर्व बैंक को 30 सितम्बर, 1994 तक की बड़ाई हुई अवधि के अन्दर-अन्दर विवरणियों के रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

[सं. 15/8/93-बी ओ ए.]

बी.एल. सचदेव, अवर सचिव

New Delhi, the 31st October, 1994

S.O. 3195.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 31 of the said Act, shall not apply to the Kashi Nath Seth Bank Ltd. upto 30th November, 1994 in so far as it is required to publish the accounts and balance sheet as at 31st March, 1994 together with auditors' report in the prescribed manner and submit three copies thereof as returns to the Reserve Bank of India within the extended period upto 30th September, 1994.

[F. No. 15/8/93-BOA]

B. L. SACHDEVA, Under Secy.

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3196.—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उप नियम (2), नियम 12 के उप नियम (2) के खंड (ख) तथा नियम 24 के उप नियम (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. 633, दिनांक 28 फरवरी, 1957 की अधिसूचना में और अधिक संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में, “राष्ट्रीय प्रतिवर्ण सर्वेक्षण संगठन” शीर्ष, “क्षेत्र संकार्य प्रभाग” उप शीर्ष के अंतर्गत भाग III सामान्य केन्द्रीय सेवा-वर्गी 1 में खंड (क) के सामने भोजन प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रति स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
“मुख्यालय पर सभी पद	उप निदेशक (प्रशासन)	उप निदेशक (प्रशासन) प्रशासनिक अधिकारी	सभी (i) से (iv)	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उप निदेशक (प्रशासन)”

टिप्पणी :—मंत्रिमंडल सचिवालय में भारत सरकार की मूल अधिसूचना दिनांक 28-2-1957 के एड. आर. ओ. संख्या 633 के सहित प्रकाशित की गई थी बाव में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए थे :—

मंत्रिमंडल सचिवालय अधिसूचना संख्या सा.आ. 2119 दिनांक 3-9-88

मंत्रिमंडल सचिवालय (सांख्यिकी विभाग) अधिसूचना संख्या सा.आ. 898 दिनांक 31-3-1982

मंत्रिमंडल सचिवालय

(सांख्यिकी विभाग)

अधिसूचना सं. सा.आ. 436 दिनांक 8-2-1964
सं. सा. आ. 3846 दिनांक 14-11-1964
सं. सा. आ. 1004 दिनांक 3-4-1963
सं. सा. आ. 2718 दिनांक 17-9-1966
सं. सा. आ. 368 दिनांक 4-2-1967
सं. सा. आ. 2250 दिनांक 14-6-1969
सं. सा. आ. 4172 दिनांक 18-10-1969
सं. सा. आ. 1684 दिनांक 24-4-1971
सं. सा. आ. 1685 दिनांक 24-4-1971
सं. सा. आ. 585 दिनांक 3-3-1973

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

अधिसूचना सं. सा. आ. 1951 दिनांक 12-6-1976
सं. सा. आ. 289 दिनांक 4-2-1978
सं. सा. आ. 367 दिनांक 16-2-1980
सं. सा. आ. 2775 दिनांक 7-11-1992

[सं. ए.-60011/1/92--प्रशा. III]

डी. एन. सेठी, चवर डायरेक्टर

MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(Department of Statistics)

New Delhi, the 25th October, 1994

S.O.3196:—In pursuance of sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendment in the Schedule to the notification of the Government of India in the Cabinet Secretariat, No. S.R.O. 633, dated the 28th February, 1957, namely :—

In the said Schedule, in part-III General Central Service-Class IV, under heading “National Sample Survey Organisation” under sub-heading “Field Operations Division”, for the existing entries against clause (a) the following entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
All posts at Headquarters	Deputy Director (Administration)	Deputy Director (Administration)	All	Chief Administrative Officer
		Administrative Officer	(1) to (iv)	Deputy Director (Administration)

NOTE :—Original Notification of Government of India in the Cabinet Secretariat was published vide S.R.O. No. 633 dated 28-2-1957. Subsequently, the following amendments were notified :—

Cabinet Secretariat Notification No. S.O. 2119 dt. 3-9-60

Cabinet Secretariat

(Department of Statistics) Notification No. S.O. 898 dated 31-3-1962.

Cabinet Secretariat

(Department of Statistics) Notifications

No. S.O. 436 dated 8-2-1964.

No. S.O. 3846 dated 14-11-1964.

No. S.O. 1004 dated 3-04-1965.

No. S.O. 2718 dated 17-9-1966.

No. S.O. 368 dated 4-02-1967.

No. S.O. 2250 dated 14-6-1969.

No. S.O. 4172 dated 18-10-1969.

No. S.O. 1684 dated 24-4-1971.

No. S.O. 1685 dated 24-4-1971.

No. S.O. 585 dated 3-03-1973.

Ministry of Planning

(Department of Statistics) Notifications

No. S.O. 1951 dated 12-06-1976.

No. S.O. 289 dated 4-02-1978.

No. S.O. 367 dated 16-02-1980.

No. S.O. 2775 dated 7-11-1992.

[No. A-60011/1/92-Admn. III]

D.S. SETHI, Under Secy.

ताम्रिक प्रति, उपभोक्ता मामले और सांख्यिक बितरण मंत्रालय

(भारतीय मानक ब्यूरो)

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1994

क्र. भा. 3187.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 5 के उपविनियम (6) के अनुसरण में एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन प्रमाणन नमूने लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, उनकी अवधि समाप्त हो गई है:

अनुसूची

क्रम सं. (सी एम/एन)	लाइसेंस सं.	लाइसेंसधारी का नाम	आई एस संख्या	अवधि समाप्ति की तिथि	समाप्ति का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	0083737	लकी ऐसिड एण्ड केमिकल वर्क्स, 32/2, मुरारी पुरुर रोड, कलकत्ता-700067	आई एस 264: 1978	93-05-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक
2.	0368531	संजु इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., 12वां, किमी पोलाची रोड, मालुमाधेक पाट्टी पोस्ट, कोयम्बटूर-641021	आई एस 6595: 1988	93-07-16	मुद्रांकन शुल्क नहीं दिया
3.	0442941	निरूपति एण्ड कं., मार्शल हाउस (कमरा नं. 583), 33-1, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001	आई एस 10 (भाग 4): 1976	93-06-16	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ
4.	0481042	जे.एस. इंटरप्राइसेस, पी-3 गौर बी-4 ईड, एस्टेट, विशाखापत्तनम-530007	आई एस 204 (भाग 2): 1978	93-07-01	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ
5.	0539451	पटेल इंजीनियरिंग कं. लि. (तीराणा), अजय औद्योगिक बसहत, भावनगर रोड, राजकोट-360003	आई एस 10001: 1981	93-06-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक
6.	0585761	अन्ना इंडस्ट्रीज (पेंटस) प्रा. लि., 46, पुराना किला, लखनऊ-226001	आई एस 427: 1985	93-06-01	लाइसेंस धारी अनइच्छुक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. 0672037	पेस्ट कंट्रोल (इंडिया) प्रा. लि., यूसफ बिल्डिंग, एम.जी. रोड, पोस्ट बाक्स 1510, बम्बई-400023	ग्राई एम 1307: 1988	93-08-16	उत्पाद पर रोक	
8. 0685049	भारत पुनर्वसिद्धि मिल्स प्रा. लि., श्रीनिकेतन, 14, कवीनम रोड, बम्बई-400020	ग्राई एम 8291: 1976	93-08-16	नाइसंधारी अनइच्छुक	
9. 0683256	अपर इंडिया स्टील मैनुफैक्चरिंग एण्ड इंजी. क. लि., आनंदरी इंडस्ट्रियल फोवल् एस्टेट, पो. बा. नं. 119, वृधियाना-141018	ग्राई एम 1825: 1978	93-08-01	नाइसंधारी अनइच्छुक	
10. 0697267	भारत पेट्रोलेियम कार्पो., भारत भवन, 4 एण्ड 6, कुरीमनाथ रोड, बेलोई एस्टेट, पो. बा. नं. 688, बम्बई-400038	ग्राई एम 3576: 1977	93-07-16	नाइसंधारी अनइच्छुक	
11. 0912346	प्रकाश केबल्स एण्ड कंडक्टर्स, 22, कल्पना गोसावईटी, रेमकोर्म, बरोडा-390007	ग्राई एम 694: 1977	92-11-16	पुनरीक्षित का कार्यालय नहीं	
12. 0912447	प्रकाश केबल्स एण्ड कंडक्टर्स, 22, कल्पना गोसावईटी, रेमकोर्म, बरोडा-390007	ग्राई एम 1554 (भाग 1): 1988	92-11-16	पुनरीक्षित का कार्यालय नहीं	
13. 0983773	पेस्टो केम इंडिया, 966-67, गली तेजिन, पीछे नॉथवेली सिनेमा, विल्ली	ग्राई एम 2567: 1978	93-08-01	नाइसंधारी अनइच्छुक	
14. 1083035	श्रीराम इंड्रुल इनकार्पो., 11, मुरली जालाराम एस्टेट, नागरबेल हनुमान रोड, राबिल, ब्रह्मवीरवाड-380023	ग्राई एम 694: 1977	93-06-01	फैक्टरी बंद हो गई	
15. 1096347	ब्लू बुल होजरीज, 90 जी/2, कामराज रोड, निहपुर-638604	ग्राई एम 4964: 1980	93-07-15	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ	
16. 1106223	भारत पुनर्वसिद्धि मिल्स प्रा. लि., श्रीनिकेतन, 140 कवीनम रोड, बम्बई-400020	ग्राई एम 8028: 1987	93-08-16	नाइसंधारी अनइच्छुक	
17. 1164540	मुष्ठा इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन, बैजनाथ गावा, रायपुर-492001	ग्राई एम 389 (भाग 1): 1976	93-04-01	नाइसंधारी अनइच्छुक	
18. 1191644	इसेक्ट्रीसाइड्स एण्ड एलाइड कोरीकम्स 87/6, आर्कड रोड, मद्रास-600026	ग्राई एम 4323: 1980	93-06-15	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	1191745	इंतेक्टोसाइड्स एण्ड एलाइड केमिकल्स, 87/6, मार्केट रोड, मद्रास-600026	आई एस 3903 : 1984	93-06-15	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ
20.	1211725	एंग्लो इंडिया जूट मिल्स कं. लि., 31, नेताजी सुभाष रोड (सुबर), कलकत्ता-700001	आई एस 2580 : 1982	93-08-01	लाइसेंसधारी अनहस्तुक्त
21.	1313632	वैकटेश्वराय एगो केमिकल्स एण्ड मिनेरल्स (प्रा.) लि., प्लॉट नं. 3-बी, (एन पी) इंड. एस्टेट, अम्बातूर, मद्रास 600098	आई एस 8028 : 1987	93-06-31	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ
22.	1318945	नैनी हूरे पाइप्ट, 72 ए, सूरज कुंड, मेरठ-250002	आई एस 458 : 1988	93-07-01	फैक्टरी बंद
23.	1392048	अकेमिक्स केमिकल्स एण्ड कोटिंग्स प्रा. लि., 327, गांधी जेनपुर, मेहरोली, नई दिल्ली-110030	आई एस 2074 : 1979	93-06-16	लाइसेंसधारी अनहस्तुक्त
24.	1435141	द इंडियन स्टील रोलिंग मिल्स लि., राजमी हाऊस, 156, ग्रेनेस रोड, मद्रास-600006	आई एस 226 : 1975	93-06-16	बापस
25.	1524241	गोइनका इंडस्ट्रीज, एफ 374, रोड नं. 9 एफ, विश्वकर्मा इंड. एरिया, अदपुर	आई एस 581 : 1978	93-03-16	लाइसेंसधारी अनहस्तुक्त
26.	1565760	डी. आर. इंडस्ट्रीज, मंडी रोड, जालंधर	आई एस 6750 : 1985	93-06-01	लाइसेंसधारी अनहस्तुक्त
27.	1586257	भारत फाउंड्री, अम्मानकुलम रोड, पप्पानाईसकेन पलायम, कोयम्बतूर-641037	आई एस 6595 : 1980	93-07-16	लाइसेंसधारी अनहस्तुक्त
28.	1594363	प्रकाश केबल्स प्रा. लि., ए 1/171 जी आई डी सी, पो. बा. नं. 27, अंकलेश्वर-398002	आई एस 392 (भाग 1)	92-11-16	लाइसेंसधारी अनहस्तुक्त
29.	1699983	विजयो प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्रा. लि., 70, हाडा पासर इंड. एस्टेट, पूणे-411013	आई एस 418 : 1978	93-06-01	लाइसेंसधारी अनहस्तुक्त
30.	1793746	फेफ्रीग्लास पिलविस्टन लि., पो. बो. नं. 211, एलबी शास्त्री मार्ग, थाणे-4	आई एस 8183 : 1976	93-06-16	लाइसेंसधारी अनहस्तुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	1703746	कैब्री अलास लिमिटेड लि., पो. बा. नं० 211, एल.बी. शास्त्री मार्ग, बाण-400602	आईएस 8183 : 1976	93-06-16	निरीक्षण परीक्षण योजना के अनुसार नहीं
32.	1754662	पेस्ट कंट्रोल (इंडिया) प्रा. लि., मुमुफ बिल्डिंग, एम.जी. रोड, पोस्ट बॉक्स नं. 1510, बम्बई 400022	आई एस 1111 : 1966	91-08-16	निरीक्षण परीक्षण योजना के अनुसार नहीं
33.	1840152	पिक्स प्राटो इंड., सिमला पुरी, मिल रोड, लुधियाना	आई एस 6639 : 1972	93-07-01	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक
34.	1919163	खेतान इलेक्ट्रिकल्स लि., प्लॉट नं. 14, मैक्टर 6, फरीदाबाद-121006	आई. एस 8978 : 1985	93-06-01	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक
35.	1944263	गुजरात एग्री इंस्ट्रूमेंट कार्पो. लि., खेत-उद्योग भवन, सम्मुखः हाईकोर्ट, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380014	आईएस 7131 : 1973	91-08-01	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक
36.	1974878	मानविजय डवलपमेंट फं. लि., 59/1, कृष्णापुर रोड, कलकत्ता-700028	आईएस 7406 (भाग 2): 1984	91-05-15	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक
37.	1974979	मानविजय डवलपमेंट फं. लि., 59/1, कृष्णापुरी रोड, कलकत्ता-700028	आईएस 7406 (भाग 1): 1984	93-05-16	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक
38.	1978886	वेस्ट बंगाल लिमिटेड प्रा. लि. 16-ए, एयरपोर्ट हाऊस, 46/मी चौरंगी रोड, कलकत्ता-700071	आईएस 7406 (भाग 2): 84	84-05-16	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक
39.	1979181	हुगली सेमिनेटिंग इंड. 6 क्लेयरा, कलकत्ता-700001	आईएस 7406 (भाग 2) 84	93-05-16	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक
40.	1992175	वैन्टज पेस्टीसिड्स लि., 6-C-788/12, वूर्गा नगर कालोनी अमीरपेट, हैदराबाद-500016	आईएस 9356 : 1980	93-07-01	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ
41.	2075037	जे.एस. इंटरप्राइजेज, बी-39, बी-4 इंड. एस्टेट, विशाखापत्तनम-530007	आईएस 2681 : 1979	93-07-08	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
42.	2095148	हाई स्पीड अपलाइसेस (प्रा.) लि., बी-3 एण्ड बी-4 इंड. एस्टेट, विशाखापत्तनम	आईएस 2082 : 1985	91-04-01	नि.प.यो. का अनुसरण नहीं
43.	2105226	प्राइमर वैजिटबल प्रोडक्ट्स लि., 95, इंडस्ट्रियल एरिया, जेटवाडा, जयपुर-302012	आईएस 11351 : 1985	91-03-16	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक
44.	2114732	चनाना स्टील ट्यूब्स प्रा. लि., 26/4, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008	आईएस 1161 : 1979	93-05-16	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक
45.	2115653	विराल इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि., डी-7, एम आई सी सी, अम्बाड, नासिक-422001	आईएस 2465 : 1984	93-07-01	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक

(1)	2	(3)	(4)	(5)	(6)
46. 2124634 कंठ	लाइफ वैट्रीज (प्रा. लि.), कंठमेट रोड, कटक, उड़ीसा-753001		आईएस 7372: 1974	93-07-16	लाइसेंस का त्याग
47. 2146411	हावड़ा मिक्स कं. लि., 4, कल्याण रा कलकत्ता-700001		आईएस 12154: 1987	93-09-01	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक
48. 2218077	गोयल ब्रदर्स, न्यू इंड. एरिया, गोंगाव, रायपुर (म. प्र.)		आईएस 1003 (भाग 1) 1977	93-01-16	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक
49. 2229244	गुप्ता बाकलाइट फैक्टरी, 220, गली बशेशर नाथ, समीप रोबिन सिनेमा, राजगी मंडी, दिल्ली-110007		आईएस 1258: 1987	93-04-01	कार्य संतीपजनक नहीं
50. 2245747	स्टैण्डर्ड इंडस्ट्रीज, बो-5, को. प्रा. इंड. एस्टेट, बालानगर, हैदराबाद-500007		आईएस 916: 1975	93-07-01	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ
51. 2248248	काइगोलाइट इंटर्प्राइजेज, 1-8-449, गम्मुख पुलिस लाइन, सिकन्दराबाद-500001		आईएस 11246: 1985	93-06-16	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ
52. 2258352	नारायणा इंडस्ट्रीज, 125-बो, अविनाशी रोड, पोलामेडू पोस्ट, कोयंबटूर		आईएस 9283: 1979	93-07-16	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ
53. 2359556	शिवालिक एप्री कैमोकल्स बो-59, फेस-7, इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट, सास नगर-160051		आईएस 561: 1978	93-07-16	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक
54. 2345246	कलियुग पेंट्स, 5, पुष्पावराज मार्केट, सम्मुख खान मार्केट, नई दिल्ली-110001		आईएस 1111: 1975	93-6-16	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक
55. 2386159	मोनट्री इंडस्ट्रीज लि., गांव : डोनसा, तहसील : बूलाचूर, जिला होशियारपुर, 144522		आईएस 9355: 1980	93-07-16	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक
56. 2387161	सुप्रोम सैटप्रोडक्ट्स प्रा. लि., जो 854/14, एन. बी. के. आई, एरिया अयपुर-302013		आई एस 398 (भाग 2): 1976	93-03-16	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक
57. 2392356	अरिहंत कंठकटर्स, भलेज रोड, समीप ओषर भिज, अनन्त (गुजरात)-388001		आईएस 398 (भाग 1): 1976	93-08-01	लाइसेंसधारी अनहस्त्युक

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 17th October, 1994

S.O. 3197:—In pursuance of sub-regulation (6) of Regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, it is, hereby notified that the Certification Marks Licences, details of which are mentioned in the following Schedule, have expired :

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Name of the licensee	Number of the relevant Indian Standard	Date of expiry	Reason for expiry
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	0083737	Lucky acid & Chemical works 32/2, Murari Pukur Road, Calcutta 700 067	IS 264 : 1976	93-05-16	Party not interested
2	0368551	Manju Electrical Industries Pvt. Ltd., 12th, KM Pollachi Road, Malumacham Pattj Post Coimbatore 641 021	IS 6595 : 1980	93-07-16	Marking fees not paid
3	0442941	Tirupaty & Co. Marshall House (Room No. 563) 33-1, Netaji Subhas Road, Calcutta 700 001	IS 10 (Part 4) : 1976	93-06-16	Application not received
4	0481042	J.S. Enterprises B-3 & B-4, Indl. Estate, Visakhapatnam 530 007	IS 204 (Part 2) : 1978	93-07-01	Application not received
5	0539451	Patel Engineering Co. (Saurashtra) Ltd. Aji Udyogic Vasant, Bhavnagar Road, Rajkot 360 003	IS 10001 : 1981	93-06-16	Party not interested
6	0585761	Alka Industries (Paints) Pvt. Ltd., 46, Purana Kila, Lucknow 226 001	IS 427 : 1965	93-06-01	Party not interested
7	0632037	Pest Control (India) Pvt. Ltd., Yusuf Bldg., M.G. Road, Post Box-1510, Bombay 400 023	IS 1307 : 1988	93-08-16	Product Banned
8	0655049	Bharat Pulverising Mills Pvt. Ltd., "Shriniketan" 14, Queens Road Bombay 400 020	IS 8291 : 1976	93-08-16	Party not interested
9	0683256	Upper India Steel Manufacturing & Engg. Co. Ltd., Dhandri Industrial Focal Point, P.O. Box No. 119 Ludhiana 141 010	IS 1875 : 1978	93-08-01	Party not interested
10	0697267	Bharat Petroleum Corpn. Bharat Bhavan 4 & 6, Currimbhoy Road, Ballard Estate, P.B. No. 688 Bombay 400 038	IS 3575 : 1977	93-07-16	Party not interested
11	0912346	Parekh Cables & Conductors 22, Kalpana Society Race Course, Baroda 390 007	IS 694 : 1977	92-11-16	Revised is not implemented
12	0912447	Parekh Cables & Conductors 22, Kalpana Society Race Course, Baroda 390 007	IS 1554 (Part 1) : 1988	92-11-16	Revised is not implemented
13	0983773	Pesto Chem India 966-67, Gali Telian behind Novelty Cinema, Delhi	IS 2567 : 1978	93-08-01	Party not interested

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14 1083035	Shri Ram Insul Incorp, 11, Surti Jalaram Estate Nagarwel Hanuman Road, Rakhial Ahmedabad 380 023	IS 694 : 1977	93-06-01	Factory Closed
15 1096347	Blue Bull Hoseries 90/ G/2, Kamaraj Road, Tirupur 638 604.	IS 4964 : 1980	93-07-15	Application not received
16 1106223	Bharat Pulverising Mills Pvt. Ltd., "Shriniketan" 14, Queens Road, Bombay 400 020	IS 8028 : 1987	93-08-16	Party not interested
17 1164540	Mutha Industrial Corporations Baij Nath Para, Raipur 492 001.	IS 398 (Part 1) : 1976	93-01-01	Party not interested
18 1191644	Insecticides & Allied Chemicals 87/6, Arcot Road, Madras 600 026.	IS 4323 : 1980	93-06-15	Application not received
19 1191745	Insecticides & Allied Chemicals 87/6, Arcot Road Madras 600 026	IS 3903 : 1984	93-06-15	Application not received
20 1211725	Anglo India Jute Mills Co. Ltd., 31, Netaji Subhas Road (Lower) Calcutta 700 001.	IS 2580 : 1982	93-08-01	Party not interested
21 1313632	Venkateswara Agro Chemicals & Minerals (P) Ltd., Plot 3-B, (N.P.) Indl. Estate Ambattur, Madras 600 098	IS 8028 : 1987	93-06-31	Application not received
22 1318945	Naini Hure Pipes 72A, Surajkund Meerut 250002	IS 458 : 1988	93-07-01	Factory Closed
23 1392048	Acromix Chemicals and Coatings Pvt. Ltd., 327, Village Jonapur Mehrauli, New Delhi 110 030	IS 2074 : 1979	93-06-16	Party not interested
24 1435141	The Indian Steel Rolling Mills Ltd., Rajam House, 156, Greames Road Madras 600 006	IS 226 : 1975	93-07-16	IS withdrawn
25 1524241	Goenka Industries F-374, Road No. 9 F Vishwakarma Indl. Area, Jaipur	IS 561 : 1978	93-03-16	Party not interested
26 1565760	D.R. Industries, Mandi Road, Jalandhar 144 001	IS 6750 : 1985	93-06-01	Party not interested
27 1566257	Bharat Foundry Ammankulam Road, Pappanaicken Palayam Coimbatore 641 037	IS 6595 : 1980	93-07-16	Marking fees not paid
28 1594363	Parkesh Cables Pvt. Ltd. A/1/711, GIDC P.B. No. 27 Ankleshwar 393 002	IS 398 (Part : 1) : 1976	92-11-16	Party not interested
29 1699983	Bijlee Products (India) Pvt. Ltd., 70, HADA-Pasar Indl. Estate Pune 411 013	IS 418 : 1978	93-06-01	Party not interested
30 1703746	Fibreglass Pilkington Ltd., P.B. No. 211 L.B. Shastri Marg Thane 400 602	IS 8183 : 1976	93-06-16	Party not interested

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31 1703746	Fibreglass Pilkington Ltd., P.B. No. 211 L.B. Shastri Marg, Thane 400 602	IS 8183 : 1976	93-06-16	STI Not follow
32 1754662	Pest Control (India Pvt. Ltd., Yusuf Bldgs. M.G. Road, Post Box -1510 Bombay 400 023	IS 1311 : 1966	93-08-16	STI Not follow
33 1840352	Picks auto Inds. Simla Puri, Bill Road, Ludhiana 141 003	IS 6639 : 1972	93-07-01	Party not interested
34 1919163	Khaitan Electrical Ltd., Plot No. 14, Sector 6 Faridabad 121 006	IS 8978 : 1985	93-06-01	Party not interested
35 1944263	Gujarat Agro Industries Corpn. Ltd., Khet-Udyog Bhavan, Opp. High Court Navarangpura, Ahmedabad 300 014	IS 7121 : 1973	93-08-01	Party not interested
36 1974878	Manvijaya Development Co. Ltd., 59/1, Krishnapur Road, Calcutta 700028.	IS 7406 (Part 2) : 1984	93-05-16	Party not interested
37 1974979	Manvijaya Development Co. Ltd., 59/1, Krishnapur Road, Calcutta 7000 28	IS 7406 (Part I) : 1984	93-05-16	Party not interested
38 1978886	West Bengal Laminators Pvt. Ltd., 16-A Everest House, 46/C Chowringhee Road, Calcutta 700071	IS 7406 (Part 2) : 1984	93-05-16	Party not interested
39 1979181	Hooghly Laminating Inds., 6, Civil Row, Calcutta 700 001.	IS 7406 (Part 2) : 1984	93-05-16	Party not interested
40 1992173	Vantech Pesticides Ltd., 6-3-788/A/12, Durga Nagar Colony Ameerpet Hyderabad 500016	IS 9356 : 1980	93-07-01	Application not received
41 2073037	J.S. Enterprises, B-3 & B-4, Indl. Estate, Visakhapatnam 530 007	IS 2681 : 1979	93-07-01	Application not received
42 2095148	HI-Speed Appliances (P) Ltd., Atur Chaambers, 2A, Moledina Road, Pune 411001	IS 2082 : 1985	93-04-01	STI not follow
43 2105226	Premier Vegetable Products Ltd., 95, Industrial Area, Jhotwara, Jaipur 302012.	IS 11352 : 1985	93-03-16	Party not interested

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
44	2114732	Chanana Steel Tubes Pvt. Ltd., 26/4 East Patel Nagar, New Delhi 110008	IS 1161 : 1979	93-05-16	Party not interested
45	2115633	Viral Electronics Pvt. Ltd., D-7, MIDC Ambad, Nasik 422001.	IS 2465 : 1984	93-07-01	Party not Interested
46	2124634	Life Batteries (P) Ltd., Cantonment Road, Cuttack (Orissa) 753001.	IS 7372 : 1984	93-07-16	Surrendered the Licence
47	2146442	Howrah Mills Co. Ltd., 4, Clive Row Calcutta 700 001.	IS 12154 : 1987	93-09-01	Party not interested
48	2218037	Goel Brothers New Indl. Area, Gogaon, Raipur (MP).	IS 1003 (Part 1) : 1977	93-03-16	Party not interested
49	2229244	Gupta Bakelite Factory 220, Gali Basheshar Nath, Near Robbin Cinema Subzi Mandi, Delhi 7.	IS 1258 : 1987	93-04-01	Performance unsatisfactory
50	2245747	Standard Industries B-5, Co-op. Indl. Estate, Balanagar, Hyderabad-500037.	IS 916 : 1975	93-07-01	Application not received
51	2248248	Fibrolite Enterprises 1-8-449, Opp. Police Lines, Secunderabad (AP) 500003.	IS 11246 : 1985	93-06-16	Application not received
52	2258352	Narayan Industries 1251-B, Avanashi Road, Peelamedu Post, Coimbatore 641004.	IS 9283 : 1979	93-07-16	Application not received
53	2259556	Shivalik Agro Chemicals, B-59, Phase VII Industrial Focal Point, Sas Nagar 160 051.	IS 561 : 1978	93-07-16	Party not interested
54	2345246	Philips Paints, 5, Prithviraj Market, Opp. Khan Market, New Delhi 110003.	IS 133 : 1975	93-06-16	Party not interested
55	2386159	Montari Industries Ltd., Vill. Toansa Teh : Bulachur Distt. Hoshiarpur 144 522	IS 9355 : 1980	93-07-16	Party not interested
56	2387161	Supreme Metprods Pvt. Ltd., G-854/14 N, Vki Area, Jaipur 302013	IS 398 (Part 2) : 1976	93-03-16	Party not interested
57	2392356	Arihant Conductors Bhalej Road, Near Over Bridge, Anand (Gujarat) 388001.	IS 398 (Part 1) : 1976	93-08-01	Party not interested

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1994

कां.प्रा. 3198—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 5 के उपविनियम (6) के अनुसरण में एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन प्रमाणन मुहर लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची के दिए गए हैं, उनकी अवधि समाप्त हो गई है :

अनुसूची

क्रम लाइसेंस सं० सं० (सीएम/एल)	लाइसेंसधारी का नाम	आईएस : संख्या	प्रवधि समाप्ति की तिथि	समाप्ति का कारण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 0043018	द इंडियन आइरन एण्ड स्टील कं० लि०, आईएस : 226:1975 इम्फो हाउस, 50 चौहंगी रोड, कलकत्ता-700 071		93-10-01	वापस	
2. 0129836	मोदी स्टील्स, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद-201204	आईएस : 280:1978	93-07-16	लाइसेंसधारी अनहस्तक	
3. 0198653	एमएचआई केबल्स एंड कंडक्टर्स लि०, एक्जीक्यूटिव रोड, पटना-800 001	आईएस 398 (भाग 2) : 1976	93-06-16	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ	
4. 0209753	यूनिक इंडस्ट्रीज, 10, अम्बिका को-आप-हाउसिंग सोसाइटी, पेटलड रोड, पो०प्रा० बॉक्स नं० 34, नादिया-387 001	आईएस 398 (भाग 1)	93-05-01	लाइसेंसधारी की रूचि नहीं	
5. 0371338	वेद स्टील्स, इय एरिया, लखनऊ-226 004	आईएस 6915:1978	93-08-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
6. 0428240	के०आर० स्टील यूनिट लि०, एवरेस्ट हाउस, 10वीं मंजिल, 46सी—चौहंगी रोड, कलकत्ता-700 071	आईएस 6914:1978	93-10-01	लाइसेंसधारी की रूचि नहीं	
7. 0428341	के०आर० स्टील यूनिट लि०, एवरेस्ट हाउस, 10वीं मंजिल, 46सी—चौहंगी रोड, कलकत्ता-700 071	आईएस 6915:1978	93-10-01	लाइसेंसधारी की रूचि नहीं	
8. 0655756	बीके पेस्टीसाइड्स लि०, 75 मोदी स्ट्रीट, पो० बा० 553, बम्बई-400 001	आईएस 2567:1978	93-07-16	कार्य असन्तोष प्रद	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	0699271	प्रकाश केबल्स एंड कंजक्टेर्स, 22, कल्याण सोसाइटी, रेमकोर्भ, यडोदा-390 007	आईएस 398 (भाग 1) : 1976	93-05-16	आवेदन प्राप्त नहीं
10.	0813243	सनयो इंडस्ट्रीज, 50-51, 60-61 इंडस्ट्रियल एरिया, डंडी-452 002	आईएस 2933:1975	93-09-18	लाइसेंसधारी की रूचि नहीं
11.	0893671	केपस केबल इंडस्ट्रीज, केसन हाउस, हिन्द मौराष्ट्र इंड एस्टेट, अंधेरी-कुर्ली रोड, मरोल नाका, बम्बई-400 059	आईएस-691-1977	93-09-01	कार्य संतोषप्रद नहीं
12.	0893772	केपस केबल इंडस्ट्रीज, केसन हाउस, हिन्द मौराष्ट्र इंड एस्टेट, अंधेरी-कुर्ली रोड, मरोल नाका, बम्बई-400 059	आईएस 1554 (भाग 1) : 1988	93-09-01	कार्य संतोषप्रद नहीं
13.	0954160	ट्रेडस्का (इंडिया) रवड बक्स, 170, गुजरात बेचारी महामंडल, औद्योगिक बसाहर, अहमदाबाद-382 410 (गुज)	आईएस 1370:1976	93-04-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
14.	1043730	एमएनआई केबल्स एंड कंजक्टेर्स लि०, एक्सीन्ग्रेशन रोड, पटना-800 001	आईएस 398 (भाग 1) : 1976	93-06-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
15.	1111014	प्रॉक्टर एण्ड गेबल इंडियन लि०, टिकआसेन हाउस, डा० ई० मोसेस रोड, बम्बई-400 011	आईएस 3134:1965	93-09-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
16.	1115931	स्पेशियल मशीनस, बाई पास कुंजपुरा रोड, करनाल-132 001	आईएस 814 (भाग 1) :	93-10-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
17.	1212929	कंचनजंगा लडाखी इंड० प्रा० लि०, लडाखी मेशन, बल्लुआखानी, गंगटोक 737 101	आईएस 398 (भाग 2), 1976	93-07-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
18.	1213880	इंडस्ट्रियल प्राइवेटस, प्लॉट नं० 4, इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कालोनी कुंजपुरा रोड, करनाल	आईएस 814 (भाग 1)	93-10-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
19.	1281241	एम०पी० स्टेट एगो इंडस्ट्रीज, डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि०, उरी मंजिल पंचानन, मालवीय नगर, भोपाल-462 003	आईएस 7122:1984	93-10-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	1332232	विजय पेंट इंडो, दौलत गंज, ग्वालियर-474 001	आईएस 427:1965	93-10-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक
21.	1342336	कोंटेंचा ब्रादर्सी, बी०डी० बार्दनवाला रोड, जामनगर-361 001	आईएस 10325:1986	93-10-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
22.	1355042	कुमुम इस्पात एण्ड वायर प्राइवेट्स प्रा० लि०, प्लॉट नं० ई-37, एमआईडीसी इंड एरिया, चिकलथाणे, औरंगाबाद-431 210	आईएस 6003:1983	93-06-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
23.	1390317	अम्बिका रि-रोलिंग मिल्स, साइजपुर बोगा, समीप : जी०टी० हाई स्कूल, अहमदाबाद-382 345	आईएस 228:1975	93-05-01	वापस
24.	1413030	स्वाती इंटरप्राइजेज, अजी इंडस्ट्रियल एस्टेट, राजकोट-360 003	आईएस 10001:1981	93-08-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक
25.	1426140	जय नित इंजीनियरिंग, जी-40 डी, लक्ष्मी वूलन मिल्स, रंभादेव शक्ति, मील लेन, महालक्ष्मी, बम्बई-400 011	आईएस 934:1989	93-08-01	कार्य संतोषप्रद नहीं
26.	1432438	मुकुंद आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लि०, खाल बहादुर शाम्बरी मार्ग, कुर्ला, बम्बई-400 070	आईएस 1786:1985	93-07-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
27.	1439755	असर स्पन पाइप प्राइवेट्स, चौरी-चौरा, गोरखपुर।	आईएस 458:1988	93-08-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
28.	1442744	मलहोत्रा स्टील इंड गुजरात प्रा० लि०, प्लॉट नं० 105, गांव तेमघर, कल्याण भिवंडी रोड, कल्याण, जिला थाणे-421 302	आईएस 2062:1984	93-08-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
29.	1463045	जयंत एक्सट्रूजन इंडिया लि०, विदेश्वर, जामनगर-361 002	आईएस 10633:1986	93-10-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
30.	1523340	भारत पुलवराइजिंग मिल्स, “श्री निकेतन”, 14 क्वींस रोड, बम्बई-400 020	आईएस 8708:1978	93-10-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
31.	1535448	जयंत एक्सट्रूजन इंडो लि०, विदेश्वर, जामनगर-361 002	आईएस 10325:1989	93-03-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.	1538454	बीनर्मे इंजीनियरिंग प्रा० लि०, प्लॉट नं० 31 एमआईडीसी इंड० एरिया, गुगुस रोड, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	आईएस 226:1975	93-05-01	वापस
33.	1553955	स्पानप्रो इंडस्ट्रीज, 50-51, 60-61 इंडस्ट्रियल एस्टेट, पोलोग्राउंड, इन्दौर-452 003	आईएस 341:1973	93-09-16	लाइसेंसधारी की रूचि नहीं
34.	1559553	ईगल स्टील्स, 10, हंसराज दामोदर ट्रस्ट बिल्डिंग, 42, कैंडी ब्रिज, बम्बई-400 004	आईएस 1977:1975	93-09-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
35.	1562451	जी०के० कंजुमर प्राइवट्स (प्रा०) लि०, एफ० 90/1 ओम्बेला इंड० एरिया, फेस 1, नई दिल्ली।	आईएस 10840:1986	93-05-16	लाइसेंसधारी की रूचि नहीं
36.	1608752	यूनिवर्सल कार्पोरेशन, 7, उद्योग मार्ग, गाला नं० 104, प्रथम तल, एम०बी० रोड, गौरेगांव, बम्बई।	आईएस 10840:1986	93-09-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
37.	1687370	परफेक्स सेनेट्री पाइप, इंडस्ट्रियल एरिया, भारतपुर।	आईएस 651:1980	93-05-16	लाइसेंसधारी की रूचि नहीं
38.	1703544	दिनेश सीमेंट उद्योग (प्रा०) लि०, खोकल रोड, भारतपुर, जिला रायपुर।	आईएस 269:1989	93-10-01	लाइसेंसधारी की रूचि नहीं
39.	1709960	डी० सर्ववाल मै०फै०लेव लि०, प्लॉट नं० 9 जी०टी० रोड, भवानीपुर, पो०ओ० भंझारी, कानपुर।	आईएस 4717:1980	93-08-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
40.	1711846	कोरस (इंडिया) लि०, नं० 7, केनाल स्ट्रीट, कलकत्ता-700 014	आईएस 4174:1977	93-07-16	लाइसेंसधारी की रूचि नहीं
41.	1720947	बी वजेरिया इंडस्ट्रीज, बोडक रोड, खमवाट-388 620	आईएस 2200:1962	93-08-16	कार्य संतोषप्रद नहीं
42.	1723550	पराग इंडस्ट्रीज, 54, 58 एम०ए० रोड, रंगोला कंपाउंड, जेकेव सर्किल, बम्बई।	आईएस 8808:1986	93-08-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43.	1728358	फ्लोक्सी फोम प्रा० लि०, पुश् कालन, खसरा नं० 106/37, दिल्ली-110041	आईएस 1741:1960	93-09-01	लाइसेंसधारी की रुचि नहीं
44.	1740146	कनोडिया स्टील्स (प्रो० आदित्य मिल्स लि०) स्टेडियम हाउस, दूसरा ब्लॉक, बीर नारिमन रोड, बम्बई-20	आईएस 2830:1975	93-10-01	लाइसेंसधारी की रुचि नहीं
45	1817559	मनीष रबड़ इंटरप्राइजेस, 50, यूनिफ इंडस्ट्रियल एस्टेट, राजेंद्र प्रसाद रोड, सम्मुख : जवाहर सिनेमा मल्ल (प) बम्बई-400 080	आईएस 5424:1969	93-05-01	लाइसेंसधारी की रुचि नहीं !
46.	1818561	राजेश -रि-रोलिंग्स (प्रा०) लि०, 535/बी, उर्ला इंड० कम्पलेक्स, रायपुर।	आईएस 1786:1985	93-05-01	लाइसेंसधारी की रुचि नहीं
47	1821146	मनीष ट्रांसमिशन प्राइवेट्स प्रा० लि०, ग्रोबिण्ड कम्पाउंड, ब्लॉक नं० 7, गांव दुनिया, पो०ओ० हलील-50	आईएस 398 (भाग 1) : 1976	93-05-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
48	1841152	रीता स्टील इंस्ट्रूज, 251, स्माल फैक्टरी एरिया, बगद गंज, नागपुर-440 008	आईएस 226:1975	93-05-01	वापस
49	1871161	चन्द्रकार बिस्कुट कम्पनी, अमीर बाग, चुख रोड, मैडल, मालवान-416 606	आईएस 1011:1981	93-09-01	कार्य संतोषप्रद नहीं
50	1909059	महाराष्ट्र स्टील रोलिंग एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, प्लॉट नं० 10, न्यू दाखाना मजगांव, बम्बई-400 010	आईएस 226:1975	93-05-01	वापस
51.	1986986	कुसुम इस्पात एण्ड वायर प्राइवेट्स प्रा. लि., प्लॉट ई-37, एम आई डी सी इंडस्ट्रियल एरिया, चिकल ठाणे, कलकत्ता-700 001	आई एस : 432 (भाग 2) : 1982	93-06-16	आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ
52.	1900990	कं. लि., 10, सिविल रोड, तीसरी मंजिल, कलकत्ता-700 001	आई एस : 3751 : 1966	93-06-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
53. 1990977	प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स (1935) लि., 311/312 चेतक सेंटर, 12/2 आर. एन. टी. मार्ग, इंदौर-452 001	आई एम 8051 : 1976	93-06-16	लाइसेंसधारी की रुचि नहीं	
54. 1993276	कृपि रसायन, लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेट, आर. के. आश्रम, मुजफ्फरपुर-843 116	आई एम / 8074 : 1980	93-07-01	आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ	
55. 1998286	अमर केबल्स, ए-28, नारायणा इंड. एरिया, फेस 1, नई दिल्ली-110028	आई एम 1554 (भाग 1) : 1988	93-07-16	आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ	
56. 2004725	बिट्यू बैग मैन्यूफैक्चरर्स, 144/145 जे. एम. मुखर्जी रोड, घूसुरी, हावड़ा	आई एम 7406 (भाग 1) : 1984	93-08-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
57. 2004826	बिट्यू बैग मैन्यूफैक्चरर्स, 144/145 जे. एन. मुखर्जी रोड, घूसुरी, हावड़ा	आई एम : 7406 (भाग 2) : 1984	93-08-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
58. 2015124	कोल्टस सीमेंट (प्रा.) लि. हलद्वानी, साउथन एवेन्यू, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065	आई एम : 269 : 1989	93-08-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
59. 2032831	छेविग्रोट कं. लि., 9, ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता-700 001	आई एम : 12154 : 1987	93-10-01	लाइसेंसधारी की रुचि नहीं	
60. 2101521	म. केबल्स कंडक्टर्स लि., एक्सीक्यूशन रोड, पटना-800 001	आई एम : 398 (भाग 5) : 1976	93-04-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
61. 2104931	महाराष्ट्र केबल इंडस्ट्रीज, शेड नं. 1, 49/2, इंड एरिया, कामनी मैन्यूफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, मेन रोड, उल्हास नगर-421 004	आई एम 694 : 1977	93-04-16	कार्य संतोषप्रद नहीं	
62. 2116938	मधुश्री ट्रेडर्स, 21, रेसीडेंसी रोड, जोधपुर	आई एम : 7231 : 1984	93-05-16	लाइसेंसधारी की रुचि नहीं	
63. 2120222	गंधार वायर एंड केबल्स प्रा. लि., श्रीचन्द अक्खरी स्ट्रीट, नया बाग, वैअवर (राजस्थान-305901)	398 (भाग 1) : 1976	93-06-01	लाइसेंसधारी की रुचि नहीं	
64. 2121729	भारत पुलवराइजिंग मिल्स, “श्री निकेतन” 14, बर्डीस रोड, बम्बई-400 020	आई एम 4323 : 1980	93-10-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	

1	2	3	4	5	6
65. 2121830	कृष्ण रमायन, लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेट, आर. के. आश्रम, मुजफ्फरपुर-843 116	आई एम 8023 : 1987	93-06-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
66. 2123733	सेलवेक्स केबल्स क. (प्रा.) लि., साकी बिहार रोड, बम्बई-400 072	आई एम 1554 (भाग 1) : 1988	93-06-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
67. 2123935	सेलवेक्स केबल्स क. (प्रा.) लि., साकी बिहार रोड, बम्बई-400 072	आई एम 694 : 1977	93-06-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
68. 2129947	सिंह एण्ड सिंह, 100 एफ इंड एस्टेट, गोविन्दपुरी, भोपाल-462 023	आई एम 1333 : 1978	93-07-01	लाइसेंसधारी की रुचि नहीं	
69. 2136742	शिल्पा रि-रोलर्स प्रा. लि., 2, सुराणा ले आउट, विजय नगर, नागपुर	आई एम 226 : 1975	93-05-01	वापस	
70. 2138140	धर्मीजा इंड. कार्पोरेशन, एस-5 इंड. एरिया, साइट ए, बाई पास, मथुरा	आई एम 1729 : 1979	93-08-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
71. 2141634	रेतोरिया लेमिनेटर्स प्रा. लि., 132 काटन स्ट्रीट, प्रथम मंजिल, कलकत्ता 700 007	आई एम : 7406 (भाग 1) : 1984	93-08-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
72. 2197358	जलगांव रि-रोलिंग इंडस्ट्रीज लि., 18-27 इंडस्ट्रियल एस्टेट, अजयनाथ रोड, जलगांव-425 001	आई एम 226 : 1975	93-05-01	वापस कर लिया	
73. 2204430	विशेष इस्पात प्रा. लि., समी : गुजरात स्टील ट्यूब्स, काली गाम, अहमदाबाद 382 470	आई एम 226 : 1975	93-05-01	वापस	
74. 2217136	महावीर रोलिंग मिल्स, 2410, फेस 4, जी आई डी सी एस्टेट, वनवा, अहमदाबाद	आई एम 226 : 1975	93-05-01	वापस	
75. 2338447	भारत पुलवराइजिंग मिल्स, "श्रीनिकेतन", 14-बबींस रोड, बम्बई-400 020	आई एम : 4766 : 1982	93-10-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
76. 2259152	बंगाल स्टील मेटल वर्क्स, 19 बी. बी. गांगुली स्ट्रीट, कलकत्ता-700 012	आई एम : 278 : 1968	93-07-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
77. 2259253	भारत आयल कं. (इंडिया) रजि., 169, कैलाश हिल्स, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-110065	आई एम : 493 (भाग 1) : 1981	93-10-16	लाइसेंसधारी की रुचि नहीं	

1	2	3	4	5	6
78. 2260137	सोनक वाणिज्य उद्योग प्रा. लि., 25 राखल दास अड्डे रोड, कलकत्ता-700 027	आई एम : 7406 (भाग 2):1984	93-07-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
79. 2260238	सोनक वाणिज्य उद्योग प्रा. लि., 25 राखल दास अड्डे रोड, कलकत्ता-700 027	आई एम : 7406 (भाग 1):1984	93-07-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
80. 2260339	यूनाइटेड जूट बैग्स, ओल्ड गुड्डम गेड, बिलासपुर (म.प्र.)-495 004	आई एम : 12154 1987	93-07-16	लाइसेंसधारी की रुचि नहीं	
81. 2265046	के. बी. केसीकल्स, प्लाट नं. 32, सेक्टर 8, लेन बी, समीप वाटर ईक, वशही, न्यू बम्बई 400 703	आई एम : 4989: (भाग 3):1985	93-08-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
82. 2265955	आर एच एल प्रोफिल्स लि., ई-12, इंड एरिया, तालकटोरा, लखनऊ-5	आई एम : 133: 1975	93-08-01	लाइसेंसधारी की रुचि नहीं	
83. 2270544	आत्मा स्टील लि., सी-138-142 इंड एरिया,-1 बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद	आई एम : 513: 1986	93-08-16	लाइसेंसधारी की रुचि नहीं	
84. 2773752	राजागम स्टील इंडस्ट्रीज, 4 ओल्ड मोटर स्टैंड, भंडारा रोड, ईटवाडी, नागपुर-440 008	आई एम : 1786: 1985	93-09-01	मृदांकन शुल्क का भुगतान नहीं किया	
85. 2276657	शाह इंडस्ट्रीज, बिधान संघ इंड. एस्टेट नं. 5, गाना नं. 9 बमई (ई), जिला ठाणे-401 202	आई एम : 3854: 1988	93-09-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
86. 2288866	जे. के. वनस्पति उद्योग प्रा. लि., डावर रोड, धोरपुर, लघियाणा (पंजाब)	आई एम : 10633: 1986	93-10-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
87. 2383860	डी आर एस स्टील इंडस्ट्रीज प्रा. लि., आनलीकारा बिल्डिंग, प्रथम तल, सर पी एम रोड, बम्बई-400 001	आई एम : 2062: 1984	93-07-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
88. 2389468	प्रेसमेन इंजी. वर्क्स, 51 ए मे जेड, इंड एस्टेट, प्रेसमेन रोड, लवर पारेल, बम्बई-400 013	आई एम : 7538: 1975	93-08-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
89. 2390756	नार्थ ईस्टर्न केबल्स एण्ड कंडक्टर्स प्रा. लि. एफ-44, इंडस्ट्रियल एरिया, सिकर (राजस्थान) 332 001	आई एम : 398 (भाग 1):	93-08-01	लाइसेंसधारी की रुचि नहीं	
90. 2396667	राज ब्रुकेट फैक्टरी, गोदबंदर रोड, गोदबंदर गांव, पो. प्रा. मीरा, जिला ठाणे	आई एम : 1783 (भाग 2):1983	93-09-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	

1	2	3	4	5	6
91.	2400228	डी सी एम श्रीराम इंडस्ट्रीज लि., (यूनिट : हिन्डन रीवर मिल्स), कंचनजंगा विल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली	आई एस : 7085- 1986	93-09-16	लाइसेंसधारा की रूचि नहीं
92.	2400329	डी सी एम श्रीराम इंड. लि., (यूनिट : हिन्डन रीवर मिल्स), कंचनजंगा विल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली	आई एस : 9517- 1986	93-09-16	लाइसेंसधारा की रूचि नहीं
93.	2401432	ट्रारक्स इस्पात उद्योग, एफ-8, एम. आई. डी. सी. हिंगना रोड, नागपुर-440066	आई एस : 1786- 1985	93-09-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
94.	2401937	सिंह इलेक्ट्रो स्टील लि., डी. पी. टी. प्लॉट नं. 52, विक्टोरिया ओवरब्रिज रोड, मजगांव, बम्बई-10	आई एस : 2830- 1975	93-10-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
95.	2403133	मराठवाड़ा केमिकल्स इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि., एस नं. 43/2 सतारा रोड, उसमानपुर, औरंगाबाद	आई एस : 8249- 1986	93-09-16	लाइसेंसधारा की रूचि नहीं
96.	2406543	सोलर केमिकल्स 15, अमृत केशव नायक मार्ग, तीसरी मंजिल, समीप न्यू इम्पियर सिनेमा फोर्ट, बम्बई-400 001	आई एस : 6444- 1979	93-10-01	कार्य सुलोपप्रद नहीं
97.	7008657	इस्पात प्रोफील्स इंडिया लि., महेन्द्रा चेम्बरस, 4, धोले पाटिल रोड, पुणे-411 001	आई एस : 226- 1975	93-05-01	वापस

[के. प्र. वि. : 13 : 14]
पी. एस. दास, अपर महानिदेशक

New Delhi, the 17th October, 1994

S.O.: . . 3196:—In pursuance of Sub-regulation (6) of Regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, it is, hereby notified that the Certification Marks Licences, details of which are mentioned in the following Schedule, have expired :

THE SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Name of the licensee	Number of the relevant Indian Standard	Date of expiry	Reason for expiry
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	0043018	The Indian Iron & Steel Co. Ltd., 'IISCO House' 50, Chowringhee Road, Calcutta-700071.	IS 226 : 1975	93-10-01	IS Withdrawn
2.	0129836	Modi Steels, Modi Nagar, Distt. Ghaziabad 201 204.	IS 280 : 1978	93-07-16	Party not interested
3.	0798653	MHI Cables and Conductors Ltd., Exhibition Road, Patna 800 001	IS 398 (Part 2) : 1976	93-06-16	Application not received

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4	0209733	Unique Industries 10, Ambica Co-op Housing Society Perlad Road, P.O. Box No. 54, NADIAD 387 001	IS 398 (Part 1) : 1976	93-05-01	Party not interested
5	0371338	Vaid Steels Indl. Area AIS Bagh, Lucknow 226004	IS 6915 : 1978	93-08-16	Application not received
6	0428240	K.R. Steel Union Ltd., "Everest House", 10th Floor, 46C, Chowringhee Road, Calcutta-700071	IS 6914 : 1978	93-10-01	Party not interested
7	0428341	K.R. Steel Union Ltd., "Everest House", 10th Floor, 46C, Chowringhee Road, Calcutta 700 071	IS 6915 : 1978	93-10-01	Party not interested
8	0655756	Beekay Pesticides Pvt. Ltd., 75, Mody Street, Post Box 553 Bombay 400 001	IS 2567 : 1978	93-07-16	Unsatisfactory performance
9	0699271	Parekh Cables & Conductors 22, Kalpana Society Race Course, Baroda 390007	IS 398 (Part 1) : 1976	93-05-16	Application not received
10	0813243	Synpro Industries 50-51, 60-61, Industrial Estate, Pologround, Indore 452 003.	IS 2933 : 1975	93-09-16	Party not interested
11	0898671	Kaysons Cable Industries "Kayson House" Hind-Saurashtra Indl. Estate, Andheri-Kurla Road, Mrol Naka, Bombay 400059	IS 694 : 1977	93-09-01	Unsatisfactory Performance
12	0893772	Kaysons Cable Industries "Kayson House" Hind Saurashtra Indl. Estate, Andheri-Kurla Road, Mrol Naka, Bombay 400059	IS 1554 (Part 1) : 1988	93-09-01	Unsatisfactory performance
13	0954160	Tradescos (India) Rubber Works, 170, Gujarat Vepari Mahamandal Audhagic Vasahar, Odhar, Ahmedabad 382 410 (Guj.)	IS 1370 : 1976	93-04-01	Application not received
14	1043730	MHI Cables and Conductors Ltd., Exhibition Road, Patna 800 001	IS 398 (Part 1) : 1976	93-06-16	Application not received
15	1111014	Procter & Gamble India Ltd., Telecican House, Dr. E. Moses Road, Bombay 400 011	IS 3134 : 1965	93-09-01	Application not received
16	1115931	Special Machines Bye-Pass, Kunjpura Road, Karwal 132 001	IS 814 (Part 1) : 19	93-10-01	Application not received
17	1212929	Kanchenjunga Ladakhi Inds. Pvt. Ltd., Ladakhi Mansions, Balluwakhani Gangtok 737 101	IS 398 (Part 2) : 1976	93-07-16	Application not received
18	1213830	Industrial Products Plot No. 4, Industrial Development Colony, Kunjpura Road, Karnal-132 001	IS 814 (Part 1) : 19	93-10-01	Application not received

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	1281241	MP State Agro Industries Development Corporation Ltd., 3rd Floor, Panchanan, Malviya Nagar, Bhopal 462 003	IS 7122 : 1984	93/10/01	Party not interested
20	1332232	Vijay Paint Inds., Daulat Ganj, Gwalior 474 001	IS 427 : 1965	93-10-16	Party not interested
21	1342336	Kotecha Brothers, V.D. Bardanwala Road, Jamnagar 361 001	IS 10325 : 1989	93-10-01	Application not received
22	1355042	Kusum Ispat and Wire Products Pvt. Ltd., Plot E-37 MIDC Industrial Area, Chikalthane Aurangabad 431210	IS 6003 : 1983	93-06-16	Application not received
23	1390347	Ambica Re-rolling Mills, Saijpur Bogha, Near G.D. High School, Ahmedabad 382345	IS 226 : 1975	93-05-01	Is Withdrawn
24	1413030	Swati Enterprise, Aji Industrial Estate, Rajkot 360 003	IS 10001 : 1981	93-08-01	Party not interested
25	1426140	Jay Nit Engineering, G-100, Laxmi Woolen Mills Compound Shakti Mill Lane, Mahalaxmi, Bombay 400011.	IS 934 : 1989	93-08-01	Unsatisfactory Performance
26	1432438	Mukund Iron & Steel Works Ltd., Lal Bahadur Shastri Marg, Kurla, Bombay 400070	IS 1786 : 1985	93-07-16	Application not received
27	1439755	Amar Spun Pipe Products Chauri Chaura, Gorakhpur	IS 458 : 1988	93-08-16	Unsatisfactory Performance
28	1442744	Malhotra Steel Inds. Gujarat Pvt. Ltd., Plot No. 105, Village Temghar, Kalyan Bhiwandi Road, Kalyan, Distt. Thane 421302.	IS 2062 : 1984	93-08-16	Application not received
29	1463045	Jayant Extraction Inds. Ltd., Bedeshwar, Jamnagar 361 002	IS 10633 : 1986	93-10-01	Application not received
30	1523340	Bharat Pulverising Mills "Shriniketan" 14, Queens Road, Bombay 400 020	IS 8708 : 1978	93-10-16	Application not received
31	1535448	Jayant Extraction -Inds. Ltd., Bedeshwar, Jamnagar 361 002	IS 10325 : 1989	93-03-16	Application not received
32	1538454	Veenars Engineering Pvt. Ltd., Plot B-31, MIDC Indl. Area, Ghughus Road, Chandrapur (Mah.)	IS 226 : 1975	93-05-01	Is withdrawn
33	1553955	Synpro Industries, 50-51, 60-61, Industrial Estate, Pologround, Indore 452 003.	IS 341 : 1973	93-09-16	Party not interested
34	1559563	Eagle Steels, 10, Hansraj Damodar Trust Bldg., 42, Kennedy Bridge, Bombay 400 004.	IS 1977 : 1975	93-09-16	Application not received

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
35	1562451	Gee Kay Consumer Products (P) Ltd., F-90/1, Okhla Indl. Area, Phase - I 1, New Delhi	IS 10840 : 1986	93-05-16	Party not interested
36	1608752	Universal Corporation 7, Udyog Nagar, Gali No. 104, 1st Floor, S.V. Road, Goregaon (W), Bombay	IS 10840 : 1986	93-09-16	Application not received
37	1687370	Perfect Sanitary Pipes Industrial Area, Bharatpur	IS 651 : 1980	93-05-16	Party not interested
38	1703544	Dinesh Cement Udyog (P) Ltd., Khokhi Road, Bhatapur Distt. Raipur	IS 269 : 1989	93-10-01	Party not interested
39	1709960	Dr. Sabharwal Mfg. Lab Ltd. Plot No. 9, G.T. Road, Bhawanipur, P.O. Mandhare, Kanpur	IS 4717 : 1980	93-08-01	Application not received
40	1711846	Kures (India) Ltd., No. 7, Canal Street, Calcutta 700 014	IS 4174 : 1977	93-07-16	Party not interested
41	1720948	Bajerla Industries, Bodhak Road, Khambhat 388620	IS 2208 : 1962	93-08-16	Unsatisfactory Performance
42	1723550	Parag Industries, 54, 58, M.A. Road, Rangoala Compound Jecab Circle, Bombay	IS 8808 : 1986	93-08-16	Application not received
43	1728358	Flexo Foam Pvt. Ltd., Pooth, Ka an, Khasra No. 106/37 Delhi 110 041	IS 1741 : 1960	93-09-01	Party not interested
44	1740146	Kanoria Steels (Prop : Aditiya Mills Ltd.) Stadium House, 2nd Block, Veer Nariman Road, Bombay 400020	IS 2830 : 1975	93-10-01	Application not received
45	1817559	Manisha Rubber Enterprises 50, Unique Industrial Estate, Rajendra Prasad Road, Opp. Jawahar Cinema Mulund (W) Bombay 400080	IS 5424 : 1969	93-05-01	Party not interested
46	1818561	Rajesh Re-Rollers (P) Ltd., 535/B, Urala Indl. Complex, Raipur	IS 1786 : 1985	93-05-01	Party not interested
47	1821146	Manish Transmission Products Private Limited, Zodiac Compound Block No. 7, Village Duniya, P.O. Halol 50	IS 398 (Part 1) : 1976	93-05-16	Application not received
48	1841152	Rita Steel Industries 251, Small Factory Area, Ragadganj, Nagpur 440008	IS 226 : 1975	93-05-01	Is Withdrawn
49	1871161	Chanderkar Biscuit Company Amir Bang, Church Road, Medha, Malvan 416 606	IS 1011 : 1981	93-09-01	Unsatisfactory Performance
50	1909059	Maharashtra Steel Rolling & Engineering Works, Plot 10, New Darukhna Mazagaon, Bombay 400010	IS 226 : 1975	93-05-01	Is Withdrawn

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
51	1986986	Kusum Ispat and Wire Products Pvt. Ltd., Plot E-37, MIDC Industrial Area, Chikal thana, Aurangabad 431210	IS 432 (Part 2) : 1982	93-06-16	Application not received
52	1988990	Fort William Co. Ltd., 10, Clive Row, Third Floor Calcutta 700001.	IS 3751 : 1966	93-06-16	Application not received
53	1990977	Pratap Steel Rolling Mills (1935) Ltd., 311/312 Chetak Centre, 12/2, R.N. T. Marg, Indore 452001.	IS 8051 : 1976	93-06-16	Party not interested
54	1993276	Krishi Rasayan, Large Industrial Estate, R.K. Ashram, Muzaffarpur 843 116	IS 8074 : 1983	92-07-01	Application not received
55	1998286	Amar Cables, A-28 Naraina Indl. Area, Phase I New Delhi 110028	IS 1554 (Part 1) : 1988	93-07-16	Application not received
56	2004725	Bitu Bag Manufacturers 144/145 J.N. Mukerjee Road, Ghusuri, Howrah	IS 7406 (Part 1) : 1984	93-08-01	Application not received
57	2004826	Bitu Bag Manufacturers 144/145, J.N. Mukerjee Road, Ghusuri, Howrah	IS 7406 (Part 2) : 1984	93-08-01	Application not received
58	2015124	Colts Cements (P) Ltd., Haldwani, Southern Avenue, Manarani Bagh, New Delhi 110065	IS 269 : 1989	93-08-16	Application not received
59	2032831	Cheviot Co. Ltd., 9, Brabourne Road, Calcutta 700 001	IS 12154 : 1987	93-10-01	Party not interested
60	2101521	MHI Cables and Conductors Ltd., Exhibition Road, Patna 800 001	IS 398 (Part 5) : 1976	93-04-16	Application not received
61	2104931	Maharashtra Cable Industries Shed No. 1, 49/2, Indl. Area, Kamal Manufacturing Compound Main Road, Ulhasnagar 421004	IS 694 : 1977	93-04-16	Unsatisfactory Performance
62	2116938	Madhushree Traders 21 Residency Road, Jodhpur	IS 7231 : 1984	93-05-16	Party not interested
63	2120222	Gandhar Wire & Cables Pvt. Ltd., Shrichand Abbani Street, Naya Bas Beawar (Rajasthan) 305901.	IS 398 (Part 1) : 1976	93-06-01	Party not interested
64	2121729	Bharat Pulverising Mills "Shriniketan" 14, Queens Road, Bombay 400 020	IS 4323 : 1980	93-10-16	Application not received
65	2121830	Krishi Rasayan Large Industrial Estate, R.K. Ashram Muzaffarpur 843 116	IS 8028 : 1987	93-06-01	Application not received
66	2123733	Sylvex Cables Co. (P) Ltd., Saki Vihar Road, Bombay 400072	IS 1554 (Part 1) : 1988	93-06-16	Application not received
67	2123985	Sylvex Cables Co. (P) Ltd., Saki Vihar Road, Bombay 400072	IS 694 : 1977	93-06-16	Application not Received
68	2129947	Singh & Singh 100F Indl. Estate, Govindpuri, Bhopal 462023	IS 1333 : 1978	93-07-01	Party not interested

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69	2136742	Shilpa Re-Rollers Pvt. Ltd., 2, Surana Layout Vijay Nagar, Nagpur	IS 226 : 1975	93-05-01	Is withdrawn
70	2138140	Dhamija Indl. Corpn., S-5, Indl. Area, Site A, Byc Pass, Mathura	IS 1729 : 1979	93-08-01	Application not received
71	2141634	Rateria Laminators Pvt. Ltd., 132, Cotton Street, First Floor, Calcutta-700007	IS 7406 (Part 1) : 1984	93-08-16	Application not received
72	2197358	Jalgaon Re-rolling Industries Ltd., 18-27, Industrial Estate, Ajintha Road, Jalgaon-425001	IS 226 : 1975	93-05-01	Is withdrawn
73	2204430	Vishesh Ispat Pvt. Ltd., Near Gujarat Steel Tubes, Kaligam Ahmedabad 382470	IS 226 : 1975	93-05-01	Is withdrawn
74	2217136	Mahavir Rolling Mills 2410, Phase IV GIDC Estate Vatva, Ahmedabad	IS 226 : 1975	93-05-01	Is withdrawn
75	2238447	Bharat Pulverising Mills "Shriniketan" 14, Queens Road, Bombay 400 020	IS 4766 : 1982	93-10-16	Application not received
76	2259152	Bengal Sheet Metal Works 19 B, B.B. Ganguli Street Calcutta-700012	IS 278 : 1978	93-07-16	Application not received
77	2259253	Bharat Oil Co. (India) Regd., 169, Kailash Hills East of Kailash New Delhi 110065	IS 493 (Part 1) : 1981	93-10-16	Party not interested
78	2260137	Shaunak Vanijya Udyog Pvt. Ltd., 25, Rakhal Das Addy Road, Calcutta 700027	IS 7406 (Part 2) : 1984	93-07-16	Application not received
79	2260238	Shaunak Vanijya Udyog Pvt. Ltd., 25, Rakhal Das Addy Road, Calcutta 700027	IS 7406 (Part 1) : 1984	93-07-16	Application not received
80	2260339	United Jute Bags Old Goods Shed, Bilaspur (MP)-495004	IS 12154 : 1987	93-07-16	Party not interested
81	2265046	K.V. Chemicals Plot No. 32, Sector 8 Lane B, Near Water Tank Vashi New Bombay 400703	IS 4989 (Part 3) : 1985	93-08-01	Application not received
82	2265955	RHL Profiles Ltd., E-12, Indl. Estate, Talkatora, Lucknow-5	IS 133 : 1975	93-08-01	Party not interested
83	2270544	Atma Steels Ltd., C-138-142, Indl. Area I Bulandshahr Road, Ghaziabad	IS 513 : 1986	93-08-16	Party not interested
84	2273752	Rajaram Steel Inds., Old Motor Stand Bhandara Road, Itwari, Nagpur 440008	IS 1786 : 1985	93-09-01	Marking Fees not Paid
85	2276657	Shah Industries, Diwan Sons Indl. Estate No. 5 Gala No. 9 Vasai (E) Distt. Thane 401202	IS 3854 : 1988	93-09-01	Application not received

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
86	2288866	J.K. Vanaspati Udyog Pvt. Ltd., Daba Road, Sherpur, Ludhiana (Punjab)	IS 10633 : 1986	93-10-01	Application not received
87	2383860	DRM Steel Industries Pvt. Ltd., Onlookar Building First Floor, Sir. P.M. Road, Bombay 400001	IS 2062 : 1984	93-07-16	Application not received
88	2389468	Precision Engg. Works 51, A to Z Indl. Estate, Ferguson Road, Lower Parel, Bombay 400 013	IS 7538 : 1975	93-08-01	Application not received
89	2390756	North Eastern Cables & Conductors (P) Ltd., F-44, Indl. Area, Sikar (Raj.) 332001	IS 398 (Part 1) : 1976	93-08-01	Party not interested
90	2396667	Raj Bucket Factory Ghodbunder Road, Ghodbunder Village P.O. Mira, Distt. Thane 401104	IS 1783 (Part 2) : 1983	93-09-01	Application not received
91	2400228	DCM Shri Ram Inds. Ltd., (Unit : Hindon River Mills) Kanchenjunga Building Barakhamba Road, New Delhi	IS 7085 : 1986	93-09-16	Party not interested
92	2400329	DCM Shri Ram Inds. Ltd. (Unit : Hindon River Mills) Kanchenjunga Building Barakhamba Road, New Delhi	IS 9517 : 1986	93-09-16	Party not interested
93	2401432	Dwarbas Ispat Udyog F-8, MIDC Hingna Road, Nagpur 440016	IS 1786 : 1985	93-09-16	Application not received
94	2401937	Singh Electro Steel Ltd., B.P.T. Plot No. 52 Victoria Overbridge Road, Mazagaon, Bombay 10	IS 2830 : 1975	93/10/01	Application not received
95	2403133	Marathwada Chemical Industries (P) Ltd., S No. 43*2, Satara Road, Usmanpur, Oranabad	IS 8249 : 1976	93-09-16	Party not interested
96	2406543	Solar Chemicals 15 Amrit Keshav Nayak Marg 3rd Floor Near New Empire Cinema, Fort Bombay 400001	IS 6444 : 1979	93-10-01	Unsatisfactory performance
97	7008657	Ispat Profiles India Ltd., Mahendra Chambers 4, Dhole Patil Road, Pune 411001	IS 226 : 1975	93-05-01	IS withdrawn

[No. CMD / 13 : 14]

P.S. DAS, Additional Director General

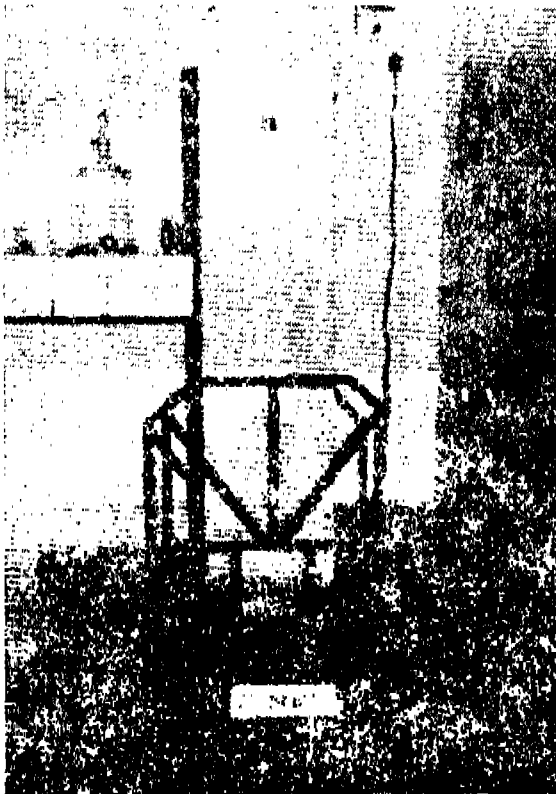
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1994

का.मा. 3199.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित

प्रतिमान बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (प्रतिमानों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान लम्बी अवधि तक अविरत उपयोग के संबंध में ठीक बना रहेगा और परिवर्तित दशाओं में सही सेवा देगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स फाइनेक्स डिजिटल सिस्टम्स, 11, हर्षद चैम्बर्स, ओटाव, अहमदाबाद-382415 द्वारा विनिर्मित टाइप सं. एफ पी एस-100 और "फाइनेक्स" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक, अस्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/94/25 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन से इस पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी मित्ता के अनुसार और उन्हीं सामग्री से, जिनसे अनुमोदन प्रतिमान का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित 50 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 500 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले उसी सीरीज के समरूप मेक, शुद्धता और कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी आएंगे।



(आकृति)

प्रतिमान (आकृति देखिए) एक मध्यम शुद्धता (शुद्धता वर्ग 3) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 100 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 2 किलोग्राम है। मत्स्यापन मापमान अंतर (ई) 100 ग्राम है। इसमें एक ऐसी टैरे युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारित टैरे प्रभाव शत-प्रतिशत है। आधार और प्लेटफार्म मृदु इस्पात के हैं। भार ग्राही वर्गाकार आकार का है जिसकी पार्श्व लंबाई

500 मिलीमीटर है। 12 मिलीमीटर सप्रतीक आकार का सात खंडीय निर्वर्तित प्रदीप्तिशील प्रदर्शक तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती द्वारा विद्युत प्रदाय पर चलाया जाता है।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम.-21(29) 92]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

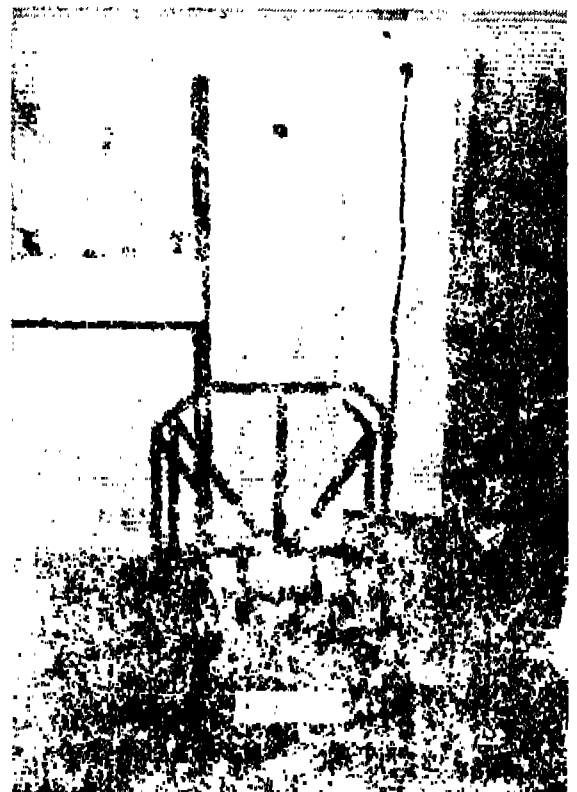
MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS
AND PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 28th October, 1994

S.O. 3199.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standard of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of Model of self-indicating non-automatic weighing instrument of type FPS-100 and with brand name 'FINEX' (herein after referred to as the Model) manufactured by M/s. Finex Digital Systems, 11, Harshad Chambers, Odhav, Ahmedabad-382415, and which is assigned the approval mark IND/09/94/25;

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 50 kilogram, 200 kilogram, 300 kilogram, 500 kilogram and 1000 kilogram manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same material with which, the approved Model has been manufactured.



The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 100 kilogram and minimum capacity of 2 kilogram. The verification scale interval (e) is 100 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The base and the platform are of mild steel. The load receptor is of square shape with side of length 500 millimetre. The seven segment vacuum fluorescent display of character size 12 millimetre indicate the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(29)/92]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3200 :—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (प्रतिमानों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबन्धों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान लम्बी अवधि तक अविरत उपयोग के संबंध में ठीक बना रहेगा और परिवर्तित दशाओं में सही सेवा देगा ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स फाइनेक्स डिजिटल सिस्टम्स, 11, हर्षद चैम्बर्स, ओटाव, ग्रहसदाबाद-382415 द्वारा विनिर्मित टाइप सं. एफ सी एस-20 और “फाइनेक्स” ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक, अस्व-चालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/94/26 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ;

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन द्वारा प्रमाणपत्र के अन्तर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त के अनुसार और उन्हीं सामग्री से, जिनसे अनुमोदित प्रतिमान का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित 10 किलोग्राम और 50 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले उसी सीरीज के तथा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम की अधिकतम

क्षमता वाले ‘एफ टी बी’ सीरीज के समरूप मेक, जुन्ता और कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी प्राप्त होंगे।



(आकृति)

प्रतिमान (आकृति देखिए) एक मध्यम शुद्धता (शुद्धता वर्ग 3) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 20 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 200 ग्राम है। स्थापन मापमान अन्तर (ई) 10 ग्राम है। इसमें एक ऐसी टैरे युक्ति है जिसके व्यक्तीकृत प्रतिधारित टैरे प्रभाव शत प्रतिशत है। आधार और भार ग्राही क्रमशः मृदु एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं। वृत्ताकार भारग्राही का व्यास 350 मिलीमीटर है। 12 मिलीमीटर संप्रतीक आकार का सात-खंडीय निर्वात प्रदीप्तिशील प्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर चलाया जाता है।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम.-21(29)/92]
राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 28th October, 1994

S.O. 3200.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standard of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of Model

of self-indicating non-automatic weighing instrument of type FCS-20 and with brand name 'FINEX' (herein after referred to as the Model) manufactured by Ms. Finex Digital Systems, 11 Harshad Chambers, Odhav, Ahmedabad-382415, and which is assigned the approval mark IND/09/94/26;

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 10 kilogram, and 50 kilogram of 'FTB' series with maximum capacity of 100 gram, 200 gram, 2 kilogram and 5 kilogram manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approval Model has been manufactured.



(Figure)

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 20 kilogram and minimum capacity of 200 gram. The verification scale interval (e) is 10 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The base and the load receptor are made up of aluminium and stainless steel respectively. The circular load receptor is of diameter 350 millimetre. The seven segment vacuum fluorescent display of character size 12 millimetre indicate the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternative current power supply.

[F. No. WM-21(29)/92]
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3201 :—भारत का राजपत्र दिनांक 5-3-94 के पृष्ठ संख्या 662, 663 व 665 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम संख्या 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1)

के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या 698, दिनांक 17-2-94, ग्राम सहनपुर, परगना व तहसील किरावली, जिला आगरा को प्रकाशित सूची के हिन्दी लिपि के स्तम्भ 5 व 6 में गाटा संख्या 208 क्षेत्रफल 0.1250 के स्थान पर गाटा संख्या 208 क्षेत्रफल 0.1280 तथा हिन्दी-अंग्रेजी दोनों में गाटा संख्या 311 के स्थान पर गाटा संख्या 424 पढ़ा जाये।

[संख्या एल-14016/22/93-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th October, 1994

S.O. 3201.—In the Gazette of India Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 698 dated 17-2-94 published on 5-3-94 at page No. 662, 663 & 665 in English version sub-section (i) of Section-3 of the Petroleum & Mineral Pipe line (Acquisition of Right of users in land) Act, 1962 (50 of 1962) of Village-Sahanpur Pargana & Tehsil-Kiroli, Distt.-Agra in column 5 & 6 be read as plot No. 208 area 0.1230 instead of plot No. 208 area 0.1250. Also in both Hindi and English version plot No. 424 instead of plot No. 311.

[No. L-14016/22/93-G.P.]
ARDHENDU SEN, Director

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3202 :—भारत का राजपत्र दिनांक 5-3-94 के भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (2) के पृष्ठ संख्या 669 व 670 पर अंग्रेजी में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम संख्या 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 17-2-1994 ग्राम मिरौली, परगना व तहसील किरावली, जिला आगरा की प्रकाशित सूची के स्तम्भ 5 व 6 में गाटा संख्या 6 क्षेत्रफल 02.400 के स्थान पर गाटा संख्या 6 क्षेत्रफल 0.2400, गाटा संख्या 43 क्षेत्रफल 0.1200 के स्थान पर गाटा संख्या 43 क्षेत्रफल 0.0120 तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में ही गाटा संख्या 76/2 क्षेत्रफल 0.56 के स्थान पर गाटा संख्या 76/2 क्षेत्रफल 0.6736 तथा गाटा संख्या 75 क्षेत्रफल 0.1200 के स्थान पर गाटा संख्या 75 क्षेत्रफल 0.0120 पढ़ा जाये।

[संख्या एल-14016/22/93-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th October, 1994

S.O. 3202.—In the Gazette of India Ministry of Petroleum & Natural Gas No. 640 dated 17-2-94 published on 5-3-94 at page 669-670 in English version Sub-section (i) of Section-3 of the Petroleum & Mineral Pipe line (Acquisition of Right of users in land) Act, 1962 (50 of 1962), of Village Sirauli, Pargana & Tehsil-Kiroli, Dist. Agra in column 5 & 6 be

read as plot No. 6 area 0-2400 instead of plot No. 6 area-02-400 plot No. 43 area 0-0120 instead of plot No. 43 area 0-01200. Also in both Hindi and English version plot No. 76/2 area 0-6736 be read instead of Plot No. 76/2 area 0-5656 and plot No. 75 area 0-0120 be read instead of Plot No. 75 area 0-1200.

[No. L-14016/22/93-GP]
ARDHENDU SEN, Director.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3203:—भारत का राजपत्र दिनांक 19-3-94 के भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (2) के पृष्ठ संख्या 925 पर अंग्रेजी में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम संख्या 1962 (1962 का 50) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना सं. का.आ. 741 दिनांक 8-3-94 ग्राम मराय अहमद, परगना व तहसील खेरागढ़, जिला आगरा की प्रकाशित सूची के स्तम्भ 5 व 6 में गाटा संख्या 137 क्षेत्रफल 0.4080 के स्थान पर गाटा संख्या 137 क्षेत्रफल 0.0480 पढ़ा जाये एवं पृष्ठ सं. 924 व 925 पर हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित सूची के स्तम्भ-5 में गाटा सं. 123 के स्थान पर 124 पढ़ा जाये।

[संख्या : एल-14016/22/93-जीपी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th October, 1994

S.O. 3203.—In the Gazette of India Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 741 dated 8-3-94 at page No. 925 Sub-section (i) of section-3 of the Petroleum & Mineral Pipe Line (Acquisition of Right of users in land) Act 1962 (50 of 1962) of Village-Sarai Ahmad, Pargana and Tehsil- Khera Garh, Distt.-Agra in column 5 & 6 be read as plot No. 137 area 0.0480 in English version and on page 924 and 925 in column 5 of both in Hindi and English version plot No. 124 be read instead of 123.

[No. L-14016/22/93-GP]
ARDHENDU SEN, Director

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3204 :—भारत का राजपत्र दिनांक 19-3-94 के पृष्ठ संख्या 926 व 927 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम संख्या 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या 742 दिनांक 8-3-94 ग्राम खाखरा, परगना व तहसील खेरागढ़ जिला आगरा की प्रकाशित सूची के स्तम्भ 5 व 6 में गाटा संख्या 2 क्षेत्रफल 0.0808 के स्थान पर गाटा संख्या 2 क्षेत्रफल 0.0708 एवं अन्त में गाटा संख्या 4 क्षेत्रफल 0.0100 बढ़ा हुआ, अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में पढ़ा जाये।

[संख्या : एल-14016/22/93-जीपी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th October, 1994

S.O. 3204.—In the Gazette of India Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 742 dated 8-3-94 published on 19-3-94 at page 926 and 927 Sub-section (i) of section-3 of the Petroleum & Mineral Pipe line (Acquisition of Right of users in land) Act 1962 (50 of 1962) village-Khaukhra, Pargana and Tehsil-Khera Garh, Distt.-Agra column 5 and 6 be read as plot No. 2 area 0.0708 instead of 0.808 and plot No. 4 area 0.0100 be added in both Hindi and English version.

[No. L-14016/22/93-G.P.]
ARDHENDU SEN, Director

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3205:—भारत का राजपत्र दिनांक 19-3-94 के पृष्ठ संख्या 904 व 905 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या 736 दिनांक 8-3-94 ग्राम बसनई खुर्द परगना व तहसील खेरागढ़ जनपद आगरा की हिन्दी व अंग्रेजी की प्रकाशित सूची के स्तम्भ -5 व 7 में चक संख्या 224 क्षेत्रफल 0.1856 के स्थान पर गाटा संख्या 284 क्षेत्रफल 0.1856 पढ़ा जाये।

[संख्या एल-14016/22/93-जीपी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th October, 1994

S.O. 3205.—In the Gazette of India Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 736 dated 8-3-94 published on 19-3-94 at page No. 904 and 905 Sub-section (i) of Section-3 of the Petroleum & Mineral Pipe line (Acquisition of Right of land) Act, 1962 (50 of 1962), of Village-Bamnai Khurd Pargana & Tehsil Khera Garh, Distt. Agra in Column 5 & 7 be read as plot No. 284 area 0.1856 instead of chak No. 224 area 0.1856 in both Hindi and English version.

[No. L-14016/22/93-G P.]
ARDHENDU SEN, Director

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3206 :—भारत का राजपत्र दिनांक 5-3-94 के पृष्ठ संख्या 667 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम संख्या 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या का. आ. सं. 639 दिनांक 17-2-94 ग्राम जाजौली परगना व तहसील किरावली, जिला आगरा की प्रकाशित सूची (हिन्दी में) के स्तम्भ 5 व 6 में गाटा संख्या 379 क्षेत्रफल 0.2260 के स्थान पर गाटा संख्या 379 क्षेत्रफल 0.2660 पढ़ा जाये।

[संख्या : एल-14016/22/93-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th October, 1994

S.O. 3205.—In the Gazette of India Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 639 dated 17-02-94 published on 05-03-94 at page No. 667 in volume-2 part-3, sub section (ii) Under Sub-section (i) of section-3 of the Petroleum & Mineral Pipe line (Acquisition of Right of users in land) Act 1962 (50 of 1962) of Village Jajauli, Pargana & Tehsil-Kirāṭī, Distt.-Agra in column 5 & 6 of Hindi version be read as plot No. 379 area 0-2660 instead of plot No. 379 area 0-2260.

[No. L-14016/22/93-G.P.]
ARDHENDU SEN, Director

अहमदी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3207 यतः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कतिपय संशोधन, जिन्हें केन्द्र सरकार अध्यापित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली वृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करना है तथा जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा-11क के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 2-4-94 के नोटिस संख्या एफ-13 (2)/93-एम.पी. द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें आपत्तियों/सुझाव उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किए गए थे।

और यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई आपत्तियां सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यान-पूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली वृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है।

अतः अब केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त वृहद योजना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

“योजना डिवाजन “एफ” (दक्षिण दिल्ली-1) के पूर्वोत्तर में मलजल शोधन संयंत्र ओखला, पश्चिम में 45 मीटर चौड़ा मथुरा रोड और दक्षिण में डिस्ट्रिक्ट पार्क से घिरे लगभग 6 हेक्टर (15 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को “उपयोगिता” (मलजल शोधन) से सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं (अस्पताल) में परिवर्तित किया जाता है।

[म. के-13011/15/92-डी.डी. 1वीं]

एन.सी. सागर, जवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

New Delhi, the 19th October, 1994

S.O. 3207.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi/ Zonal Development Plan regarding the area mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 13(2)93-MP dated 2-4-94 inviting objections/suggestions in accordance with the

provisions of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1957 within thirty days from the date of the said notice;

Whereas no objections/suggestions were received with regard to the proposed modifications;

And, whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi w.e.f. the date of publication of this notification in the Gazette of India.

MODIFICATION :

“The land use of an area, measuring about 6.00 h.a. (15 acres) falling in the planning division ‘F’ South Delhi-D bounded by Sewage Treatment Plant, Okhla in the East and North, 45 mts. wide Mathura Road in the West and District Park in the South is changed from ‘Utility’ (Sewerage Treatment Plant) to ‘Public and semi public facilities’ (Hospital).”

[No. K-13011/15/92-DDIB]

S. C. SAGAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3208 :—यतः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अध्यापित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली वृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 6/11/93 के नोटिस संख्या एफ 3(52)/91-एम पी द्वारा प्रकाशित किये गये थे, जिससे जनता से आपत्तियां/सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किए गए थे;

यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में जनता से एक आपत्ति/सुझाव मिला है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है;

और यतः मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली वृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त वृहद योजना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :—

(1) खामपुर गांव की राजस्व सम्पदा में, पूर्व में मौजूदा नाला सं. 6 से, पश्चिम में जी. टी. करनाल रोड से और उत्तर तथा दक्षिण में हरित पट्टी से घिरे 10 हेक्टर (25 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को “ग्रामीण उपयोग” से “उपयोगिता” (मलजल शोधन संयंत्र) में परिवर्तित किया जाता है।”

(2) बड़पुर गांव और बीजापुर गांव के निकट, दक्षिण में ब्याना एक्सेप से, उत्तर में हरित पट्टी से, पश्चिम में जी. टी. करनाल रोड से और पूर्व में नहरी भेजर

डिस्ट्रीब्यूटरी से बिरे लगभग 40 हेक्टर (100 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "ग्रामीण उपयोग" से "उपयोगिता" (मलजल शोधन संयंत्र) में परि वर्तित किया जाता है।"

[सं. के.-13011/20/93-डी. डी. 1 बी]

एस. सी. सागर, अवर सचिव

and green belt and Nahari major distributory in the East, is changed from 'rural use' to 'utility' (Sewage Treatment Plant)".

[No. K-13011/20/93-DDIB]

S. C. SAGAR, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

New Delhi, the 20th October, 1994

S.O. 3208.—Whereas the following modifications, which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 3(52)/91-MP dated 16-11-93 inviting objections/suggestions from the public, in accordance with the provisions of section 11-A of the Delhi Development Act, 1957, within thirty days from the date of the said notice;

Whereas, one objections/suggestions was received from the public with regard to the said proposed modifications, which has been considered by the Authority;

And, whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

- (i) "The land use of an area, measuring 10 h.a. (25 acres), bounded by existing drain No. 6 in the East, G. T. Karnal Road in the West and green belt in the North and South, in the revenue estate of village Khampur is changed from 'rural use' to 'utility' (Sewage Treatment Plant)".
- (ii) "The land use of an area, measuring 40 h.a. (100 acres), near Village Budhpur and Village Bijapur, bounded by Bawana escape in the South, green belt in the North, G. T. Karnal Road in the West

-शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1994

का. आ. 3209:—इस निदेशालय के दिनांक 28-1-92 के समसंख्यक पत्र के तहत जारी अधिभूचना, जिसके तहत केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की डाक विभाग में सम्पदा अधिकारियों के बतौर कार्य करने हेतु नियुक्ति को भारत के राजपत्र के भाग II-3(ii) दिनांक 11-9-93 में प्रकाशित किया गया था, में पृष्ठ सं. 5 कम सं 18 पर इलाहाबाद क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) के सामने निम्नलिखित परिवर्तन किया जाए।

क्र. सं.	सकिल का नाम	अधिकारियों का पदनाम	क्षेत्राधिकार
18.	उत्तर प्रदेश	सहायक महानिदेशक डाक सेवाएं (स्था. एवं जांच) इलाहाबाद क्षेत्र	इलाहाबाद क्षेत्र

[सं. 2-119/90-भवन]

दिनांक 28 अक्टूबर, 1994, सहायक महानिदेशक (बी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th October, 1994

S.O. 3209:—In the notification issued under the Directorate Office of even No. dated 28-1-92 in respect of the Central Govt. Gazetted Officers appointed to act as Estate Officers in the Department of Posts published in Gazette of India in Part-II-3(i) dated 11-9-93. The following changes may be made against sl. no. 18 page 5 against Allahabad Region (Uttar Pradesh).

Sl. No.	Name of Circle	Designation of the Officers	Territorial Jurisdiction
18.	Uttar Pradesh	Asstt. Director Postal Services (Estt. & Inv.) Allahabad Region.	Allahabad Region

[No. 2-119/90-Bldg.]

D. SARKAR, Asstt. Director General (B)

(सदन शाखा)

शुद्धि पत्र-II

नई दिल्ली, 6 जून, 1994

का.भा. 3210 :- डाक विभाग में सम्पदा अधिकारी के बनने कार्य करने के लिए नियुक्त केन्द्रीय सरकार राजपत्रित अधिकाधिकारियों के संबंध में निदेशालय के दिनांक 28-1-92 के संसर्गक पत्र के तहत जारी अधिनियम में, जो भारत के राजपत्र के भाग II-3(ii) में दिनांक 11-9-93 को प्रकाशित किया गया था, क्रम सं. 2, 12 और 19 अर्थात् असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सर्किल के समक्ष निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएं :-

क्रम सं.	सर्किल का नाम	अधिकारी का पदनाम	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार
2.	असम सर्किल	सहायक पोस्टमास्टर जनरल (भवन), मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, असम सर्किल, गुवाहाटी	असम सर्किल
12.	महाराष्ट्र सर्किल	सहायक पोस्टमास्टर जनरल (डाक) मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, बम्बई	बम्बई रीजन
19.	पश्चिम बंगाल सर्किल	सहायक पोस्टमास्टर जनरल (पी), मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्किल, कलकत्ता-700012	कलकत्ता मिडी क्षेत्र में स्थित परिमर
2	"	सहायक निदेशक, डाक सेवाएं (ई), मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्किल, कलकत्ता-700012	कलकत्ता मिडी क्षेत्र में स्थित परिमर की अपेक्षा पोस्टमास्टर जनरल (कलकत्ता) और मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के प्रशासनिक नियंत्रण में पड़ने वाले इकाइयों। युनिटों में स्थित परिमर

[मं. 2-119/90-भवन]

प्रिन्सिपल सचिव, सहायक महानिदेशक (बं.)

(Building Branch)

CORRIGENDUM-II

New Delhi, the 6th June, 1994

S.O. 3210 :- In the notification issued under the Directorate office of even no. dated 28-1-92 in respect of the Central Govt. gazetted Officers appointed to act as Estate Officers in the Department of Posts published in gazette of India in part. II-3(ii) dt. 11-9-93. The following changes may be made against Sl. No. 2, 12, & 19 i.e. Assam, Maharashtra Circle & West Bengal Circle.

Sl. No.	Name of Circle	Designation of the Officers	Territorial jurisdiction
2.	Assam Circle	Asstt. Postmaster General (Bldg.) O/o Chief Postmaster General, Assam Circle Guwahati	Assam Circle
12.	Maharashtra Circle	Asstt. Postmaster Gen. (Mails) O/o the Chief Postmaster Gen. Bombay.	Bombay Region
19.	West Bengal Circle	Asstt. Postmaster Gen. (P) O/o the Chief Postmaster Gen. W.B. Circle Calcutta-700012	Premises situated in Cal. City area
2.	"	Asstt. Director of Postal Services (E) O/o the Chief Postmaster Gen. W.B. Circle, Calcutta 700012	Premises situated in Dns/Units under the administrative control of PMG (Cal) and C.P.M.G. than the premises situated in Calcutta City area.

[No. 2-119/90-BI g.]

D. SARKAR, Asstt. Director General (B)

सुद्धिपत्र-III

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1994

का.पा. 3211:—आक विभाग में सारा अधिकाधिकारों के रूप में कार्य करने के लिए केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में निदेशालय की सयसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-1-92 को भारत के राजपत्र के भाग-II-3(ii) में 11-9-93 का प्रकाशित हुई थी, उसमें क्रम सं. 4 दिल्ली सर्किल के मामले निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएं।

क्रम सं.	सर्किल का नाम	अधिकारियों का पदनाम	अन्तर्गत
4	दिल्ली सर्किल	सहायक पोस्टमास्टर जनरल (सी), मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय दिल्ली सर्किल, दिल्ली	दिल्ली सर्किल

[गं. 2-119/90-सं. 19]

[दिनांक: 5 सितम्बर, 1994]

CORRIGENDUM-III

New Delhi, the 5th September, 1994

S.O. 3211 :—In the notification issued under the Directorate office of even No. dated 28-1-92 in respect of the Central Govt. Gazetted Officers appointed to act as Estate Officers in the Department of Posts published in Gazette of India in part-II—3 (i) dt. 11-9-93. The following changes may be made against Sl. No. 4 Delhi Circle.

Sl. No.	Name of Circle	Designation of the Officers	Territorial jurisdiction
4.	Delhi Circle	Asstt. Postmaster General (C), O/o the Chief Postmaster General, Delhi Circle, Delhi.	Delhi Circle

[No. 2-119/90-Bldg.]

D. SARKAR, Asstt. Director General (B)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली 13 अक्टूबर, 1994

का. आ. 3212—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ बड़ोदा के प्रबंधन के संबंध में निदेशालय की सयसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-1-92 को भारत के राजपत्र के भाग-II-3(ii) में 11-9-93 का प्रकाशित हुई थी, उसमें क्रम सं. 4 दिल्ली सर्किल के मामले निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएं।

[सं. 12012/304/87-डी. II (ए)/आई. ए. आर. भा. 2]

का. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 13th October, 1994

S.O. 3212.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, 2, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 13-10-1994.

[No. L-12012/304/87-D.II-A/IR (B II)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/9 of 1988

Employers in relation to the management of Bank of Baroda

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Mr. L. I. D'Souza, Representative.

For the Workmen—Mr. A. P. Kulkarni, Advocate.

INDUSTRY : Banking

STATE : Maharashtra

Bombay, the 6th September, 1994

AWARD

The reference is sent to this Tribunal for adjudication by the Government of India Ministry of Labour, New Delhi by its letter No. L-12012/304-87-D.II (A) dated 3-2-88. The reference is in the following terms :

"Whether the action of the management of Bank of Baroda in denying Cuckoo allowance of Special Assistant from 1-1-86 to Shri Nalin R. Pathe, Air-conditioning Plant Operator, consequent upon the retirement of Shri Percy Neroy, Special Assistant

on 31-12-85 and non filling of this post thereafter is justified? If not, to what relief Shri Pethe is entitled from 1-1-86?"

2. After the receipt of the reference, the parties were duly served with the notices. The workman Shri Nitin R. Pethe through the Bank of Baroda Employees Trade Union Congress had filed his statement of claim.

3. In nutshell the claim is that the Workman Pethe was employed in Bank of Baroda (hereinafter referred to as the Bank) on 6-5-1983 applied to the Bank in response to the Advertisement appeared in the local newspaper i.e. Loksaatta and Maharashtra Times dated 2-2-1982. The advertisement was for the post of Air Conditioning Mechanic-cum-Operator. The Workman concerned has a technical qualification i.e. H.S.C. and Diploma in Air-Conditioning. On 5th May, 1983 an appointment letter was issued to the Workman. In the appointment letter of the Workman his technical duties are specifically mentioned. From the appointment letter it is very clear that the Workman's appointment was on a technical post by the Bank.

4. One Mr. Percy Neroy, retired on 31-12-84. Since 1-1-85, the Workman is performing additional duties attracting Special allowance. Mr. Percy Neroy who retired was working as a Special Assistant. After his retirement, all his duties are performed by the Workman. Mr. Neroy, Special Assistant (Maintenance Department) was performing the following duties.

- (i) Supervising all Air-Conditioners, electric fittings and fixtures,
- (ii) Preparing of estimates of Air conditioning machines and electrical wiring, and
- (iii) Bill scrutinisation.

5. The workman claims the special allowance at the rate of Rs. 450 per month from 1-1-1985 as he is doing all those works which were done by Mr. Neroy. On July 1, 1986 the workman addressed a letter to the Bank calling upon it to pay the special allowance. But it did not. His claim was passed on the basis of the Bipartite settlement. The workman had done some additional duties along with his own duties for the special allowance from 1-1-1985.

6. The Bank did not fill up the post of Special Assistant after the retirement of Mr. Neroy which is wrong. The workman is supervising the entire work of the Maintenance section. He sends Mechanics and Electricians to the respective sections and departments according to the notices of the various sections and departments of the Bank. It is a practice of the Bank to pay Special allowance to the employees who work on a higher post in addition to their own duties. As the workman was doing the work of a higher post requiring extra skill, he is entitled to the Special allowance. The Bank had given such a special allowance to one Shri B. D. Khuble, Shri P. G. Dalvi and Shri V. V. Tribhuvan on the earlier occasions. Non payment of the special allowance to the workman is discriminating. It is averred that the principles of equal pay for equal work demands that the workman performing the same duties (duties of the Special Assistant) should be paid the allowance. The workman claimed that he may be awarded the dues of a special allowance along with 18% interest p.a. on it from 1-1-1985.

7. The management i.e. the Bank resisted the claim by the written statement at Exh. M/3. It is averred that the workman was never instructed or authorised to do any work of Shri Neroy, who was working as a special assistant, attracting the special pay on his retirement. It is pleaded that no additional duties to Shri Nitin were done by the workman, attracting the special allowance. It is averred that whatever work is done by the worker is as per his appointment letter. It is submitted that whenever a junior person is asked to officiate in a higher post or higher position, written instructions are given to him by his superior Officer and then naturally he will be allowed to carry the duty of the Special Assistant for which he will be entitled to special allowance as applicable in the bipartite settlement. The workman was never authorised to do such a work. Hence he is not entitled to a special pay.

8. It is averred that filling of the vacancy is essentially the function of the management and the workers cannot claim it as of a right. It is submitted that the workman never worked in a superior capacity. He was never given any additional duties.

9. My Learned Predecessor framed issues at Exh. 4. The issues and my findings thereon are as follows:

ISSUES

FINDINGS

1. Whether the Bank of Baroda Employees: In the Trade Union Congress proves that the negative Bank management had instructed and authorised the workman Shri Pethe to perform the duties of a Special Assistant performed by Shri Percy Neroy, retired Special Assistant, after his retirement from 1-1-1985?
 2. If so, whether the said Trade Union Congress further proves that the said workman performed the additional duties attracting Special allowance?
 3. Whether the action of the management of Bank of Baroda in denying officiating allowance of Special Assistant from 1-1-1985 to Shri Nitin R. Pethe, Air Conditioning Plant Operator, consent upon the retirement of Shri Percy Neroy, Special Assistant on 31-12-84 and non filling of this post thereafter is justified?
 4. If not, to what relief Shri Pethe is entitled from 1-1-85?
 5. What Award?
- Does not survive
affirmative
Does not survive
As per order below.

REASONS

9. It is not in dispute that the workman Shri Pethe in response to the advertisement in the daily Loksaatta (Exh. 5/1) applied for the post in the Bank. The Banking Service Recruitment Board had sent him letter (Exh. 5/2) dated 19th March, 1983. It appears that after his interview, he was selected for the Post of Clerical cadre as Air-condition maintenance/Plant Operator. On 5th May, 1983, he was given an appointment letter (Exh. 5/4) which speaks that his duties will include the work of the Cash department such as the receipts and payments of cash, and dealings with cash, attending to godown, typing and other clerical duties as may be given from time to time including operation and the maintenance of the Air-conditioning plant, Electrical Appliances and Fixtures. The Workman, on its basis joined the duties of the Bank.

10. Mr. Pethe affirmed that after about four to five days of his joining, he was placed in the maintenance department. The work of that department was to maintain the Air-Conditioned window units, Central plants and all other Electrical fixtures etc. The other section of the department was doing the work of the maintenance of the Bank premises.

11. It is not in dispute that one Shri Percy Neroy was a special assistant. Mr. Pethe affirmed that he is doing all the duties which Mr. Neroy was doing. Those duties include:

- (i) Supervising all air conditioners, electrical fittings and fixtures,
- (ii) Preparing of estimates of air-conditioning machines and electrical wiring, and
- (iii) Bill scrutinisation.

He claims to have done these duties from January 1, 1985. He claims special allowance @ Rs. 450 per month from that day.

12. Mr. Pethe admits that even though he had affirmed to have done seven categories of work, namely :—

- (i) Passing independently Cash, Clearing and Transfer Cheques, Vouchers etc. (whether Credits or debits) upto and including Rs. 5,600 (or any higher limit fixed by the Bank in its own discretion). Passing will include verification of signatures and scrutiny as to the correctness of endorsements and other particulars of such instruments ;
- (ii) Signing vouchers, cheques drafts, pay orders advices, bill schedules, statements, certificates etc. ;
- (iii) Checking all vouchers, advices, statements bills, returns, books of accounts etc. ;
- (iv) Checking current, savings and other ledgers ;
- (v) Discharging, endorsing cheques, bills etc. ;
- (vi) Checking the coding and decoding of telegrams (excluding check symbols or cyphers) ;
- (vii) Inspecting godowns.

He admits that he did not do the work except that mentioned in category 3. So far as category 3 is concerned, there is again his admission which goes to show that he had not done all the works mentioned in it. In other words one has to say that Mr. Pethe is not true to his words. He is changing his versions from place to place.

13. Admittedly, Damodat Shetty (Exh. M/10) was the Officer-in-charge of the maintenance department at the Bombay main office. He worked in that capacity from 1982 to June, 1990. His duty was to look after the purchasing, stationery, maintenance and servicing of all Office equipments, premises, vehicles, airconditioners etc. Mr. Pethe was working in his department. He affirmed that Mr. Neroy was given the grade of Special Assistant only by virtue of his seniority as per the Bipartite settlement and not on account of his duty performed in the maintenance department. So far as his preposition is concerned, no documentary evidence is produced. But the fact that he was paid that special allowance is not in dispute. There is no reason as to why his word has to be rejected.

14. Mr. Shetty affirmed that after the retirement of Shri Neroy he was looking after the maintenance of the premises, equipments, electrical installations including airconditioners etc. The Airconditioning department has no books of accounts but only stock books. He used to verify the totals, estimates, service contracts and thereafter they were submitted to the higher authorities. From the cross-examination of Mr. Pethe it reveals that there was an endorsement of what the bills were, but they were never sanctioned.

15. Mr. Shetty affirmed that Mr. Neroy was doing all these works, which I have already referred above which Mr. Pethe is doing after the retirement of Mr. Neroy. On this admission, it is tried to argue on behalf of the workman that he is entitled to special allowance. There is no record to show that in what capacity Mr. Neroy was appointed. But so far as the workman is concerned, his appointment letter is on the record.

16. Exh. 574 is an appointment letter of the workman. From the letter it is very clear that he is appointed in the Clerical cadre along with other duties which are referred to above. He was look after the operation and maintenance of airconditioning plant, electrical appliances and fixtures. If this is so if the work done is in that capacity, it cannot be said to be a work of a special assistant. He was to do the technical work. As the appointment letter includes the nature of the technical work to be carried out by the claimant, there is no substance in the claim of the workman that on that ground he is entitled for special allowance.

17. So far as the work of preparing of estimates of Air-conditioning machines and clerical work is concerned, it is rightly argued on behalf of the management that the workman is responsible for the maintenance of the airconditioning plant, and electrical appliances and fixtures. If anything goes wrong with the systems and they are to be repaired, it was the duty of the workman to prepare estimates for

that purpose. It is included in the nature of work which he is required to do. As such it cannot be said that he is doing any additional work which can be said to be of a technical nature, entitling him for special allowance.

18. So far as the bill scrutinisation is concerned, as he has to maintain the airconditioners and the fixtures, it was his duty to see that the bills which are prepared by the repairer for repairs are correct. It is to be said that it was a part of the normal duties as specified in his appointment letter. Under such circumstances I find that the claim of the workman that he is entitled to special allowance in view of the technical duties which he did cannot be accepted.

19. The workman emphasizes that the Bank had paid special allowance to Mr. B. D. Kulbe and Mr. V. V. Tribhuvan. It can be seen that they have done the work of the Officers in their department. It is not the case of Mr. Pethe that he did discharge the duty of Mr. D. R. Shetty who was his Officer. Under such circumstances the analogy given by the workman also has no merit.

20. At one stage it is suggested that the post of Mr. Neroy was not filled up by the Bank and that has effected him. In the Hindustan Levers Limited v/s. Administration 1977 37 F.L.R. 150 Their Lordships have observed that the workman cannot ask the management to reorganise the Company and also cannot raise any objection if the management reorganizes or rationalises its work in such a manner that it can do without filling the posts of the persons who ceased to work in the company by reason of retirement, death or resignation. The case which is tried to put before me by the management is that after the retirement of Mr. Neroy the airconditioning department is closed and that they are managing their affairs without any trouble. I therefore find that the contention of the workman to this effect is without any merit.

21. No provision is shown to me on behalf of the workman that the management was duty bound to fill up the post of Mr. Neroy after his retirement. As this is so, relying upon the ratio given in the above said authority the management cannot be directed to fill up the post of Mr. Neroy who was a Special Assistant.

22. It is tried to argue that the workman asked for production of some documents and the management had not produced the same. But it can be seen that when they say was filed on the application of the Workman, it was contended that they don't possess the documents which are sought for. As this was so, no adverse inference can be drawn against the management as nothing is produced on the record to show that the management did possess that document and had taken a false contention.

23. Mr. Pethe admits that he was not, in writing, directed by the management to do another work which can be said to be of a Special Assistant. But he affirmed further that earlier, instructions were given to him. As against this Mr. Shetty had affirmed that Mr. Pethe had not performed any duty in the maintenance/Airconditioning department which attracts special allowance after the retirement of Mr. Neroy. It is a common knowledge that when additional authority is given or additional work is given or allotted is in writing. In the present matter as there is no such written order, it cannot be accepted that Mr. Pethe was earlier instructed to do some additional jobs other than his usual job. For all these reasons I record my findings on the points accordingly and pass the following order :

ORDER

1. The action of the management of the Bank of Baroda, in denying Officiating allowance of Special Assistance from 1-1-86 to Shri Nitin R. Pethe, Air-Conditioning Plant Operator, consequent upon the retirement of Shri Percy Neroy, Special Assistant on 31-12-85 and non filling of this post therein is justified.
2. No order as to costs.

S. B. PANSE, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1994

का. आ. 3213-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुमरण में, केन्द्रीय सरकार केनरा बैंक के प्रबन्धन के संबंध में, केन्द्रीय और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 2, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, का केन्द्रीय सरकार को 13 अक्टूबर, 1994 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल. 12011/73/82 डी-2 (ए) आई आर (बी-II)]

वी के शर्मा डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th October, 1994

S.O. 3213.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, 2, Bombay as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Canara Bank and their workmen which was received by the Central Government on 13-10-94.

[No. L-12011/73/82-DIIA/IR(B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer
Reference No CGIT-2/45 of 1989
(Old Ref. CGIT-2/34 of 1983)

Employers in relation to the Management of Canara Bank

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri R. S. Pai, Advocate.

For the Workmen—1. Shri Madan Phudnis, Advocate—for the Canara Bank Staff Union.

2. Shri I. G. Gadkari, Advocate—for the Canara Bank Employees Union.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra
L. Bombay, dated 7th September, 1994

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, by its letters No. L-12011/73/82 D.IIA dated 11th September 1983 has referred to the following industrial dispute for adjudication under section 19 of the Industrial Disputes Act. The reference is in the following words :—

“Whether the action of the management of the Canara Bank in adopting two different fitment formulae for promotion from the cadre of sub-staff to Clerical cadre i.e. one for those promoted between 1972 and 1978 and another for those promoted after August 1978 resulting in anomalies, is justified? If not, to what relief the Workmen affected entitled?”

2. The General Secretary of Canara Bank Staff Union had filed its statement of claim. It contended that after the promotions from sub-staff to Clerical cadre the Seniors in that cadre get lesser pay than the promotees. To remove that anomaly, they made representation to the management, but it did not consider the same. Then the matter was sent to the Regional Labour Commissioner (Central) for 2471 GI/94—13

his intervention. In that proceeding the stand of the management Bank was that the Bank is fixing wages payable in consultation with the recognised Union. It is averred that on 30th August, 1972 the Bank issued a circular for referring to the formula for fitment of subordinate staff on promotion to Clerical cadre. In the said formula, the members of the sub-staff being promoted to Clerical cadre were to be treated in that cadre on the basis of the said formula. It is averred that the formula had several defects. It did not consider the impact of the emolument payable to the sub-staff and clerical staff's due to different rates of neutralisation and also the impact of the past few increments against the 10% advance shown to have been given at the time of promotion. That formula became a retrograde step more glaringly because of the 3rd bipartite settlement which merged a portion of dearness allowances up to 200 points in basic salary with the result that subordinate staff promoted to clerical cadre instead of gaining some monetary benefit or atleast their emoluments as a subordinate staff being protected became looser as a result of promotion. Even the amended formula dated 18-7-80 had not served the purpose. It is averred that due to this amended formula also the infirmity continued. The workman had given instances of such an infirmity in his statement of claim.

3. The Union submits that in other Public Sector undertakings like Canara Bank, there is an expressed provision in the service rules that the pay of the Seniors who may be getting less basic pay than that of the juniors in that category shall be stepped up to that of the juniors in that category. Copy of such service rules is in the case of Hindustan Antibiotics, Pimpri which is a Public sector undertaking of the Government of India. This infirmity which is created by the Bank is deliberate with the hand glove of the Canara Bank Employees Union. It is against the interest of the Worker. The Union therefore claimed that the Canara Bank may be directed to set up the basic salary of all senior promoted from subordinate staff to clerical cadre to remove the discrimination and bring their basic salary on par.

4. The Canara Bank management had filed its written statement at Exh. 2/M&S and contended that there is no substance in the claim. It is averred that whenever there is a revision in the pay scale the effect of it would be seen whenever promotions take place in as much as the sub-staff get different allowances which have to be taken into consideration. The total emoluments of the sub-staff with the fitment formula is bound to adversely effect the case of subsequent revision of wages. This anomaly is bound to be there and there cannot be a single formula for rectifying such anomaly. It is averred that under such a case, only the individual case would have to be considered in the right of the Union and the other benefits will be available to the individual concerns.

5. The management denied to have amended the rules as per their choice and without any consultation with the Union. It is asserted that the Canara Bank Employees Union continues to have the majority even today and the negotiations can be effected with the recognised union only. It is submitted that the present reference is due to the inter union rivalries and had no merit.

6. On 22-6-1984 my Learned Predecessor decided the reference. It was also published in the Gazette.

7. The Canara Bank being aggrieved by the said order preferred writ petition no. 18305 of 1984. It was allowed and the matter was sent back to this Court for a fresh hearing certain directions therein.

8. The issues that follow for my consideration and my findings thereon are as follows :—

ISSUES

FINDINGS

1. Whether as a result of two different fitment formulae of sub-ordinate staff on promotion to clerical cadre between 1972-1978 and another after 1978 has resulted in anomalies.

YES.

2. If yes, what relief the workman effected are entitled to ?

As per the final order

REASONS

9. It is necessary to give in verbatim what are the two different formula. The formula for fitment of subordinate staff for promotion to clerical cadre of 1972 is as under :—

- I. The employees on promotion would be provided with an increase of 10% in the total emoluments drawn by them in the place in which they are working at the time of promotion.
- II. Subject to the increase stipulated as above, members of the subordinate staff in the following stages in their respective time scale of pay would be fitted in the stage in the clerical scale of pay noted against each as under :—

Subordinates in stage of sub-staff scale under the second Bipartite settlement	Fitment in clerical scale of pay under the Second Bipartite settlement
--	--

6th, 7th and 8th	1st Stage.
9th	2nd Stage.
10, 11th and 12th	3rd Stage.
13th and 14th	4th Stage.
15th, 16th and 17th	5th Stage.
18th	6th Stage.
19th and 20th	7th Stage.

After so fitting an employee, the difference in emoluments, if any, rising to provide the 10% increase in emoluments on promotion, would be treated as Temporary Adjustments Allowance (TAA) for being adjusted in their future increments and D.A. thereon. The T.A.A. will not rank for provident fund, bonus and overtime.

- III. The formula for fitment mentioned herein would also be made applicable to all subordinates staff who had been promoted so far to the Clerical cadre, for relaxation of their respective basic pays in the Clerical scale of pay as on 1st July, 1972.

10. In 1978 another formula was formed by the Bank, which came in to effect from 1-9-1978. It is as follows :—

"To the basic pay and DA which the sub-staff was drawing on the date of promotion, 10% of the same will be added together with special allowances which the employee was actually drawing subject to a maximum of dearness allowance plus DA thereon, and the sub-staff will be fitted in the clerical scale will not be less than the amount arrives as above. The fitment will also have relation to the place where he was working as "sub-staff". This formula will be effective from 1-9-78".

11. It is tried to suggest that these two formulae had not created any dispute. On account of the third Bipartite Settlement which came in to effect from 1-9-1978 the anomaly is created. As such all the sub-staff who came to be promoted after 1-9-1978 were entitled for the protection of their total emoluments. The D.A. revision factors in the third Bipartite Settlement was more beneficial to the Sub-staff than to the clerical staff, as there was a difference in the rate of neutralisation and the D.A. of 25% between the sub-staff of the clerical cadre. It is in these circumstances that the sub-staff who were promoted after 1-9-78 on their fitment of promotion to clerical cadre became entitled to emoluments. The fact from the written statement and the oral evidence which is filed by the Bank and from the oral argument I have no hesitation to come to the conclusion that these two formulae have created anomalies.

12. It appears that in the writ petition the Canara Bank Employees Union was a party before the High Court. After the remand Mr. I. G. Gadkari Advocate for that union had filed his written submissions at Exh. 11/W and had also orally argued the matter. He supports the submissions of the Bank. He argued that the anomalies have not resulted because of the admission of the two different formula, but of the other factors. According to the Bipartite settlements the non-clerical workmen (Sub-staff) receive the dearness allowance providing for 100% neutralisation of the cost of living index, while the clerical staff receive only 75% neutralisation of

the cost of living index (All India Shimla Series). What therefore happens is that the D.A. payable to the sub-staff rises much rapidly than those payable to the clerical staff. This is the main reason why the anomalies have arisen.

13. It is tried to argue by Mr. Pai that the formula in itself has not created another anomaly. Therefore the reference has to be rejected. I am inclined to accept this submission that when these two formula are to be taken into consideration the third Bipartite settlement is also to be taken into consideration while fixing the pay. Naturally the fact is that the anomalies are created. If such anomalies are there, then it is not at all justified.

14. Mr. Phadnis, the Learned advocate for the workmen i.e. the Canara Bank Employees Union argued that this Tribunal can pass the Award which was already passed by its Predecessor by giving cogent reasons. There is no dispute in this proposition. But for coming to that conclusion I have to satisfy myself that the Award which was passed by my Predecessor is just and proper. Further on remand I have to decide the matter afresh. It can be further seen that their Lordship while remanding the matter had observed that

"When the matter comes back to the Tribunal it shall take into consideration the effect or all the subsequent events that are in the existence whilst the settlement between the Workers and the Petitioner".

The settlement which took place between the management and the Canara Bank Employees Union dated 27-2-1985 is produced along with Exh. 7/M. The Learned advocate for the workmen argued that this settlement cannot be taken into consideration as the management had not taken into consideration the workman in this reference for consideration. The terms of the settlement has to be considered by the Tribunal to come to a proper conclusion.

15. Mr. Phadnis, the learned Advocate for the workmen argued that the anomalies which are occurring are because of the formula and nothing else. Unless the anomalies are considered from the point of view of the seniors and juniors no solution can be arrived at. It is submitted that the regulations of Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri and the rules prevailing in the services of the Government of India provided in the fundamental rules have to be taken in to consideration. In these rules there is a provision for removing the anomalies which are likely to occur or to be occurred after fit promotions.

16. As against this, Mr. Pai, the Learned Advocate for the management argued that after the reference there were negotiations between the management and the employees of the Bank represented by the majority Union viz. the Canara Bank Employees Union. On 28-2-1985, meeting was held and a settlement was arrived at. Under the said settlement the sub-staff who were promoted to clerical cadre between 1-1-1970 to 31-8-1978 were reviewed, and the Bank has agreed to extend the fitment formulae as per the minutes off the joint conference dated 18-7-1980 to those promotees between 1-1-70 to 31-8-1978. However, the revision on account of the above shall come into effect from 1-6-1984 and arrears shall be paid only from that date.

17. In the case of *Herbertsons Ltd. Vs.—Workmen of Herbertsons Ltd.* (1977) LJ page 162 (S.C.), the Supreme Court has held that even if a few workers are not members of the majority Union, it would be just and fair that the settlement should not be disturbed particularly when a recognised and registered Union enters into a voluntary settlement. The Canara Bank Employees' Union is a majority Union and a Union recognised by the Bank. The ratio given in this authority is aptly applicable to the present set of facts.

18. For all these reasons I find that the settlement which took place on 28-2-1985 is workable to solving out the anomaly which arisen due to two fitment formulae. So far as the contention of the workman that the regulations of Hindustan Antibiotics Limited and that of the service of the Government of India and the rules prevailing in the services of the Government of India provided in the fundamental rules to be made applicable are concerned, I do not find any merit in it, because of the settlements which took place between the management and the other Union and which is working properly. Under such circumstance I record my

findings on the points accordingly and pass the following order :—

ORDER

1. The action of the management of the Canara Bank in adopting two different formulae for promotion from the cadre of sub-staff to Clerical cadre i.e. one for those promoted between 1972 and 1978, and another for those promoted after August, 1978 resulting in anomalies, is not justified.
2. The management is directed to make applicable the settlement which took place on 28-2-1985 between the representatives of the Bank and the Canara Bank Employees Union.
3. No order as to costs.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1994

का. आ. 3214:— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एम.ई.सी.एल. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल. 22012/334/93-आई आर (सी-II)]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th October, 1994

S.O. 3214.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S. E. C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th October, 1994.

[No. L-22012/334/93-IR(C.II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.
Reference No. CGIT-2/16 of 1994

Employers in relation to the management of Nowrozabad sub Area of SFCL.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers : 1. Mr. P. S. Nair, 2. Mr. A. K. Sasi, Advocates.

For the Workmen : Mr. G. R. Swamy, Representative.

INDUSTRY : Mining. STATE : Maharashtra.
Bombay, dated 26th September, 1994

AWARD

On 7-4-94, the Government of India, Ministry of Labour had referred the following industrial dispute under section 10 of the Industrial Disputes Act for adjudication. It is in the following terms :

“Whether the action of the Sub-Area Manager, Nowrozabad Sub-Area of Johilla Area of SECL in dismissing

Shri Gorelal S/o Sudama Prasad, Miner, Nowrozabad West Colliery from Company services w.c.f. 16-12-1992 is legal and justified ?”

2. The workman contended that his dismissal from the Company's services is illegal and unjustified, which took place on 16-12-1992. He contended that no procedure was followed and arbitrary the action was taken against him. According to him, there was no justification in his dismissal. He claimed that he may be re-instated in the services, with continuity in service and with full back wages.

3. The management opposed the claim contending that the enquiry was properly held following all the legal procedures. It is asserted that there is no justification in the claim of the workman that it did not follow the principles of natural justice. It is averred that the action taken by the management against the workman is perfectly legal and proper.

4. The workman thereafter also filed his rejoinder.

5. On 22-9-94 when the matter was for documents and for evidence, the parties to the dispute filed a settlement (Exh. MW/9). They argued in respect of the terms of the settlement which was taken on the record on the very day. It is requested that the dispute may be settled on the basis of the terms of the settlement. I find justification in the same. In the result I pass the following order :

ORDER

1. The dispute is disposed of in view of the terms of the Settlements at Exh. MW/9.

2. It is ordered that :

(i) Shri Gorelal s/o Sudama, Minor, T. No. 220 shall be reinstated within the 15 days of the signing of this settlement subject to medical fitness.

(ii) The period of absence shall be treated as “DIES NON”.

(iii) The continuity of service shall be given for the purpose of gratuity.

(iv) If the workman does not turn up within one month of signing of the settlement it shall be presumed that he is not interested and therefore he shall loose his case for reinstatement.

(v) The case shall not be cited as precedence.

(vi) It is agreed that the copies of this settlement shall be filed before the C.G.I.T. (Bombay) for consent award in case No. CGIT/R-2/16/94.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1994

का. आ. 3215:— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, एस. सी.सी.एल.के. प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल. 22012/198/91-आई आर (सी-II)]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th October, 1994

S.O. 3215.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SCC Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 12-10-1994.

[No. L-22012/198/91-IR(C.II)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT
HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.
Dated, 1st day of October, 1994
Industrial Dispute No. 37 of 1991

BETWEEN

Sri Sansar Singh, C/o Sri Nanchand
Singh, R/o Nutanding, P.O. Jag Jivnagar,
Dt. Dhanbad (Bihar)-826003. ..Petitioner

AND

The General Manager, RG(P), S.C. Co. Ltd.,
P.O. Godavarikhani, Dist. Karimnagar-
505209. ..Respondent.

APPEARANCES :

M/s. G. Bikshapathi and others, Advocates for the
Petitioner—workman.

M/s. K. Srinivasa Murthy and others, Advocates for the
Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. J-22012/198/91-IR(C.II), dated 22-8-1992 referred the following dispute under Section 10(1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, RG (Project) Godavarikhani and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Management of M/s. S. C. Co. Ltd., RG (Project), Godavarikhani in dismissing Sri Sansar Singh, Peon from services w.e.f. 14-5-87 without giving sufficient opportunity to defend his case is legal and justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled to?"

The reference is registered as Industrial Dispute No. 37 of 1991 and notices were served on both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the Petitioner workman read as follows :—The Petitioner was appointed as Peon in the year 1982 in Coal Mines Labour Welfare Organisation. The Coal Mines Labour Welfare Organisation transferred the petitioner to its Regional Hospital at Ramagundam on 18-8-1982. The Petitioner applied for leave from 6-11-1985 to 24-11-1985. After going to his native place, the petitioner fell ill. He sent letter to the Superintendent, Area Hospital for extension of his leave from 25-11-1985 to 24-12-1985. However, the Petitioner did not recover from illness and he was admitted in Mental Hospital, under intensive care and treatment was given from 30-11-1985 to 19-8-88 for mental imbalances. After recovery from illness, petitioner came to know that he was dismissed from service by an order dated 24-5-1987, when he reported for duty with fitness certificate at Area Hospital, Godavarikhani. Aggrieved by the action of the Respondent in dismissing the petitioner from service by an order dated 24-5-1987, the petitioner raised Industrial Dispute which culminated in present dispute. The Respondent failed to see that the petitioner had applied leave from 6-11-1985 and further extended leave by one month. However, due to mental illness, the Petitioner could not join duty after the sanctioned leave. The Respondent failed to see that the petitioner did not attend the duties only due to illness. He has reported to duty along with the Medical Certificate issued by the Doctor. Therefore, the absence of the Petitioner does not come within the meaning of Misconduct under 16(16) of the Standing Orders of the Company. Therefore the dismissal from service for the alleged misconduct is illegal and unwarranted. The action of the Respondent in calling the Petitioner for interview and rejecting his case on the ground of defective eye vision is equally arbitrary. It is therefore prayed that the Hon'ble Court may be pleased to hold that the action of the Respondent in dismissing the petitioner from service is illegal and arbitrary and consequently pass an Award directing the Respondent to reinstate the petitioner into service with back wages, continuity of service and other attendant benefits and pass orders as this Hon'ble Court deems fit and proper.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent-Management read as follows : It is true that the petitioner was appointed as a Peon on 18th August, 1982 in the erstwhile Regional Hospital, Ramagundam. It is true that the petitioner applied for leave for 15 days from 6-11-1985 to 24-11-1985. But after expiry of the leave period neither he joined duty nor sent any communication to the Management either for extension of leave or whether he was suffering from any ailment. Petitioner is fully aware that if he was interested to take extension of leave prior to the expiry of leave itself he had to make an application which he has not chosen to do so and remained absent continuously for more than 10 days after expiry of leave, which is misconduct under Clause 16(16) of Company's Standing Orders. As such management initiated disciplinary action and issued a charge sheet dated 27-4-1986. Petitioner has received the charge sheet on 2-5-1986 at his address at Jagjivanagar, Dhanbad 826003. As there was explanation from the petitioner within the stipulated period, Company appointed an Enquiry Officer to conduct enquiry into the charge-sheet. As such the allegation that Sri Sansar Singh sent a letter to the Superintendent, Area Hospital, Ramagundam for extension of leave by one month from 25-11-1985 to 24-12-1985 is not correct. The allegation that the petitioner did not recover from illness and he was admitted in Mental Hospital, is not correct. The petitioner conveniently remained absent from 25-11-1985 and for the first time in August, 1988 he came up with a case that he should be taken into service. It is true that the petitioner submitted a mercy petition, but the allegation that the management refused to reinstate the petitioner into service is not correct. Sri Sansar Singh is estopped by his conduct now to raise the issue on the dismissal order passed on 24-5-1987. It is not out of place to mention that having aggrieved of the dismissal order Sri Sansar Singh came before the Review Committee for Medical Examination for appointment as Badli worker. Without prejudice to the rights of this respondent management it is respectfully admitted that the domestic enquiry is conducted and then the order of dismissal was passed. There are no merits in the Petitioner's case. In view of the above mentioned facts this Hon'ble Court may be pleased to dismiss the claim petition and the petitioner is not entitled for re-instatement into service with back wages, continuity of service and other attendant benefits.

4. The point for adjudication is whether the Respondent in dismissing Sri Sansar Singh, Peon from service w.e.f. 24-5-1987 without giving sufficient opportunity to defend his case is legal and justified.

5. Before going into the merits of this case, this Tribunal decided the validity of the domestic enquiry and passed order on 21-9-1994 holding the domestic enquiry conducted by the Respondent Management against the petitioner as fair and proper. The above order is part and parcel of this award.

6. It is an admitted fact that the Petitioner-workman was appointed as Peon in the year 1982 in Coal Mines Labour Welfare Organisation and then the petitioner was transferred to Regional Hospital at Ramagundam on 18-8-1982 when the Coal Mines Labour Welfare Organisation was abolished. The case of the Petitioner was that he applied for leave from 6-11-1985 to 24-11-1985 and went to his native place where he fell sick. That he sent letter to the Superintendent, Area Hospital for extension of his leave from 25-11-1985 to 24-12-1985, since the petitioner did not recover from illness he was admitted in Mental Hospital under intensive care and treatment from 30-11-1985 to 19-8-1988 for mental imbalances. When the Petitioner reported for duty with fitness certification at Area Hospital, he came to know that he was dismissed from service by an order dated 24-5-1987. Later petitioner was asked to appear before the Committee on 21-6-1989 for review of his case for providing employment as Badli Filler by the letter issued by the General Manager, Project, Ramagundam Division. Due to defective vision in right eye, the petitioner was not provided with employment. The petitioner raised this dispute aggrieved by the action of the Respondent in dismissing the petitioner from service by an order dated 24-5-1987.

7. It is seen that the Petitioner was suffering from mental disease and that is why he could not attend to duty. It is also seen that he sent a letter to the Superintendent, Area Hospital for extension of his leave from 25-11-1985 to 24-12-1985 and that he was under intensive care and treatment from 30-11-1985 to 19-8-1988 as he suffered mental imbalances. It is also seen that after recovery from illness, petitioner came to know that he was dismissed from service

by an order dated 24-5-1987 when he reported for duty with fitness certificate at area hospital, Godavari khani. Further it is also the case of the petitioner that he received a letter issued by the General Manager, Projects, Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division asking him to appear before the Committee on 21-6-1989 for review of his case for providing employment a Badli Filler. So on the ground of defective vision is right eye he was not provided with employment. It is pertinent to note that the petitioner was appointed as Peon and there is no disability for performing the same duty. It is also pertinent to note that the defective eye vision does not come in the way for performing the duties of a Peon. So the action of the Respondent in calling the Petitioner for interview and rejecting his case on the ground of defective eye vision is arbitrary and invalid. The Petitioner appeared before the Committee on 21-6-1989 for review of his case for providing employment as Badli Filler. Here the petitioner is not a Coal Filler, or Mazdoor so as to review his case for Badli Filler's post, he is only a Peon employed. Therefore I find that the dismissal from service for the alleged misconduct is illegal and unwarranted, as the Respondent failed to see that the Petitioner did not attend the duties only due to illness. Hence I find that the petition is entitled to be reinstated into service as the dismissal from service is illegal and arbitrary.

8. In the result, the action of the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, R. G. (Project) Godavari khani in dismissing Sri Sansar Singh, Peon from service with effect from 24-5-1987 without giving sufficient opportunity to defend his case is illegal and unjustified. Sri Sansar Singh is entitled to be reinstated into service with full back wages, continuity of service and all other attendant benefits and the Respondent-Management is directed to pay the arrears to the Petitioner-workman within one month from the date of publication of this Award.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this 1st day of October, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I
APPENDIX OF EVIDENCE

The oral and documentary evidence adduced IR the preliminary point is treated as part and parcel of this Award.

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1994

का. आ. 3216 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, एस. सी. मा. एल. के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती हैं, जो केन्द्रीय सरकार को 12/10/94 को प्राप्त हुआ था।

[एल-22012/335/90 आईआर (सी-II)]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th October, 1994

S.O. 3216.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SCC Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 12-10-1994.

[No. L 22012/335/90-IR (C-II)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT
HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.
Dated, 30th day of September, 1994
Industrial Dispute No. 5 of 1991

BETWEEN

The Vice President, Singareni Coal
Mines Karmika Sangh (BMS), Qtr. No. DB. 154,
Ramavaram PO Kothagudem Tq.
Khammam District

Petitioner

AND

The Managing Director, M/s. Singareni
Collieries Company Limited,
Kothagudem (A.P.), Khammam Dist.-507101

Respondent.

APPEARANCES :

M/s. G. Bikshapath, G. Vidyasagar, N. Vinesh Raj
and G. Ravi Mohan, Advocates--for the Petitioner.

M/s. K. Srinivasa Murthy and G. Sudha, Advocates—
for the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-22012/335/90-IR (C-II), dated 8-3-1991 referred the following dispute under Section 10(1)(d)(2 A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., Kothagudem in fixing the seniority of seven Stenographers enlisted below on the basis of date of appointment of the employees in the organisation instead of professional seniority is justified? If not, to what relief the concerned Stenographers are entitled to?"

1. Sri A. Satyanarayana.
2. Sri K. Venkata Raju.
3. Sri D. Ram Mohan Rao
4. Sri Y. Subba Rao
5. Sri Y. Chandra Sekhar
6. Sri G. Vayunandana Rao
7. Sri V. V. Subba Rao."

This reference was registered as Industrial Dispute No. 5 of 1991 and notices were issued to both the parties.

2. The Petitioner workman has not filed the claim statement and the Advocate for the Petitioner stated across the Bench on 5-9-94 that the reference may be terminated. Hence I find that the Petitioner-workman are not interested in pursuing the matter and that I find there is no reason to adjudicate the case.

3. In the result, the reference is terminated and award passed.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 30th day of September, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I
Appendix of Evidence

NIL

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1994

का. आ. 3217 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार विजवा बैंक के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक

विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बेंगलूर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-12012/16/92-आई. आर. बी-2]

[बी० के० शर्मा डेरक, अधिकारी]

New Delhi, the 17th October, 1994

S.O. 3217.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Vijaya Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 13-10-1994.

[No. L-12012/16/92-IR (B.II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, CUM LABOUR COURT, BANGALORE.

Dated this 28th day of September, 1994

PRESENT :

Sri M. B. Vishwanath, B.Sc., B.L., Presiding Officer
Central Reference No. 44/92

I Party	v/s.	II Party
The Gen. Secy., Vijaya Bank Workers' Organisation, No. 37/1, 1st Floor, Car Street, Ulsoor, Bangalore-560008. (By Sri B. D. Kuttappa, Advocate)		The Gen. Manager, Vijaya Bank, Head Office, 14, M. G. Road, Trinity Circle, Bangalore-01. (By Sri B. C. Prabhakar, Advocate)

AWARD

In this reference made by the Hon'ble Central Govt. by its order No. L. 12012/16/92-IR (B.II) Dt. 29-4-92 under Sec. 10(2A) (1)(d) of the I.D. Act the point for adjudication as per schedule to reference is :—

"Whether the action of the management of Vijaya Bank in striking off the name of the workman Sh. A. P. Muthanna, Spl. Asstt. Kowdle Branch from roll w.e.f. 17-8-90 for alleged absence is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. In the claim statement it is contended :—

The I party workman was working as a special assistant at the Kowdle branch of II party. His services were illegally terminated w.e.f. 17-8-90 on the ground that he was unauthorisedly absent for more than 90 days from 1-4-90. The termination (Striking Off) is illegal. The II party has stated that I party was deemed to have voluntarily retired from service. The I party fell seriously ill w.e.f. 1-4-90. So he was compelled to proceed on leave. He was forced to take leave because of his ill health. The Manager of the Kowdle branch has ignored the applications sent by the I party for extension of leave. The I party went to his native place for better medical facilities.

After I party recouped his health he went to Kowdle branch on 22-10-1990 to report for duty. The Manager at Kowdle branch refused to take him on duty. The I party workman is not aware of the notice sent by the II party as per

the provisions of B.P.S. The I party workman had informed the II party about his ill health. There was no intention on the part of the I party workman to abandon the services or to take retirement voluntarily.

The II party ought to have conducted an enquiry against the I party before illegally terminating the services of I party. The I party has been unemployed and has been suffering untold hardship. The order passed by the II party striking off the name of the I party from the rolls is illegal. The I party has to be reinstated with consequential benefits.

3. In the counter statement it is contended :—

The I party workman was working in Kowdle branch. He has voluntarily retired from the services of the bank w.e.f. 17-8-90. The I party was unauthorisedly absent from 1-4-90. So a final notice dt. 17-7-90 was sent to I party his local address and also permanent address by registered post, asking the I party to report for duty within 30 days. It was made clear in the notice that if he failed to return for duty within 30 days, it would be deemed that he had voluntarily retired from service. The notice sent to the local address of I party was returned with the remarks "addressee not available during delivery time". Regarding the notice sent to his permanent address, the bank received neither the postal acknowledgment nor the undelivered cover. Since the notice was sent to his local and permanent addresses as given by the I party, it should be deemed that the notice had been served on I party. The I party's name was struck off from the muster roll w.e.f. 17-8-90 as per Clause 17 of the B.P.S.

The I party workman was sanctioned leave by the Branch Manager for the period from 18-1-90 to 31-3-94. The I party failed to report for duty after 31-3-90. The II party has followed the correct procedure. The I party who failed to report for duty within 30 days from the date of service of notice must be deemed to have voluntarily retired from service, I party having remained absent unauthorisedly for more than 90 consecutive days. The allegation that I party was ill is false. This is only an after thought to suit his convenience. There is no force in the allegation that the II party should have conducted an enquiry against the I party. The reference has to be rejected.

4. As could be seen from the order sheet dt. 26-10-93 it has been stated by this Tribunal that the point for adjudication is covered by the schedule to reference and no other issues were necessary. It has also been made clear that all other subsidiary points if any, would be considered at the time of final arguments.

5. On behalf of the II party MW.I Sanjeeva Shetty, Sr. Manager has been examined. On behalf of the I party workman he has got himself examined and closed his case.

6. It is admitted that the I party was granted leave from 18-1-90 to 31-3-90. The case of the II party is that the I party remained unauthorisedly absent, without intimation to II party, for more than 90 days w.e.f. 1-4-90. The further case of the II party is that they sent, under the provisions of the BPS notice as per Ex. M-1 to the local address and the permanent address, given by I party through RPAD directing the I party to report for duty within 30 days of notice. The I party did not report for duty and so he was deemed to have voluntarily retired from service, having no intention to join the duty. This is in accordance with Clause 17 of B.P.S.

7. Ex. M-2 is the cover in which the original of Ex. M-1 was enclosed. The notice sent to the local address of the I party by registered post has been returned with the remarks that the I party was absent in this address for a number of days. Thus the mandatory notice directing the I party to return to duty within 30 days has not been served on the I party.

8. Ex. M-3 is the postal receipt. According to II party they sent the notice as per Ex. M-1 directing the I party to return to duty within 30 days by R.P. to his permanent address. Admittedly neither the postal acknowledgment nor the unserved registered cover has been produced to this Tribunal. Nobody knows about the postal ack. or the registered cover. In fact the Sr. Manager M.W. I, to use his own language in the evidence, "the notice sent to permanent address,

the fate of it is not known". M.W. 1 has further stated that since the I party did not report for duty the competent authority passed the order as per Ex. M.4 holding that the I party had voluntarily retired from service and his name was struck off from the muster roll w.e.f. 17-8-90 M.W.1 has stated that the final notice sent to his permanent address was served as per the postal ack. Ex. M.5.

9. In deciding this matter we are not concerned whether the final or striking off the name of the I party from muster roll was served. The crux of the matter is whether the notice as per Ex. M.1 directing the I party to report for duty within 30 days from the date of service of notice was served on I party or not. To repeat, the one sent to local address was not served and it was returned M.W.1 has stated that the fate of the notice sent to permanent address of I party is not known. On the strength of the receipt Ex. M.3 it is hazardous to hold that the notice sent by R.P. to the permanent address of I party was served on him.

10. From the facts and discussion above it is clear that the II party has not complied with the mandatory provisions of B.P.S. directing the I party to return for duty within 30 days from the date of service of notice. I come to this conclusion because the notice Ex. M.1 has not been served on the I party.

11. For the aforesaid reasons, I am of opinion, the order striking off the name of the I party from the muster roll has to be set aside and the II party should be directed to reinstate the I party.

12. The I party workman is entitled to succeed on yet another ground.

13. The case of the II party is that the I party workman remained unauthorisedly absent from 1-4-90 continuously for more than 90 days. The decision reported in 1993 (II) L.L.J. 696 (D. K. Yadav v/s. IMA Industries Ltd.) arose out of the award passed by the Labour Court, Haryana. The workman had wilfully absented himself from duty for more than 8 days without leave or prior permission from the management and therefore he was deemed to have left the service of the company on his own account and lost his lien and the appointment because clause 13 (2) (iv) of the standing order was that if a workman remained absent without sanctioned leave he shall lose his lien on his appointment unless he reports to duty within 8 calendar days of the commencement of the absence. In accordance with the standing order, the name of the employee was struck off from the muster rolls. The Labour Court up-held the termination order passed by the management. Ultimately the matter went to Hon'ble Supreme Court.

The Hon'ble Supreme Court after observing in para 13 at page 702 that "the order of termination of service of an employee/workman visits with civil consequences of jeopardising not only his/her livelihood but also career and livelihood of dependents" has laid down, "Therefore, before taking any action putting an end to the tenure of an employee/workman fair play requires that a reasonable opportunity to put forth his case is given and domestic enquiry conducted complying with the principles of natural justice." The Supreme Court was pleased to set aside the termination order and reinstate the employee.

14. In the instant case admittedly no D.E. has been held and the conditions for retrenchment have not been complied with. In view of the latest decision of the Supreme Court the order of termination as per Ex. M.4 has to be set aside and I party reinstated.

15. The Learned counsel for the II party has relied on a decision of the Kerala High Court to impress upon me that I should hold that the service of notice of Ex. M.1 should be held sufficient. He has not produced the authority. In view of the law laid down by the Supreme Court the Kerala High Court authority would not have been helpful to the II party.

16. It is feebly contended in the counter-statement that the I party is not a workman. No arguments were addressed in this regard. The schedule to reference states that I party is a workman.

ORDER

The order passed by the II party striking off the name of the I party workman w.e.f. 17-8-90 for alleged absence is not justified. Accordingly the said order striking off the name of the I party is set aside. The II party is directed to reinstate the I party forthwith with continuity of service. II party is directed to pay 50 per-cent of the back wages to I party. Award passed as stated herein. Submit to Government.

(Dictated to Stenographer, typed by him corrected, signed by me on this 28th day of September 1994).

M. B. VISHWANATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1994

का. आ. 3218 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्तर्गत में, केन्द्रीय सरकार सी. एस. आर. टी. आई., मैसूर के प्रबन्धन के संयुक्त विभाजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिरक्षण, बंगलूर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 17 अक्टूबर, 1994 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-42012/29/87 डी-II (बी)]

के० बी० बी० उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th October, 1994

S.O. 3218.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Centre Sericulture Research and Training Institute, Mysore and their workmen, which was received by the Central Government on 17th October, 1994.

[No. L-42012/29/87-D.II (B)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BANGALORE

Dated this 28th day of September, 1994

PRESENT :

Sri M. B. Vishwanath, B.Sc., B.L., Presiding Officer.
Central Ref. No. 4/89

I PARTY :

H. Mahadeva,
Dr. No. 3379,
3rd Cross, 6th Main,
S.J. Hostel Road,
Vidyaranyapuram,
Mysore-570008.

(Bv Smt. Mangalamba Rao, Advocate)

V/s.

II PARTY :

The Member Secretary,
Central Industrial Tribunal,
United Mansions,
M.C. Road,
Bangalore-560001.

(By Sri R. Gururajan, Advocate)

AWARD

In this reference made by the Hon'ble Central Government by its Order No. L-42012/29/87-D-II (B) dated 27-12-88 under Section 10(2A)(1)(d) of the I.D. Act the point of adjudication as per schedule to reference is :—

"Is the management of Central Sericultural Research and Training Institute, Mysore, justified in imposing the punishment of dismissal on Sri H. Mahadeva, Field-cum-Labour Assistant, w.e.f. 20-3-86. If not, to what relief is the workman entitled?"

2. In the claim statement it is contended :—

The I party workman was working as a skilled field-cum-labour assistant at Central Sericultural Research and Training Institute. The I party was suspended on false charges of attempting to misappropriate Government funds. He was issued with a charge sheet by the II party. A statement of acceptance of guilt was taken from I party under coercion. It was taken by Dr. J. Kodandaramaiah Sr. Research Asstt. of II party. The I party was not given any opportunity to defend himself in the enquiry. There was no D.E. against the I party. The II party has dismissed the I party. That the order of dismissal is illegal.

The I party has served the II party for over 7 years and had completed more than 240 days of continuous service. He was a Class-IV employee. The I party belongs to S.C. He belongs to a poor family and has got wife, four children to feed. The I party is suffering untold hardship. The I party had not tried to misappropriate any Government amount. The order of dismissal is illegal. It has to be set aside. The II party should be directed to reinstate the I party with continuity of service, back wages etc.

3. In the counter statement it is contended :—

The I party while working at Mysore submitted two cash bills viz., bill No. 3172 dated 15-5-85 and bill No. 6614 dated 16-5-85. Those bills were for Rs. 10.80 ps. and Rs. 14. The I party with an intention to defraud the Board tampered the same to read as Rs. 180.80 for the first bill and Rs. 114.00 for the second bill. He also submitted another certificate. The said certificate indicated an amount of Rs. 24.80 which was tampered to Rs. 294.80. On coming to know of this, he was kept under suspension and he was also issued with a memorandum dated 7-1-86. Alongwith the memorandum, an articles of charge with list of documents were made available to him. In reply, he categorically admitted each one of the charges in his explanation dated 5-2-86. Under those circumstances and in view of the acceptance of the articles of charge, the Board by its order dated 20-3-86 passed an order of termination in view of a clear admission. On the part of the I party with regard to the articles of charge levelled against him. The II party was fully justified in terminating the services of the I party in view of his admission. The action taken by the II party is perfectly legal. The Board is justified in imposing penalty of dismissal on the I party. Since the I party admitted guilt in his explanation, no further enquiry was required. Accordingly no D. E. was held. Even if for any reason the Tribunal holds that the admission made by the I party is bad the II party be given an opportunity to lead evidence and justify its action. It is absolutely not true to say that one Dr. J. Kodandaramaiah, Sr. Research Asstt. had taken the acceptance as sought to be made out.

4. My Learned Predecessor as could be seen from the order sheet dated 2-5-89 has framed the following issues :—

1. Whether the II party proves that the I party workman admitted to the charges and that it was justified in not holding any domestic enquiry against him?

2. If issue No. 1 is in the negative, whether the management proves the charges levelled against him?

5. On the above issues, on behalf of the management MW-1 K. N. Meenakshi, Asst. Secy. (Law) and MW-2 Dr. Kodandaramaiah, Asst. Director have been examined. On behalf of I party he got himself examined and closed his case.

6. In respect of the incident alleged against the I party workman there was a criminal complaint against the I party at the instance of the II party. This criminal case was C.C. No. 1583/89 before the Court of the J.M.F.C. (II Court) at Mysore. Ex. W-1 is the certified copy of the Judgment. The Learned Magistrate has held that the case of prosecution suffers lack of cogent evidence. After coming to the conclusion that there was no material to hold the I party guilty he has acquitted the accused. The Learned counsel for the I party tried to press into service the conclusion as per Ex. W-1 and submitted that I party should be held to have not committed incident alleged against him. In the Criminal Court the offence has to be proved beyond reasonable doubt. In the Tribunal what is required is preponderance of evidence. In view of this position in Law, simply relying on Ex. W-1 and deciding in favour of the I party would be wrong.

7. I will look to other circumstances as placed before this Tribunal.

8. The annexure to Ex. M-10 contains the charges against the I party. The allegations against the I party were that he attempted to defraud the Government by tampering cash memo, essentiality certificate as stated below :—

- 1 Cash bill No. 3172 dated 15-5-86 for Rs. 10.80 was tampered with to read "Rs. 180.80" (Difference Rs. 170.00)
- 2 Cash bill No. 6614 dated 16-5-86 for Rs. 14.00 was tampered with to read Rs. 114.00 (Difference Rs. 100.00)
3. Essentiality certificate indicating the amount of Rs. 24.80 was tampered with to read Rs. 294.80 (difference Rs. 270.00)

He claimed Rs. 296.80 on medical Form (Med-97) dated 21-5-85 on account of treatment of self from 15-5-85 to 21-5-85.

9. When the charge sheet was issued to I party workman he gave explanation as per Ex. M-11 (Ex. M-11 is the zerox copy. Original of Ex. M-11 is not disputed).

10. The Asst. Secretary (Law) of II party MW-1 has stated in her evidence that in view of the admission of I party in his explanation Ex. M-11 to charge sheet Ex. M-10 they did not hold any D.E. against the I party. The case of the II party is that the I party workman admitted the charges against him and so the II party did not think it fit to hold a D.E. There was no necessity to hold a D.E. in view of his admission in Ex. M-11. The case of the I party, as set out in the claim statement is that Ex. M-11 was taken from him under coercion. It is argued by the Learned counsel for the I party workman that since Ex. M-11 was obtained under coercion, Ex. M-11 has to be chucked out. If Ex. M-11 is not taken into consideration, it means no D.E. is held against the I party and so the I party workman has to be reinstated with other benefits.

11. Now the point for consideration is whether the II party was justified in acting on the admission of I party in the explanation Ex. M-11.

12. The I party, as already stated, has stated in his evidence that he has not given any confession letter on his own accord. He has further stated that the alleged confession letter Ex. M-11 was written by Kodandaramaiah (MW-2) in English and his signature was obtained by force by promising that nothing would happen to him (I party). Even in the claim statement the I party has stated that the II party's officer MW-2 Kodandaramaiah took the alleged confession letter Ex. M-11 and MW-2 himself wrote it. In his evidence before this Tribunal MW-2 Kodandaramaiah has admitted that Ex. M-11 is in his hand writing, though

he has denied that he promised I party that I party would have no problem if he put signature to Ex. M-11.

13. In this regard the stand of II party in para 5 of the counter statement speaks like the Oracle of Delphi. It is not clearly stated that Kodandaramaiah took confession letter which was signed by I party and it was not under coercion. What is discussed so far sheds lurid light on Ex. M-11.

14. Remembering that I party is a Class-IV servant, let me have a close look at Ex. M-11 which was written by, mind you, by the II party's officer MW-2. The signature of I party in Ex. M-11 is admitted. In Ex. M-11 it is recited "I admit each article of charge mentioned in the memo." It is stated that "due to my default and too much financial problem in my family, I was tempted to correct medical bills and attempted to defraud the Government's money while claiming reimbursement of medical expenses. Kindly pardon me for this." The I party has referred to his being placed under suspension and that he "suffered a lot with humiliation, my colleagues and family members". Ex. M-11 is written in good English and the wording is so perfect it could have not been the intention of I party to give Ex. M-11 voluntarily. If the I party had any intention to admit the guilt, the MW-2 would have asked the I party to get confession letter typed or written by somebody else. Senior Officer like MW-2 working under the II party himself writing the admission or confession letter militates against the case of the II party.

15. It is reasonable to hold, as stated by the I party in his evidence that MW-2 Kodandaramaiah obtained the signature to Ex. M-11 by promising that nothing would happen to him (I party).

16. It is argued by the Learned counsel for the II party that the letter Ex. M-13 which bears the signature of the I party also amounts to admission of guilt. Ex. M-13 is dated 27-3-86. The order of dismissal of I party is dated 20-3-86 (Ex. M-12). Ex. M-13 has sprung into existence just after the order of dismissal. Under what circumstances and under what provision of law the II party obtained Ex. M-13 is not clear. No doubt Ex. M-13, if believed, amounts to admission of guilt on the part of the I party.

17. This document Ex. M-13 taken after the order of dismissal looks highly suspicious. The I party has admitted his signature in Ex. M-13. I party has been confronted with M-13 in cross-examination. He has volunteered that the contents of Ex. M-13 are false. It is very significant to note that it has not been put to I party workman in cross-examination that the contents had been written in his own handwriting.

18. For the aforesaid reasons I am of opinion that Ex. M-13 also has to be discarded.

19. If Ex. M-11 and 13 are discarded, what emerges is that an order of dismissal has been passed on the I party workman without holding a regular D.E. and II party was not justified in not holding D. E. against the I party. Accordingly I hold issue No. 1 framed by my Learned Predecessor against the II party.

20. Now I take up issue No. 12. The Asst. Secretary (Law) MW-1 has deposed in her evidence that Ex. M-1 is the certified copy of the application filed by I party for reimbursement. MW-1 has stated that the I party has altered the amounts in column 9 and 11 in Ex. M-1. Ex. M-2 is the essentiality certificate copy signed by A.M.A. MW-1 has stated that I party was altered at Ex. M-2 (a) and (b). He has altered 10 to 70 at both places. He has altered the price of medicine also. Ex. M-3 is the medical bill produced by the I party alongwith Ex. MW-1 has stated that I party has altered the amounts and quantity of medicines in Ex. M-3. At Ex. M-3(a) I party has altered 250 to 1250. He has altered Rs. 8.30 to Rs. 88.30. He has made other alterations in Ex. M-3 to claim the inflated amounts. He has altered the two cash bills Exs. M-3 and 4. Though I party was entitled to Rs. 24.80 from both bills, through the tampered bills he has claimed Rs. 284.90. The office got suspicion and issued the charge sheet.

21. MW-1 has stated that they wrote to the A.M.A. Dr. Mohan who had issued the essentiality certificate. Ex. M-5 shows that the Doctor has stated, after issuing essentiality certificate and the cash memos, the cash memos and the bills have been altered. Exs. M-6 and 8 are the letters written by the Medical stores from which the I party had purchased the medicines. Exs. M-7 and 9 are the duplicate bills sent by the medical stores.

22. These documents Exs. M-5 to 9 clearly shows that the original bills Exs. M-3 and 4 have been altered. Essentiality certificate Ex. M-2 also has been altered. In para 3 of the claim statement the I party has stated that after receiving the order of dismissal, he submitted his representation to II party stating that he had not done any lapses in his duties and that he has not attempted to misappropriate any Government funds. This is what the I party has stated in the claim statement. He has not clearly denied the various alterations in the essentiality certificate and the medical bills. What's more, he has not denied the alterations even in his examination-in-chief before this Tribunal, though he has denied in the cross-examination the suggestion that he has made alterations.

23. Regarding the alterations alleged against the I party workman the I party has not clearly denied the alterations in his examination-in-chief or in his claim statement. The only conclusion possible is that he has made the alterations alleged against him. So I hold that the charges against the I party alleged in Ex. M-10 are proved in this Tribunal. So I hold issue No. 2 in favour of the II party.

24. The matter does not rest with the finding on issue No. 2. The Tribunal has to see, in view of Section 11-A of the I. D. Act whether the punishment imposed on the I party was justified or not.

25. There are some mitigating circumstances against the I party. MW-1 has stated that the I party has not drawn any amount in pursuance of the false medical bills he submitted for reimbursement. The I party has stated in his claim statement that he belongs to S.C. community. This is not controverted in the counter statement. The I party has been dismissed w.e.f. 20-3-86.

26. It has been laid down by the Supreme Court in AIR 1989 S.C. page 149 (Scooter India Ltd., Lucknow v/s. Labour Court, Lucknow) that though disciplinary enquiry is found to be fair and lawful and its findings were not vitiated in any manner, that by itself would not be a ground for non-interference of the order of termination of service. The Supreme Court has been pleased to lay down in this authority that the erring workman should be given an opportunity to reform himself and prove to be loyal and discipline employee. This law has been laid down by the Supreme Court in a case where the D.E. is held fair and lawful and the findings of the E.O. were not vitiated in any manner. The I party has tried to claim about Rs. 270 in excess. The excess amount claimed falsely, in my opinion, is meagre. I am of the view that the punishment imposed on I party is disproportionate and harsh. I am of the view that reinstatement should be ordered and back wages should be considerably reduced.

ORDER

The order as per Ex. M-12 terminating the services of I party w.e.f. 20-3-86 is set aside. The II party is directed to reinstate the I party forthwith with continuity of service. The I party is granted 15% of the back wages. Award passed as stated herein. Submit to Government.

(Dictated to Stenographer, typed by him, corrected, signed by me on this 28th day of September, 1994)

M. B. VISHWANATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1994

का. आ. 3219 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पश्चिम रेलवे के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं० 2, वर्ल्ड के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41011/36/88-डी II (बी) आई-आर बी-I]

बी० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th October, 1994

S.O. 3219.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Railway and their workmen, which was received by the Central Government on 13-10-1994.

[No. L-41011/36/88-D.II (B)/IR B-I]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/52 of 1989

Employers in relation to the management of Western Railway, Bombay

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Mr. T. N. Sharma, Representative.
For the Workmen—Mr. B. K. Sharma, Representative.

INDUSTRY : Railways

STATE : Rajasthan

Bombay, the 8th September, 1994

AWARD

Shri Mohd. Hassanbhai and 40 others are Casual Labourers working and are having a temporary status granted Khallasis having their Head quarters at Abu Road, working under the Chief Signal Inspector (Const.) Western Railway, Aburoad. These labours are sent out of the head quarters beyond 8 kilometers to work at different stations. As such they are entitled to daily allowance, and T.A. but it was not paid to them. The Chief Signal Inspector (Const.) transferred these casual labours from one station to another, to curb their privileges for which they are entitled to. He used to send these employees out of the Head Quarters on temporary transfer to different stations. Being aggravated by the conduct of the Railway Administration a demand was placed by the Paschim Railway Karamchhari Parishad but was not accepted. Hence the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi has sent the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication. It is in the following words :

“Whether the action of the management of Western Railway in refusing to fix Abu Road Railway Station as Headquarters of Shri Mohd. Hassan Bhai and other temporary status Khallasis working under Chief Signal Inspector (Construction) Abu Road and their consequent denial to pay

them T.A./D.A. for remaining out of their Head-quarter (Aburoad) is justified ? If not, to what relief the workman entitled to ?”

2. The Railway Administration by its Written statement (Exh. M/4) denied the contents of the statement of claim. It is averred that their action is according to Law. Shri Mohd. Hassanbhai and other casual labours are not Head-quartered at Abu Road, but their Headquarter was kept at a station where the work was not in progress. As they were stationed at different places, there was no question of sending them beyond 8 kilometers from Abu Road to work at different stations and giving them daily allowance. It is asserted that it is wrong to say that when the workers are sent on duty above 8 kilometers of range, they are not paid daily allowance. It is submitted that the application is not complete, as no name of other workers are given but are said to be effected by the action of the management.

3. My Learned Predecessor framed issues at Exh. 5. My findings thereon are as follows :

ISSUES

FINDINGS

- Whether the workman Shri Mohd. Hasan Bhai and the other In the affirmative casual labourers were head-quartered at Abu Road ?
- Whether the action of the management of Western Railway in refusing to fix Abu Road Railway station as Headquarters of Shri Mohd. Hassan Bhai and other temporary status khallasis working under Chief Signal Inspector (Construction) Abu Road and their consequent denial to pay them T.A./D.A. for remaining out of their Headquarter (Abu Road) is justified ?
- If not, to what relief the workman entitled ? They are entitled to T.A. and D.A. as per the rules
- What Award ? As per the final order.

REASONS

4. No oral evidence was lead in this matter. But the workman had filed its written argument at Exh. W/7 and the management at M/8. On the basis of these arguments, it can be very well seen that admittedly Shri Mohd. Hassan Bhai and the other 40 Casual labourers were working in with the Chief Signal Inspector (Construction) Western Railway, Abu Road. It is not in dispute that the Casual labourers are not liable to transfer. Certain privileges are admissible to T.S. granted casual labourers based on the General Manager, Western Railway, Churchgate's letter No. E/HER/1082/601 dated 14-4-1989 and APO (Bills) Churchgate's No. F(P&A) 95/5/1 dated 21-8-87. It is averred that as per the rules, the transferring allowance is not admissible but the matter is in consideration. It is not disputed that the Khallasis are entitled to T.A. when they are deputed to beyond 8 kilometers of their Headquarters.

5. Further I.R.E.M. rule 2511 clarify privileges admissible to temporary status granted casual labours. These employees are temporary status granted employees.

“2511—Rights and privileges admissible to casual labourers who are treated as temporary after completion of six months continuous service :

- Casual Labours treated as temporary are entitled to all the rights and privileges admissible to temporary railway servant as laid down in chapter XXIII of the IREM. The rights and privileges admissible to such labours are also include the benefit of the D. A. Rules. Their services, prior to the date of completion of six months continuous service will not however count for any purpose like reckoning of retirement benefits, seniority etc. such casual labours will also be allowed to carry forward the leave at their credit to the new post of on absorption in regular service”.

6. Rule 2508 of IREM clearly states that these employees are admissible TA/DA 2508" Travelling Allowance—ordinary payment of travelling allowance to casual labourers should not arise as they are recruited locally where necessary and are not liable to transfer. However, when it is necessary to depute them on duty away from their Headquarters daily allowed will be paid to the skilled, semi skilled and unskilled casual labourers".

7. It is tried to argue on behalf of the management that as per the circular dated 3-6-1992, guidelines are given in respect of T.A. and D.A. and transfer and packing allowance for casual labourers work on railway. It appears to me that this circular cannot be taken into consideration in due of the rules under the Act and the decision given in Ramnivas Matadeen and 42 others v/s. Union of India and others (1991) 15 Administration Tribunal cases 366.

8. In Ramnivas case the Applicants were railway employees as casual labourers enjoying temporary status. On completion of work at one place they used to be shifted to another. Since the new places of work were 8 kms away from their headquarters, they claimed travelling allowance and daily allowance for journeys to and from such places. Under para 2501 of the Manual, a casual labourer is not liable to transfer. Hence shifted from the Headquarters to work at certain projects he would still be deemed to have retained his headquarters to work at the original place. In view of the provisions of Rule 203 of the Code and para 2508 of the Manual, the applicants, who are railway servants under para 2507 of the Manual, if deputed to work beyond radius of 8 kms. from their headquarters would be entitled to daily allowance as well as travelling allowance.

9. The ratio given in the above said authority is applicable to the present set of facts. The claim of the applicant is perfectly legal and proper, under such circumstances I record my findings on the points accordingly and pass the following order :

ORDER

1. The action of the management of Western Railway in refusing to fix Abu Road Railway station as the Headquarters of Shri Mohd. Hassan Bhai and other temporary status Khallasis working under the Chief Signal Inspector (Construction) Abu Road and their consequent denial to pay T.A./D.A. for remaining out of their Headquarter (Abu Road) is not justified.
2. The management is directed to treat Shri Mohd. Hassan Bhai and other temporary status Khallasis as working under the Chief Signal Inspector (Construction) Abu Road, and to pay them T.A./D.A. and treat their Headquarters as Abu Road.
3. No order as to costs.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1994

का. प्रा. 3220 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार रेलवे इलेक्ट्रिकेशन, कोटा के प्रबंधन के संबंध निर्यातों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, कोटा के संघर्ष को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13 अक्टूबर, 1994 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/155/89-आई आर (डी यू)/बी-1]

वी. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th October, 1994

S.O. 3220.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Kota as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of

Railway Electrification, Kota and their workmen, which was received by the Central Government on 13-10-1994

[No. L-41012/155/89-IR (DU)/B-I]

V. K. SHARMA, Desk Officer

अनुबंध

न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण (केन्द्रीय) कोटा, राज.

निर्देश प्रकरण क्रमांक ओ. न्या. (केन्द्रीय)-16/1990

दिनांक स्थापित 2-8-90

प्रसंग: भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश

क्रमांक एल. 41012/155/89-आई. आर. (डी. यू.)

दिनांक 27-7-1990

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मध्य

डिजिटल सैकेट्री, पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद, कोटा.
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के सामने, भीमगंज मण्डी,
कोटा।

प्राची युनियन

एवं

डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे इलेक्ट्रिकेशन, कोटा
प्रतिपक्षी नियोजक

उपस्थित

श्री आर. के. चाधान,

आर. एच. जे. एस.

प्राची युनियन की ओर से कोई उप. नहीं
प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से श्री अशोक कुमार
(बिधि सहायक)

अधिनियम दिनांक 8 सितम्बर, 1994

अधिनियम

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निम्न
निर्देश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे तदुपरान्त
"अधिनियम 1947" से सम्बोधित किया जायेगा) की धारा
10 (1) (घ) व उपधारा (2-क) के अन्तर्गत इस
न्यायाधिकरण को अधिनियमार्थ सम्प्रेषित किया गया है :—

"Whether the action of the Distt. Electrical Engineer (OHE), Railway Electrification, Kota is justified in discontinuing the scale rate of Sh. Basudev, Casual Khallasi w.e.f. 20-1-85? If not, what relief the workman concerned is entitled to?"

2. निर्देश न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व पक्षकारों को सूचना जारी की गयी। प्राची श्रमिक वासुदेव की ओर से प्रस्तुत क्लेम स्टेटमेंट के अनुसार इस प्रकार है कि प्राची श्रमिक वासुदेव को प्रतिपक्षी के यहाँ दिनांक 7-4-84 को आकस्मिक मजदूर के पद पर भर्ती किया गया व 18-10-84 को प्राची को स्केल-रेट प्रदान किया गया। दिनांक 13-12-84 को एवजी साप्ताहिक (सी.आर.) पर प्राची था जो सक्षम अधिकारी ने प्रवकाश स्वीकार किया था जिसका भुगतान भी प्राची को कर दिया गया था परन्तु बाद में 13-12-84 को (एन.पी.) अनुपस्थिति लगाकर फरवरी, 1985 के बिल से बिना किसी पूर्व सूचना के प्राची के वेतन से कटौती कर दी गयी। इसी प्रकार प्राची 7-1-85

को छुटा दिया था व 8-1-85 को बताया साप्ताहिक एजजी अवकाश (सी.आर.) पर था परन्तु इन दोनों दिनों में प्रार्थी की अनुपस्थिति बतायी गयी है। प्रार्थी यदि 20 दिन तक अधिकृत रूप से नोकरी से गैरहाजिर रहता है तो उसके स्केल-रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रार्थी 21/2/84 से 20-1-85 तक 20 दिन से ज्यादा अधिकृत रूप से काम से गैरहाजिर नहीं रहा इसलिए 20-1-85 से स्केल-रेट में जो कटौती की गयी है वह सही नहीं है जो उसे प्रदान की जाय।

3. प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रार्थी श्रमिक के क्लेम का विरोध करते हुए यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी श्रमिक ने 3 दिन का एजजी साप्ताहिक अवकाश (सी.आर.) दिनांक 11-12-84, 12-12-84 एवं 13-12-84 का मांगा था जो स्वीकार कर भुगतान कर दिया गया, लेकिन वरिष्ठ लेखाधिकारी, रेल विद्युतीकरण, कोटा ने इस पर आपत्ति की कि सी.आर. दो दिन से अधिक देय नहीं है, इस पर 11-12-84 व 12-12-84 का दो दिन का सी.आर. माना गया व 13-12-84 को (एन. पी.) अनुपस्थिति करार दिया गया व 13-12-84 का जो अधिक भुगतान कर दिया वह नियमानुसार समायोजित किया गया व इसी प्रकार प्रार्थी श्रमिक 7-1-85 से 10-1-85 तक चार दिन अनुपस्थित रहा, जैसा कि वरिष्ठ विद्युत फोरमैन (आएवई) रेल विद्युतीकरण ने 1-12-84 से 10-1-85 के बेज पीरियड की उपस्थिति रजिस्टर में दर्शाया है। इसी प्रकार 11-1-85 से 20-1-85 तक 10 दिन तक बिना वेतन के अवकाश पर था जैसा कि बेज पीरियड 11-1-85 से 10-2-85 की उपस्थिति रजिस्टर में वरिष्ठ विद्युत फोरमैन, रेल विद्युतीकरण, सवाईमाधोपुर ने दर्शाया है। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक 7-1-85 से 20-1-85 तक उपस्थित नहीं था इसलिए अनुपस्थिति लगायी गयी। चूंकि एक बार उपस्थिति रजिस्टर जब वरिष्ठ लेखाधिकारी, रेल विद्युतीकरण, कोटा को भुगतान हेतु भेज दिया जाता है तो उसमें किसी प्रकार की हेराफेरी करने की संभावना नहीं है और यही कारण था कि एक बार 7-1-85 व 8-1-85 को उपस्थिति रजिस्टर में "ए" दर्शाया गया है तो उसी को वास्तविक माना गया और इन दोनों दिनों को एजजी अवकाश पर रहना लेखा विभाग ने अमान्य कर दिया। अतः प्रार्थी 22 दिन तक अनुपस्थिति रहा जिसका पूर्ण विवरण जवाब के पैरा 5 में दिया है इसलिए प्रार्थी का स्केल-रेट 20-1-85 से बन्द कर दिया गया। पुनः प्रार्थी द्वारा 180 दिन दिनांक 20-1-85 से 20-7-85 तक सेवा पूरी करने पर 21-7-85 से दुबारा स्केल रेट दिया गया व 360 दिन पूरे करने पर अस्थाई दर्जा दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर स्केल-रेट काटा गया था, अतः प्रार्थी का क्लेम निरस्त किया जावे।

4. प्रार्थी श्रमिक ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसने जिरह में स्वीकार किया है कि मेरी हाजिरी फोरमैन लगाता था जिससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। 7 जनवरी को काम पर हाजिर था व 8 जनवरी को मैंने रेस्ट लिया था जो नहीं माना गया। हम प्रार्थी श्रमिक के द्वारा नियमा-

नुसार छुट्टी नहीं लेने पर एवं 20 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर उसका स्केल-रेट 20-1-85 से काटा गया जो बाद में समायोजित पूर्ण होने पर पुनः बहाल कर दिया गया।

5. बहम सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि ने यह तहस की है कि प्रार्थी श्रमिक उनके विभाग में कर्मचारी हैं, उससे विभाग के सम्बंधित अधिकारी की किसी प्रकार की रंजिश नहीं थी। चूंकि प्रार्थी ने नियमानुसार अवकाश प्राप्त नहीं किया एवं 20 दिन से अधिक अनुपस्थित रहा इसलिए 22 दिन की अनुपस्थिति मानते हुए 20-1-85 से स्केल-रेट बन्द किया गया जो पुनः प्रार्थी श्रमिक के 180 दिन पूरे होने पर 21-7-85 से बहाल किया गया एवं 360 दिन लगातार सेवा पूरी करने पर अस्थाई दर्जा दिया गया। इन कारण प्रार्थी श्रमिक के स्वयं के अनुपस्थित रहने पर उसका स्केल-रेट नियमानुसार काटा गया जिसके आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने का कोई गुआईश नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी श्रमिक ने 11-12, 12-12 व 13-12-84 के एक साथ साप्ताहिक एजजी, अवकाश लिए थे जो नियमानुसार स्वीकृत नहीं किए जा सकते थे इसलिए लेखा विभाग के अधिकारियों ने उसे मंजूर नहीं किया व इसी प्रकार 7-1-85 व 8-1-85 को भी प्रार्थी श्रमिक हाजिर नहीं हुआ इसलिए उसकी अनुपस्थिति लगायी गयी, ऐसी मूरत में प्रार्थी श्रमिक का यह कहना कि वह समय पर हाजिर हुआ था, सही नहीं माना जा सकता एवं मेरी राय में प्रार्थी श्रमिक का जो स्केल-रेट 22 दिन की अनुपस्थिति पर 20-1-85 से काटा गया है वह सही है, फलस्वरूप प्रार्थी कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता।

6. उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सम्प्रेषित निर्देश को इस प्रकार उल्लिखित किया जाता है कि प्रतिपक्षी नियोजक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (शोएचई) रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, कोटा द्वारा प्रार्थी श्रमिक वासुदेव की स्केल-रेट 20-1-85 से काटना/बन्द करना उचित है और फलस्वरूप वह कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

इस अधिनिर्णय को समुचित सरकार को नियमानुसार प्रश्रयानार्थ भिजवाया जावे।

आर. के. चाचान, न्यायाधीश

नई दिल्ली 18 अक्टूबर, 1994

का.प्रा. 3221:- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लि. के प्रबन्धतंत्र के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन केन्द्रिय सरकार को 13-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-30012/1/90-आई आर (विविध)]/[आई आर (कोल-I)]

बज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 18th October, 1994

S.O. 3221.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employees in relation to the management of Indian Oil Corporation Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 13-10-94.

[No. L-30012/1/90-IR(Misc.)/IR(Coal-I)]

BRIJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BANGALORE

Dated this 28th day of September, 1994

PRESENT :

Sri M. B. Vishwanath, B.Sc., B.L., Presiding Officer
Central Ref. No. 31/90

I PARTY :

Sri M. B. Peerapur,
s/o Basappa,
Ex. Assistant,
House No. 1-1495-42-B,
Rathna Deepa,
Ganduthainagar,
Gulbarga-585 102,
(By Sri S. Vasanthakumar, Advocate).
V/a.

II PARTY :

The Deputy Gen. Manager, (Operation),
Indian Oil Corporation Ltd.,
Southern Region,
Indian Oil Bhavan,
Nungabhakam,
Madras-600 034.
(By Sri B. C. Prabhakar, Advocate).

AWARD

In this reference made by the Hon'ble Central Govt. by its order No. L-30012/1/90-IR(Misc.) dt. 17-5-90 under Sec. 10(2A)(1)(d) of I.D. Act the point for adjudication as per schedule to reference is :—

“Whether the action of the management of Indian Oil Corporation Ltd., Southern Region, Madras in terminating the services of Sri M. B. Peerapur, Ex-Assistant w.e.f. 20-7-87 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?”

2. In the claim statement it is contended :—

The I party was appointed by the II party on 25-8-65 as Assistant at Bombay. He was transferred to Gulbarga in 1982, at the request of the I party. The I party was appointed purely for clerical job. But the depot manager M. R. Srinivasan of II party at Gulbarga allotted typing work also to I party, though the I party did not know typing. In this regard the depot manager started harassing the I party. The I party submitted to the depot manager that instead of appointing a qualified typist it was highly unfair to allot him typing work. In this regard the I party workman made several representations to the Chairman I.O.C. Ltd., New Delhi and sent copies to the General Manager, I.O.C. Ltd., Madras.

Then a charge sheet was issued to I party. This was because the I party had complained against the harassment to I party by the depot manager M. R. Srinivasan. The I party again wrote to the Chairman bringing to his notice the hardship and mental agony to I party. The I party gave a reply to the charge sheet. A departmental enquiry was instituted. The D.E. was adjourned to 15-6-87. The I party was informed that the enquiry fixed on 15-6-87 was adjourned. No adjourned date was given.

Meanwhile the I party received the communication dt. 20-7-87 that his (I party's) resignation dt. 5-3-87 was accepted. By another letter dt. 20-7-87 the I party was relieved

w.e.f. 20-7-87. The resignation letter submitted by the I party is not voluntary. It was conditional. So the acceptance of the resignation is bad and relieving of I party from the services is bad. The relieving letter (Ex. M.19) dt. 20-7-87 terminating the services of the I party is illegal. The allegations against the I party are false. The order of termination has to be set aside and the I party is entitled to be reinstated with seniority and back wages.

3. In the counter statement it is stated :—

In pursuance of the circular issued by the II party calling for a few vacancies of typist/clerk the I party applied for the post. The II party satisfied itself that the I party knew typing and that he had declared that he knew typing. The application of I party was counter signed by the Installation Manager.

On 17-8-77 the I party was posted in the Central Laboratory and he was redesignated as Assistant. On the request of the I party, he was transferred to Gulbarga depot. He joined at Gulbarga depot on 7-2-87. Gulbarga depot is a very small depot. The I party in his capacity as assistant was attending cash, clerical work and typing.

Since the transfer to Gulbarga was on the request of I party, he lost his seniority and other transfer benefits. The I party was grumbling about the loss of seniority. He started defying the instructions of the superiors. He was frequently refusing to carryout the instructions of the superiors. The I party took up the stand that he was not expected to do typing and typing would affect his health. There were complaints about the work of I party.

On 13-1-87 a charge sheet was issued to the I party, charging with 5 acts of misconduct. He was asked to show cause why disciplinary action should not be taken against him. He gave explanation dt. 30-1-87 denying all the charges. After adjournments the D.E. was fixed on 3rd and 4th of June 1987. Meanwhile the I party sent his resignation letter dt. 5-3-87 addressed to the Chairman. In view of the resignation letter of the I party the D.E. was not proceeded with. The resignation was accepted on 25-6-87. On 9-12-87 the I party was paid a sum of Rs. 21,423.70 ps. towards gratuity. The I party also settled his P.F. fund. All the benefits were settled. After everything was settled he started agitating that his resignation was conditional etc. In view of his resignation letter which was on his own accord and which resignation was accepted the I party workman has no cause of action. The resignation has been accepted and it has come into effect. But for his resignation letter, the II party would have gone on with the D.E. The I party is not entitled to any relief since his resignation has been accepted. The reference has to be rejected.

4. As could be seen from the order sheet dt. 11-3-91 it is stated by the Tribunal that the point for determination is covered by the schedule to reference and no separate issues are required. As usual I have been hearing on all subsidiary points at the time of final arguments.

5. On behalf of the II party MW-1 S. N. Murthy, Manager of II party and MW-2 Jayaram Shetty, Depot Manager have been examined. On behalf of the I party he has got himself examined and closed his case.

6. At the relevant time the I party workman was working as Assistant in the Gulbarga depot of the II party. It is admitted that the II party issued the charge sheet Ex. M.13 to I party. The II party had just begun the D.E. At this stage, it is the case of the II party, the I party workman submitted the resignation and it was accepted and the I party was relieved as per Ex. M.19 and the I party's services came to be terminated this way.

7. MW-2 Jayaram Shetty, Depot Manager has stated in his evidence that I party submitted two resignation letters Ex. M.16 and 17 addressed to the Chairman. Ex. M.18 is the letter showing that the II party accepted the alleged resignation letter of I party. In this Ex. M.18 specific reference is made to the resignation letter dt. 5-3-87 Ex. M.17. Ex. M.19 is the document showing that the I party was relieved. The II party's document Ex. M.18 accepting the resignation of I party refers to I party resignation, I repeat, letter dt. 5-3-87. So we have to see only the resignation

letter dt. 5-3-87. This resignation letter is Ex. M.17. MW-2 has stated that I party sent two resignation letters Exs. M.16 and 17. This cannot be given any weight. There cannot be two resignation letters. There can be only one resignation letter.

8. Ex. M.17 is the resignation letter of I party on which, the II party has acted. They have accepted Ex. M.17.

9. It is argued by the Learned counsel for the I party that Ex. M.17 is a conditional resignation letter and the II party has accepted this conditional letter of resignation and so the termination of the services of I party has to be set aside.

10. It is argued by the Learned counsel for the II party that Ex. M.17 is a voluntary and unconditional and the II party was right in accepting the resignation Ex. M.17.

11. In Ex. M.17 I party, in his poor English, has narrated how hard he was working when he joined the services in 1965 in Bombay. He has stated that he had no place to sit at that time and there was no water to drink and so he was bringing the water to drink. He has stated that he worked day and night without O.T. allowance. Then he has gone on to explain that at present he has been asked to do typing work which is not expected to do. He has stated that he takes trouble even on holidays to do typing work. He has stated that because of the typing work other work is pending. He has passed only SSLC. He has stated that the II party is not thinking about his problems. He has stated that he has to spend a whole day for typing because he is not a typist.

12. He has stated in Ex. M.17, alleged resignation letter, that because he is doing typing other work is pending. No one is understanding his problem. He has no alternative but to resign. ("If no one is understanding my problem no alternative for me to resign.") He has further stated that the management is forcing him to do typing which is a technical job. He has stated that he has taken only 15 or 20 days leave in 5 years. He has complained that after getting charge sheet he is feeling very bad. (I am feeling very bad. I am not well.). He has stated that under these circumstances better to work in the fields and so he has asked his resignation letter be accepted. (You "accept" my letter).

13. I have extracted above the recitals in the resignation letter Ex. M.17. It is abundantly clear that I party was mentally agitated and so he submitted his resignation letter Ex. M.17. By no stretch of language could it be said that Ex. M.17 is voluntary and unconditional. The II party was thoroughly wrong in accepting the conditional letter of resignation Ex. M.17. The II party has clutched at straw to get rid of I party.

14. MW-1 has stated in examination-in-chief that I party has voluntarily submitted his resignation. He does not say whether this refers to Ex. M.16 or Ex. M.17. There is no cross-examination on the say that the I party has voluntarily submitted his resignation. Since there was no cross-examination, it is submitted, it should be held Ex. M.17 is voluntary. There is no force in this argument because it has been suggested to M.W.2 that Ex. M.17 contains allegations against some officers and M.W.2 has stated that Ex. M.17 contains allegations against some officers.

15. The Learned counsel for the II party pointed out a number of surrounding circumstances to show that the intention of I party was to resign and so Ex. M.17 should be considered as voluntary. We are not interpreting any ambiguous will to ascertain the intention of the testator. In this reference we are concerned with the purported resignation letter and the Tribunal should look only into the recitals of Ex. M.17 to ascertain whether it was voluntary and unconditional or whether it was conditional. In view of the nature of Ex. M.17, pointed out above, I have no hesitation in holding that the resignation letter Ex. M.17 is conditional and not voluntary.

16. For the aforesaid reasons I am of opinion the termination of the services of I party w.e.f. 10-7-87 on the strength of Ex. M.17 is not justified.

17. Ex. M.16 is also styled resignation letter. This is dated 15-3-87. The Learned counsel for the II party tried to press this into service. As I have already stated the resignation acceptance letter Ex. M.18 refers to I party's resignation letter dated 5-3-87 which is Ex. M.17. It is not proper to the Tribunal to look into Ex. M.16, and hold against the I party.

18. Assuming for moment that even Ex. M.16 is the resignation letter of I party, it won't improve the case of II party. Even in Ex. M.16 the I party has stated that after issue of charge sheet by the II party he was feeling "very bad" since he had served II party for 22 years and that he does not want to take the blame that he was a shirker. These recitals clearly show that even Ex. M.16 is not voluntary and unconditional. No doubt I party has stated in cross-examination that he sent Exs. M.16 and 17 by R.P. and he wrote Exs. M.16 and 17 voluntarily. This does not mean that the resignation is voluntary and unconditional. In examination-in-chief he has stated that his resignation letter Ex. M.16 is not voluntary. We have to look to the resignation letter Ex. M.17 only which I have analysed above.

19. All other documents and evidence not referred to by me are not relevant. In any case they do not alter my conclusions reached above.

20. For the aforesaid reasons I pass the following order:—

ORDER

It is held that the action of the II party in terminating the services of I party workman w.e.f. 20-7-87 is not justified. The II party is directed to reinstate the I party forthwith with continuity of service. I party is granted 25% of back wages. Reference accepted accordingly. Submit to Government.

(Dictated to Stenographer, typed by him, corrected, signed by me on this 28th day of September 1994).

8-9-94

M. B. VISHWANATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3222:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) को धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मै. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की कापासारा कोलियरी के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, प्रनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-(सं. 1), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 12-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-20012/76/88-डी.4(ए)/आई प्रार (कोल-I)]

ब्राज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 18th October, 1994

S.O. 3222.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad as shown in the industrial dispute between the employees in relation to the management of Kapasara Colliery of M/s. E.C.L. and their workmen, which was received by the Central Government on 12-10-94.

[No. L-20012/76/88-D.IV(A)/5R (Coal-I)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d)(2-A) of Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 170 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of **Kapasara Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd.**

And

Their Workmen

PRESENT :

Shri P. K. Sinha, Presiding Officer

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.
For the Workmen—Shri S. Bose, Secretary, RCMS.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal

Dated, the 6th October, 1994

AWARD

By Order No. L-20012(76)/88-D-IV(A)/I.R. (Coal-D) dated, the 15th November, 1989 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

“क्या कपसारा कोलियरी में कोलफिल्ड्स लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा श्री शिव शंकर सिंह को सेक्यूरिटी इंस्पेक्टर के पद पर दिनांक 15-7-81 से नियोजीकरण नहीं किए जाने की कार्रवाई उचित है ; यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुसूच का अधिकार है।”

2. The dispute has been settled out of Tribunal. A memorandum of settlement has been filed in this Tribunal. I have gone through the terms of settlement and I find those to be fair and reasonable. I allow the prayer to pass an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of this award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Sec. 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

P. K. SINHA, Presiding Officer

FORM H

(See Rule 58)

Memorandum of Settlement signed on 27-8-94 between the Management of Mugma Area with the Representative of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

Name of Parties :

1. Representing employer(s) :

- (1) Sri A.P. Yadav, Personnel Manager.
- (2) Sri S. N. Singh, Personnel Manager.

2. Representing workmen :

- (1) Sri Kesho Singh, Representative of R.C.M.S.
- (2) Sri Ramakant Singh, Rep. of R.C.M.S.

SHORT RECITAL OF THE CASE

R.C.M.S. Union raised a dispute before A.L.C(C), Dhanbad for promotion of Sri Shiv Shankar Singh, Security Havildar of Kapasara Colliery now at Shampur 'B' Colliery to the post of Security Inspector which ended in failure. The failure report was sent to the appropriate Govt. who refers the matter to the Tribunal No. 1, Dhanbad for adjudication and the same case is running at Tribunal No. 1, Dhanbad. The union and the management has discussed this issue several times and lastly agreed to settle the dispute on the following terms and conditions :

TERMS AND CONDITIONS

- (1) That Shri Shiv Shankar Singh, the workman concerned will deemed to have been upgraded to Security Sub-Inspector's grade on 31-1-82 notionally and his wages as per his settlement will be notionally arrived at as on 31-1-82. Therefore from year to year his wages as per his entitlement will be increased and arrived at notionally till 31-12-93.

That for this period from 31-1-82 to 31-12-93 the workman shall not be entitled to any wages or benefits as per the notional fixation as said above.

- (2) That actual payment of wages as per the notional fixation as said above, will be made as from 1-1-94 provided that payment through regular wage sheets will start as from 1-10-94 and for the period from 1-1-94 to 30-9-94 eligible balance wages will be paid within three months.
- (3) That the fixation of wages as said in the paras (a) & (b) above will be made by the Finance Dept. of the employers.
- (4) That this settlement the instant matter and any and every matter existing therefrom stands fully and finally settled.
- (5) That this settlement will take effect as from the date the Hon'ble Tribunal, Accepts this settlement as fair and proper is pleased to pass an Award in terms of the settlement.

The management and the workman agreed to submit the settlement before Hon'ble Tribunal No. 1, Dhanbad to give his award accordingly.

1. (A. P. Yadav)
Personnel Manager,
Mugma Area
2. (S. N. Singh)
Personnel Manager,
Mugma Area.
1. (Kesho Singh)
Rep. of R.C.M.S.
2. (Ramakant Pd. Singh)
Rep. of R.C.M.S.

WITNESS :

1. Sd/- Surendra Pal Singh (RCMS)
2. Sd/- Egbal Hussain (G.M. Office)

27-8-1994

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3223—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूच में, केन्द्रीय सरकार केनारा बैंक के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुसूच में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 2, बम्बई के पंचपद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/543/88-डी-II-ए/आई. आर (बी 2)]
को. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 18th October, 1994

S.O. 3223.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Canara Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 18-10-1994.

[No. L-12012/543/88-D-II-IR (B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT:

Reference No. CGIT-2/8 of 1989

Employers in relation to the Management of Canara
Bank.

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

For the Employers: Shri R. S. Pai, Advocate.

For the Workmen: Shri P. C. Marpakwar, Advocate.

Bombay, dated 5th October, 1994

AWARD PART-I

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by its letter No. L-12012/543/88-D.I(A) dated 28-3-1989 has referred to the following industrial dispute for adjudication, to this Tribunal under section 10(1)D of the Industrial Disputes Act of 1947. It is in the following terms:

"Whether the action of the management of Canara Bank in dismissing from the service Shri K'shan Sonajit Jawahare is justified? If not, to what relief is the Workman entitled to?"

2. Shri Kishan Sonajit Jawahare was appointed as a Clerk in the Canara Bank at Bombay in the year 1969. He continued to be in that post, till 1980, when he was transferred to Nagpur. There he was appointed as a Special Assistant. He was a member of the Staff Union and was taking keen interest in the acts of the Union. But the management did not like this.

On 19-8-1985, the Canara Bank management, charge-sheeted him, levelling various charges covered by regulation 3(j) and regulation 3(m) of the Canara Bank Service code. It is alleged that the workman made entries unauthorisedly and fraudulently. He misused his Official position. It is also alleged that the workman fraudulently transferred a sum of Rs. 1500 from the S.B. A/c No. 2421 to S.B. A/c No. 4379 with ulterior notice.

4. The workman submits that he was not given proper opportunity to meet the allegations and it is pleaded that the list of witnesses and the documents were not given to him. It is asserted that his prayer for the appointment of an Advocate to represent him was denied. It is further submitted that the Enquiry Officer acted as the Presenting Officer which resulted in to putting of questions to the witness which are prejudicial to the Workman. It is averred that the observation in the Enquiry report clearly goes to show that he had a bias mind against the workman. In all, it is submitted that the enquiry which was held against the workman is against the principles of natural justice.

5. The workman submitted that the punishment which is awarded to him is disproportionate to the charges. He has asserted that he was not given proper hearing by the Appellate authority before whom, he presented his application. It is therefore prayed that there may be reinstatement in the service with full back wages and continuity in service along with the other reliefs.

6. The management, by its written statement Exh. M/3 represented all the allegations. It is averred that the workman was given full opportunity to defend his case. The domestic enquiry was carried out as per the rules framed in the Bipartite agreement and the Canara Bank Service code-regulations. It is denied that the workman was not given a proper opportunity to defend his case and that the Enquiry Officer had a bias mind against him. It is asserted that it is not at all necessary to appoint a presenting officer in the domestic enquiry. It is denied that the Appellate Authority did not give him a proper hearing and that the punishment is disproportionate to the charges levelled against the worker.

7. My Learned Predecessor framed in all 5 issues for adjudication at Exh. 4. On 13-3-91 an order was passed to the

effect that the issue No. 1 to be tried as preliminary issue. The issue and my finding thereon is as follows:

ISSUE

FINDING

1. Whether the workman proves that the enquiry held against him was not held properly, that the rules of natural justice were not followed, and that he was not given sufficient and proper opportunity to defend himself?

In the negative

REASONS

8. From the testimony of Shri Jawahare, it is crystal clear that at no time he gave a written application allowing him to be represented through an Advocate. What he contended is that he made oral request to the Enquiry Officer for the appointment of Advocate which came down. Now it is necessary to look in to relevant provisions relating to the appointment of Advocate in the departmental proceedings.

9. The relevant provisions of the Canara Bank Service Code, that is, Chapter XI, Rule 9, Clause (d) reads as follows:

"...The employee shall, if he so desires, be permitted to be defended by any employee of the Bank or by a representative of a Registered Union of Bank, Employees, but a stranger or a Lawyer shall not appear for the Employee, without the previous permission in writing of the concerned Deputy General Manager of Circle Office/International Department/Assistant General Manager of Personnel Wing Heads."

10. Clause (a) of paragraph 19.12 of the Bipartite Settlement provides as follows:

"An employee against whom disciplinary action is proposed shall be permitted to be defended (i) by a representative of Registered Trade Union.... or with the Bank's permission by a Lawyer."

Now it can be seen that as there was no written application to the Enquiry Authority or to the competent authority, in respect of getting permission for appointment of a Lawyer, there is no question of rejection. It is therefore allegation of the worker that he was not allowed to be represented through an advocate is baseless.

11. It can be further seen that on 30th October, 1985, he wrote a letter informing the Authorities that Mr. Menon would be engaged as the representative who is the Secretary of the Canara Bank Staff Union. That letter is at page 9 of the enquiry proceedings. On 22-1-1986, a charge-sheet appeared in the enquiry proceeding alongwith Mr. Naik the General Secretary of the Canara Bank Staff Union. On that day, he asked for one month's time for making the payment of the loss he caused to the Bank. On that day also he had not given any application for engaging Advocate as a defence representative. The Workman had admitted that he had signed below all the enquiry proceedings which he attended. From the perusal of the enquiry proceedings, it reveals that there was no witness to the Enquiry Officer for engaging an Advocate for his representation. On the contrary it speaks otherwise that he was represented through Mr. Menon and Mr. Naik, the Secretary and the General Secretary of the Union. It can be further seen that the workman is a graduate, and at relevant times he was working as Office Assistant. I therefore find that there is no substance in the arguments of the workman. No natural justice was followed at the time of the enquiry by refusing to appoint Advocate to defend his case.

12. It is tried to argue that there was no Presenting Officer in the said enquiry and as such the Enquiry is vitiated. In many authorities from the perusal of the rules it cannot be said that in a domestic enquiry the Bank was bound to appoint the Presenting Officer. The questions which were put by the Enquiry Officer to the witnesses cannot be said to be in the form of suggestive nature. he had to put those questions to elucidate the things that had taken place. It cannot be said that he is partial towards the management who carried out the departmental enquiry.

13. The main contention of the worker is that he was not allowed to be represented through an Advocate, vitiates the departmental enquiry.

14. In the written argument, the Learned Advocate for the workman had given about 25 different questions, according to which they are the leading questions. In Mulchandani Electrical and Radio Industries Ltd. and Their Workmen THEIR LORDSHIPS of the Supreme Court have observed that when some questions are put by the Enquiry Officer by way of clarification for the circumstances, it cannot vitiate the enquiry at all. They are necessary. For elucidating the matter furthermore, the witness has to be cross-examined later on. On that ground also it cannot be said that the departmental enquiry was not proper.

15. The workman has given a list of witnesses and documents to the employee. The employee, i.e. the workman has signed the enquiry proceeding below the same. As he has signed it, he cannot say that he did not receive the documents, nor the list of witness. It can be seen that whenever asked for adjournment, the matter was adjourned and sufficient opportunity was given to him to cross-examine the witnesses and to lead evidence.

16. It is tried to argue that the Enquiry Officer persuaded the workman to accept the guilt. I find that this is without any basis. Infact, when his first plea was recorded, the workman pleaded not guilty to the charges and the enquiry was started. At one stage, the workman declined to cross-examine the witness as his defence representative was not present, and therefore the matter was adjourned. That itself goes to show that the Enquiry Officer had taken sufficient care to give an opportunity to the workman to cross-examine the witness. The workman declined to cross-examine the witness, which was on the 2nd and the 3rd July, 1986. An endorsement was made to that effect that :

"The charge-sheeted Employee states that he does not wish to cross-examine the witness."

This proceeding was also signed by the workman. It means that he admits the facts mentioned therein. On page 5 of the enquiry proceeding, it is observed that the charge-sheeted employee does not want to cross-examine another witness, nor he wanted to examine himself as the witness. The proceeding was closed for the delivery of findings. That page of the enquiry proceeding was also signed by the worker.

17. From the argument which is done on behalf of the workman that he was not given opportunity to cross-examine has no merit. It is because, he himself chose not to cross-examine the witness and now he cannot say that he was not given the proper opportunity to cross-examine.

18. There is one allegation that the Enquiry Officer persuaded the workman in admitting the guilt. The Enquiry Officer has filed an affidavit contending that he had not met the worker on 1-7-1986, or anybody at the Skylark Hotel. He had produced evidence to support this contention. The Railway reservation ticket and the Hotel receipt showing that he left for Nagour from Bombay on 1-7-86 from Dadar-Nagour Express and reached there on the 2nd July, 1986 at 6.00 a.m. Therefore the question of meeting the workman on 1-7-1986 is without any basis.

19. From the perusal of the record of the enquiry proceeding, it is very clear that the worker was clearly informed regarding the charges levelled against him. They are clear in their terms. When the witnesses were examined by the management, the workman was also present. The testimony relates to the charges levelled against him. The workman was given full opportunity to cross-examine them. He was given an opportunity to examine himself or the witnesses in defence. The Enquiry Officer therefore had given reasons for his findings and submitted the report. For all these reasons I find that the enquiry which was held against the workman was just and proper. The workman was given full and sufficient opportunity to defend himself. The issue is answered accordingly.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3224-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिनियम 2, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-12011/47/90-आई.आर.(बी.-2)]

वी० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 18th October, 1994

S.O. 3224.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal 2, Bombay as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of India and their workman which was received by the Central Government on 18-10-94.

[No. L-12011/47/90-IR(B.II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer

REFERENCE NO. CGIT-2/42 OF 1990

Employers in relation to the Management of Bank of India.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri L. L. D'Souza, Representative.

For the Workmen.—Shri D. P. Patil, Representative.

STATE : Maharashtra

INDUSTRY : Banking

Bombay, dated 16th September, 1994

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, by its letter No. L-12011/47/90-I.R.(B-II) dated 13-12-1990 refer to the following Industrial dispute for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act. It is in the following words :

"Whether the action of the management of Bank of India in relation to its main Branch at Solapur in treating all workmen on the Solapur main Branch to be on strike on 21-11-86 is justified ? If not to what relief the workmen are entitled to ?".

2. After receipt of the claim, the parties were duly served. The Workmen filed their claim through The Bank of India Employees Union, Solapur. The Workmen contended that the management, without any lawful justification, treated the workers to be on strike on 21-11-1986. Their pay was wrongly deducted on that day and they are entitled to back salary of that day.

3. The management opposed the claim by its written statement at Exh. 3/M. It is averred that the workers striking themselves from duty on 21-11-1986 were lawfully justified. Their action was in a strike. The management is justified in deducting the salary of the workmen on that day.

4. On 16-9-94, the General Secretary by pursals at (Exh. 8/W) informed the Court that the President of the Bank

of India Employees Union, Sholapur has conveyed that they are not interested in pursuing the matter. A xerox copy of the telex message is also produced along with the purshis. The Bank has no objection for disposing of the matter.

5. After perusal of the purshis and the telex message, I do not find that anything has remained to be done in this matter. The dispute does not survive. Hence I pass the following order :

ORDER

1. The reference is disposed of for want of prosecution.
2. No order as to costs.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1994

का.मा. 3225.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबन्धन के संरक्षित नियोजकों और उनके कर्म-कारों के बीच, अनुबंध में निरिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 2, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[पंजा एन-12012/617/87/डीII(ए)—प्राई आर. (बी-2)]
वा. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 18th October, 1994

S.O. 3225.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of UCO Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 18th October, 1994.

[No. L-12012/617/87-D.II(A)/IR(B.II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT:

Reference No. CGIT-2/41 of 1983

Employers in relation to the Management of United Commercial Bank.

AND

Their Workmen

APPEARANCES:

For the Employers—Shri V. P. Vaidya, Advocate

For the Workmen—Shri Umesh Nabar, Advocate

Bombay, the 30th September, 1994

AWARD

PART-I

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by its letter No. L-12012/617/87-D.II(A) dated 2nd October, 1988 has referred to the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication. It is in the following terms:

“Whether the action of the management of United Commercial Bank in dismissing the services of Shri P. J. Machhigar, Asstt. Cashier is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?”

2. Mr. P. J. Machhigar, joined the services of UCO Bank i.e. the Employers as a Sub-staff, Peon in the year 1975. He was promoted as Assistant Cashier in the year 1977.

3. The workman was working in the Nariman Point Branch on 3rd May, 1982. On the same day, he opened an account in the name of one Shri S. R. Kadam having a saving account No. 5461 by depositing Rs. 40. On 4th May, 1982, a cheque of Rs. 20,000 was deposited in the said account. On 6th May, 1982, and on 10th May, 1982 Rs. 6,000 and Rs. 14,000 were withdrawn from the said Account. On 20th May, 1982 a complaint was lodged against the workman with the Colaba Police Station by the Manager of the said Nariman Point Branch of the UCO Bank, wherein it was alleged that the workman had committed a fraud of Rs. 20,000 and withdrawn the said amount. He was arrested on 21st May, 1982 and was released on bail on 23rd May, 1982.

4. On 31st May, 1982, the workman was served with the order of suspension with immediate effect subject to the result of pending of criminal case. He was then tried by the Metropolitan Magistrate on 25th March, 1994. He was acquitted.

5. The workman asked for re-instatement in service. Instead of that, his suspension continued and a departmental enquiry was held against him. It is alleged that in the said departmental enquiry he was not allowed to be represented by or through an Advocate, the necessary documents were not given to him before the Advocates or over that he was not given the opportunity to cross-examine the witness thoroughly and lead evidence and that he was subjected to undue influence for admitting his guilt. He submitted that the whole process of the domestic enquiry was against the principles of natural justice.

6. The workman pleaded that the Enquiry Officer found him guilty, reported the matter to the disciplinary authority and then he was terminated from the services. No opportunity was given to him to give his say and reasons for coming to that conclusion. He submitted that it is against the principles of natural justice and the whole enquiry was improper. It is alleged that the punishment which is awarded to him is disproportionate to the acts committed by him. It is averred that under similar circumstance the management had taken a lenient view and it is discriminatory between the two of them and it is not permissible. It is further submitted that the workman has tried for the same offence twice and which the law prohibits. He therefore claimed that his dismissal order may be set aside and he may be re-instated with continuity in service with full back wages.

7. The management opposed the claim by their written statement at Exh. M/3. It is asserted that the whole departmental enquiry was as per law, the principles of natural justice, and as per the Bipartite Settlement. The permission to be represented through an advocate was rejected. It is averred that all the documents as required were given to the worker and he was represented by one Shri Jha, the Union Leader and full opportunity was given for cross-examination and for leading evidence. It is averred that the charges which are proved against the workman are of grievous nature and the punishment which is granted to him is just and proper. It is submitted that there is discrimination between the two workers. It is asserted that there is no substance in the statement that the Enquiry Officer was of bias mind and that he was not a fit person to act as an Enquiry Officer. It is submitted that the acquittal in the criminal case and the laws against him had nothing to do with the departmental enquiry. It is averred that the claim of the workman is liable to be rejected.

8. My Learned Predecessor framed issues at Exh. 4. The first three issues are decided to be treated as preliminary issues. The issues and my findings thereon are as follows :

ISSUES

FINDINGS

1. Whether the Inquiry against the workman Shri P. J. Machhigar was necessary in view of his acquittal in the criminal case lodged against him by the Bank management? In the affirmative.
2. Whether the Inquiry Officer had NO a bias against the workman, and was not fit person to act as an Enquiry Officer?

ISSUES

3. Whether the inquiry held against the said workman was not held properly, that the rules of natural justice were not followed and he was not given sufficient and proper opportunity to defend himself?

FINDINGS

In the affirmative.

REASONS

9. To Bolster up the case the workman had examined himself in Exh. W/6. He is supported by Shri M. Jha (Exh. W/8) who represented his case in the domestic enquiry. As against this Shri Vishwanath Balakrishna Kuikarni (M/9) Presenting Officer of the management lead evidence for the management. The enquiry Officer Shri S. A. Samant admittedly died on 31st August, 1988. It is therefore he could not be examined by the management.

10. It is not in dispute that the Branch Manager gave a complaint to the Colaba Police Station against the workman and which was registered under section 379, 468, 467, 471, 381 & 420 of the Indian Penal Code. This itself goes to show that the management in his mind was of the feeling that the workman had committed serious blunder, flaw and tried to cheat the management. After his acquittal, when the domestic enquiry was started, the workman gave an application for allowing him to be represented by or through an Advocate (Exh. F of the claim). His request was rejected by the disciplinary authority by the letter (Exh. G). It can be seen that the disciplinary authority had not given any reason for rejecting the prayer. What is mentioned therein is that the application is rejected as the Bank's policy does not or is not to permit representation to a charged employee through an Advocate in the departmental enquiry. Again the workman gave an application to the Appellate Authority for giving him permission for the appointment of an Advocate. He had mentioned in his applications that the charge-sheet which was served on him is of a serious nature and if proved is likely to effect him adversely. It can be seen that the Appellate Authority by its letter (Exh. L) informed him that no permission can be granted to him for engaging an Advocate. It endorsed the decision of the disciplinary authority.

11. It is not in dispute that in the Bipartite Settlement it is mentioned that the management may let the charge sheeted workman to be represented through an Advocate. It is well settled law that when there are charges of serious nature it is necessary that the workman should be allowed to be represented through an Advocate. I have already said that the charges which were levelled against the worker were of a serious nature and that he should be allowed to be represented through an Advocate. It is not that there is no provision in the Bipartite Settlement for appointment of an Advocate. It is tried to argue that as the management was not represented by an Advocate, the workman was also not represented by an Advocate. This reasoning is fallacious and not acceptable.

12. So far as giving of copies of the necessary documents to the workman or the concerned Shri Jha and the workman himself in the cross-examination admitted that they received the same before the evidence was lead. On this ground, it cannot be said that the enquiry was unjust.

13. The Presenting Officer admitted in his cross-examination that the workman did not admit his guilt by the letter in his presence. On page 115 of the enquiry proceeding, which was before the Tribunal the Branch Manager of the Nariman Point Branch, admitted that the confession was given by the workman on the assurance that he will be let off. It is argued that as this was the assurance, he admitted the guilt and this fact was not taken into consideration by the enquiry officer or the disciplinary authority and they continued with the assumption that the workman admitted the guilt and gave their conclusion on its basis. In other words, it has to be said that the management used undue influence over the workman for admitting the guilt which is definitely against the principles of natural justice. Under this circumstance, it has to be said that the enquiry was not just and proper.

14. From the evidence which is lead by the workman, by no stretch of imagination it can be said that the enquiry Officer had a bias mind against the worker. I do not find any reason for coming to the conclusion that the Management was incorrect to hold enquiry against the workman. Nothing is brought to my notice, by which it can be said that as the workman was acquitted in a criminal case no departmental enquiry could be held against him. The management was perfectly justified in starting the enquiry. It can be seen further that the acquittal which was given to the workman was because the prosecution did not lead any evidence in the matter. For all these reasons, I record my findings on the points accordingly and pass the following order:

ORDER

1. The management is justified in starting the enquiry (domestic enquiry) against the workman. Even though he was acquitted in a criminal case.
2. The Enquiry Officer had no bias mind against the worker and he was a fit person to hold the enquiry.
3. The procedure adopted at the time of holding the enquiry was against the principles of natural justice and the workman was not given a proper opportunity to defend himself.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1994

का.प्र. 3226: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुमरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ बड़ोदा के प्रबंधन के संवद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 2, बम्बई के पंचरट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/253/89/डी II (ए)/आई. आर. (बी-2)]

वा. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 18th October, 1994

S.O. 3226.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal 2, Bombay as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 18-10-1994

[No. L-12012/253/89-DII(A)/IR(B.II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT:

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/49 of 1989

Employers in relation to the Management of Bank of Baroda

AND

Their Workmen.

APPEARANCES:

For the Employers: Mr. S. K. Talsania, Advocate.

For the Workmen: Mr. A. P. Kulkarni, Advocate.

Bombay, dated 28th September, 1994

AWARD PART-I

Shri V. S. Pradhan, the workman was employed with the Bank of Baroda as a Cash Controller with effect from 27th July, 1972. On 25th September, 1985, he was suspended pending departmental enquiry. He was charge-sheeted on 9th December, 1985. It was alleged that he supplied inaccurate information, claimed leave fare concession for his mother, by making false declaration that she was dependent on him, that the workman had engaged in Milk Business and that the workman sold the flat purchased by him availing loan from the Bank without obtaining Bank's permission and did not liquidate the loan after selling the flat.

2. Shri M. M. Shettigar was appointed as the Enquiry Officer to hold a domestic enquiry of the workman. The workman gave his explanation, but it was found to be unsatisfactory.

3. Therefore the domestic enquiry was held and ultimately most of the charges were proved and one charge was partly held to be proved. Therefore after hearing the workman, he was terminated from the services.

4. The workman raised an industrial dispute and thereafter the Central Government by its order dated 24-11-1984 referred the industrial dispute under section 10(1)(D) of the Industrial Disputes Act of 1947 to this Tribunal for adjudication in the following words:

"Whether the action of the management of Bank of Baroda in dismissing from service Shri V. S. Pradhan was justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

5. The workman, while submitting his claim stated that he was not given the proper opportunity. He was not allowed to be represented through an Advocate, certain documents were produced after the enquiry was completed. Further he had no opportunity to cross-examine the witnesses and lead evidence in respect of those documents and that the whole enquiry against the principles of natural justice. He further submitted that looking to the charges, the punishment which was awarded to him is disproportionate.

6. The management while filing the claim of the worker asserted that the workman was given full opportunity in the domestic enquiry, the whole procedure was just and proper. It is asserted that there was no reason for the workman to say that the principles of natural justice were not followed. It is averred that there is no substance in the claim of the worker and therefore it may be dismissed.

7. My Learned Predecessor framed issues (Exh. 4) for determination. Thereafter the application was moved by the management to decide the first four issues which the Presiding Officer was pleased to announce. As such, I have to decide the first four issues as preliminary issues. The issues and my findings thereon are as follows:—

ISSUES

FINDINGS

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Whether the enquiry held against the workman Shri V. S. Pradhan was not held fairly and properly, and the rules of natural justice were not followed? | In the affirmative. |
| 2. Whether Shri M. M. Shettigar had conducted the preliminary enquiry against the said workman? | In the negative. |
| 3. If so, was he competent to conduct the regular enquiry against him? | Does not survive. |
| 4. Whether the findings of the said Enquiry Officer are perverse? | Does not survive |

REASONS

8. Shri V. S. Pradhan (Exh. 7/W) affirmed as per his statement of claim. He affirmed that even though he prayed for allowing him to be represented by an Advocate, his prayer was rejected. Mr. M. M. Shettigar (Exh. 9/M) the Enquiry Officer affirmed that the application which was given by the workman for the appointment of an Advocate in the domestic enquiry was rejected by the Disciplinary Authority.

9. It is argued on behalf of the workman that the workman was not given the Assistance of an Advocate, when the charges were of criminal and grievous nature. According to

him, it being so, he should have been allowed to be represented through an Advocate. It is not in dispute that the charge is dated 9-12-1985. At the initial stage, the facts are mentioned regarding the misdeeds of the workman and then the charges are mentioned. It states that:

1. You did acts prejudicial to the interest of the Bank.
2. You have been engaged in business outside the scope of the duties without obtaining written permission of the Bank.
3. You did acts of fraud.
4. You did acts showing lack of integrity and honesty.
5. You did acts unbecoming of a bank employee.
6. You made or attempted to make wrongful gain to yourself, causing or attempting to cause corresponding loss to the Bank.

So far as the charge Nos. 3 and 6 are concerned, it relates to criminality. By one charge the workman had said to have committed fraud and by another wrongful loss to the Bank and wage gain to the workman. As this is so, relying on the different authorities, it is submitted that he should be allowed to be represented by the Advocate. In Bank of Baroda v/s. Prabhakar Bokde writ petition 2404 of 1991, in Saraswat Co-operative Bank v/s. their workman THEIR LORDSHIPS in reference CGIT No. 19 of 1986 have held that the facts that the complainant has involved in the criminal charges which are of serious nature then in that case the Enquiry Officer should have allowed or permitted the Workman to be represented through an Advocate.

10. As against this the management relied on *Crescent Dyes and Chemicals Ltd. v/s. Ram Naresh Tripathi* 1992 (3) argued that the delinquent has no right to be represented through Counsel or agent, unless the law specifically confers such a right. The requirement of the rule of natural justice in so far as the delinquent's right of hearing is concerned, cannot and does not extend the right to be represented through a Counsel or an agent. It appears that in that case, rules did not provide for allowing an Advocate to be engaged in a domestic enquiry. The procedure to be followed at the enquiry in respect of the following subject is governed by the conditions of the Bipartite Settlement para 19.12 of it provides the conditions. It states that the employee against whom the discrimination is proposed should be allowed to be represented by a lawyer unless with the permission of the management. It means, the Advocate can be appointed with the permission of the management. I am allowing him to be represented by an Advocate which was rejected. Under such circumstance, the principles laid down in the above said authority has no application. As the charges levelled against the workman are of a serious nature as observed in Bokde's case, the workman should have been given an opportunity to be represented through the Advocate, as it is not done, the principles of natural justice are not followed and the enquiry is said to be incorrect.

11. It is not in dispute that the workman himself continued to proceed with the enquiry, without taking assistance of the Union. It is not in dispute that he cross-examined the witness, but I have come to the conclusion that he was precluded from the appointment of an Advocate to represent him. In result it has to be said that he could not defend himself in a proper way. The contention of the workman that he asked for the production of certain documents 48 in numbers and the Bank did not produce all the 48 documents had carried a mis-carriage. I am not inclined to accept that. It can be seen that out of that 48 documents, 33 documents were produced and the remaining 15 documents appears to be totally irrelevant. The management had not relied upon them also. The workman could not show the documents which were not produced on the record had lead to injustice.

12. It is tried to submit that the Enquiry Officer had earlier held preliminary enquiry against the workman and therefore the said Enquiry Officer would not have acted as the Enquiry Officer. On 13-1-1986, the Enquiry Officer gave a notice to the workman, that he was appointed as the Enquiry Officer and a preliminary hearing will be held at 9.00 a.m. on Saturday the 25th January, 1986. It appears that the workman had mis-understood the word preliminary hearing to that of preliminary enquiry and had raised an objection regarding the charge of the Enquiry Officer to hold a domestic enquiry. The proceedings which took place on 25-1-1986

5. Written statements filed by the management in both the disputes were more or less on identical terms. It is contended that the nature of job of a Pigny Deposit Collector is just like that of an agent. It was on the basis of contractual agreement. If there was any kind of violation of agreement by the Agents, management is within their right to terminate their services. They can effect termination by invoking Clause 7 of the agreement executed at the time of appointment of these workmen as Agents. If the revocation of the agency was in contravention of the agreement/contract of agency, the workmen could have sought remedy in a civil court for the enforcement of contract or for damages.

The management had also highlighted various points which will make distinction between the nature of job and details of service condition in so far as regular employees under the Bank and the Agents like the Pigmy Deposit Collectors. Therefore, according to them, there is nothing illegal in terminating the agency with the workmen by invoking the provisions of contractual agreement. Regarding the plea for reinstatement of the workmen in service it is contended that the Banking Regulation Act of 1949 does not empower any Court or Tribunal in giving direction to employ them in the services of the Bank. Therefore plea is made by them to sustain the termination orders effected in the case of workmen.

6. In the course of evidence management had produced the order of appointment, the notice of termination of agency (Ext. M8), the contractual agreement and indemnity bond executed by the workmen. On the side of the workmen, the Pigmy deposit scheme formulated by the management is produced (Ext. W1). The Chapter V relates to the Rules and Regulations framed by the management regarding Pigmy deposits and appointment of Pigmy Deposit Collectors. In Clause 5.2.1 it is stated that for the specific purpose of canvassing accounts and collecting contributions from the customers on behalf of the Bank, representative viz., Pigmy Collectors are to be appointed. In the procedure for appointment it is stated that the candidates shall apply to the Branch in whose jurisdiction he/she intends to work enclosing two copies of his latest passport size photographs (5.2.5). After scrutiny of the application, the appointment order would be given in triplicate in form PC-IA B&C. The Pigmy Collectors so appointed have to keep with them identity cards, issued by the management.

7. These terms and conditions prior to the appointment of Pigmy collectors will show that there are certain essential formalities for compliance not only in the matter of appointment but also in the subsequent works to be done by the Pigmy Deposit Collectors.

8. Identical nature of dispute was adjudicated by this Tribunal in an earlier reference by the Government of India and that is in I.D. No. 17/92. (Syndicate Bank Vs. G. Sasikala). The award of this Tribunal dated 18-7-1994 was published by the Government by the Notification dated 18-8-1994. Since identical issues were raised considered and decided, the rational contained in earlier award of this Tribunal is equally applicable in these two disputes also. In order to avoid repetition in the matter of evidence and conclusion reached, it would be relevant to extract some of the passages from the above referred award of this Tribunal.

"5 The management bank in this dispute raised a preliminary objection against the very maintainability of the dispute. According to them a Deposit Collector who was appointed in terms of Ext.M2 order will not come under the definition of 'workman' as defined in the I.D. Act and therefore any dispute relating to such person cannot be treated as an industrial dispute. Whether a person who had been rendering service to an employer establishment on commission basis can be treated as a workman or not was subject to judicial scrutiny by various higher Courts including the Supreme Court.

6. The term 'workman' is defined in the I.D. Act as a person who is employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward whether the terms of employment be expressed or implied. Here, in this case, the work of a deposit collector is for reward at the rate fixed in Ext.M2 order. As a deposit collector the worker has to do operational or clerical work connected with the job entrusted to her. Merely because she was receiving commission on pro rate basis with reference to the total amount collected, she will not go out of the purview as contended by the management. The work which has to be done is strictly as per the terms of appointment and under the control of the Branch Manager. In

State of Assam v. Kanak Chandra Dutta (1968) 1 LLJ 288) the Supreme Court held that remuneration could be by way of commission or collection also. It was held that the post outside the regularly constituted service need not necessarily carry "a definite rate of pay" and it can be by way of a commission or collection of Government dues also, therefore, the position is that even if a commission is received for the service rendered, that will be termed as hire or reward within the meaning of Sec. 2(s) of the Industrial Disputes Act defining the term "workman".

Now let us see the nature of work to be done by the worker concerned. She had to make deposits from the customers to the Bank regularly in accordance with the mutually agreed terms and conditions. She had to render true and correct account of the deposit collected. The deposit collected shall be accounted at the specified branch on the next working day itself. She had to use Bank stationery for all work connected with deposit collection. She had to maintain the register regarding the collection which has to be duly verified by the Branch Manager or the authorised Officer. Therefore, the position emerges is that in a different method or working arrangement, deposit collections are being made by the Bank. Instead of customers directly coming to the Bank and making deposit, the Bank itself through their agents like Pigmy Deposit collectors goes to the customers and receive deposits. No doubt, that is for and on behalf of the Bank. Such kind of arrangement itself is to attract customers and to achieve maximum deposit from the willing depositors. Therefore the nature of work which had been done by these agents is almost identical with the works which are performed by the official of the Bank. But the only difference is that the deposits are accepted outside the premises of the Bank. In view of this arrangement for mobilising maximum deposit, the persons rendering service for such deposit mobilisation are also to be treated as part of the establishment. Only difference is that when regular staff are assured on regular hire or reward every month, this deposit collectors are entitled for remuneration only on the basis of the quantum of work done and the gain achieved out of that. Merely because they are not rendering service to the Bank in a systematic and regulated atmosphere, it cannot be said that they are not rendering service for hire or reward for work connected with the work of the establishment. Therefore, I hold that this Adarsh Deposit Collectors will also come under the definition of 'workman' as defined in the I.D. Act. The learned counsel for the worker had brought to the notice of this Court a judgment of the Madras High Court in Management of Indian Bank v. Industrial Tribunal, Madras and another [1990 (1) LLJ 50]. In that case the issue raised was also identical. Instead of Adarsh Deposit Collector, the case of a Tiny Deposit Collector was subject to litigation. The Division Bench of the Madras High Court held that the Tiny Deposit Collector will come under the definition of 'workman' and therefore, they are entitled for protection as envisaged in the I.D. Act. Since the facts are identical and terms and conditions for appointment are also similar, the rational laid down by the Madras High Court can be safely applied in the case on hand also.

Since it is held that the worker concerned is entitled for protection of the I.D. Act, now the question to be resolved is whether the termination of her service was in accordance with the provisions of the I.D. Act. The management's case is that her service was strictly in accordance with the terms of contract of employment. It is alleged in the written statement of the Management Bank that agency had to be terminated on account of her negligence and dereliction of duty. But the termi-

nation order Ext. W2, does not contain any such allegation. It is only stated therein that the Pigmy Agency was terminated with immediate effect. That order is dated 5-8-1988. The appointment order Ext. M2 is dated 4-5-1979. It is evident from Ext. W2 and Ext. M2 that for about 11 years she was working as the deposit collector in the Bank. So long as there is no case of the management bank that she does not have 240 days of continuous service in the year immediately preceding the date of her termination, it can only be held that she had satisfied all conditions for getting the terminal benefit as contemplated in Sec. 25-F of the I.D. Act. Evidently and admittedly before effecting termination in her case, none of the formalities contemplated in the I.D. Act were complied with by the management bank. Therefore, the termination effected in her case can only be held as invalid and inoperative. She is entitled to continue in service till she is validly terminated in accordance with the provisions contained in the I.D. Act. As a consequence of the declaration that her termination was illegal she is entitled for full rate of wages for the period in which she is illegally kept out of service. For the purpose of calculation of her monthly wages the average wages/commission she was getting in a month immediately preceding the year to the date of termination shall be taken into account. From the pleadings of the management it is evident that her services were terminated on account of the dereliction of duty and unauthorised absence etc. If there was such irregularity on the part of the worker it would have been appropriate to issue at least a show cause notice before terminating the service. Having not done anything on that behalf, the contention of the management that the termination was strictly on the basis of contract of agency cannot be accepted."

9. The above conclusions based on the decision of the higher Courts are equally applicable in these two disputes also. In the result an award is passed holding that the termination of service of the workers concerned are illegal and unsustainable. They are entitled to continue as Pigmy Collectors in the same terms and conditions as envisaged in their appointment orders till their services are validly terminated. They are also entitled for back wages. That shall be calculated on the basis of the monthly average wages/commission they were getting in the immediately preceding year to the date of termination of their services.

10. Award is passed accordingly.
(Dated this the 24th day of September, 1994)

K. KANAKACHANDRAN, Industrial Tribunal

APPENDIX

(I.D. Nos 6/92 & 9/92)

I.D. No : 6/92

Witness examined on the side of Management ---

M.W1 : Mohan Daniel.

Witness examined on the side of the Workman ---

WW1 : Satheesan Pillai.

Exhibits marked on the side of the Management:--

M1 : Application submitted by T. P. Satheesan Pillai for appointment of Pigmy Deposit Collector.

M2 : Order of appointment issued by Bank to T. P. Satheesan Pillai.

M3 : Agreement executed by Syndicate Bank and Satheesan Pillai.

M4 : Indemnity Bond executed by K. K. Mohanan. Koovakkad, Palluruthy, Cochin-6.

M5 : Complaint filed by K. P. Bava against the worker.

M6 : Complaint filed by C. K. M. Siddik to the Manager, Syndicate Bank, Kochi.

M7 : Show cause notice dated 19-3-1987 issued by Syndicate Bank to T. P. Satheesan Pillai

M8 : Copy of termination of agency issued by Syndicate Bank to T. P. Satheesan Pillai.

Exhibits marked on the side of the workman:--

W1 : Copy of the Rules & Regulations framed by the management regarding the Pigmy Deposits and appointment of Pigmy Deposit Collectors.

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1994

का.आ. 3228:-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 17) की धारा 17 के अन्तर्गत में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक, मद्रास के प्रबन्धन के संबंध निरोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अन्तर्व्य में निम्न-औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचपद को प्रकाशन करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/179/88 की III (प) आई. आर. (की I)]

वी. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th October, 1994

S.O. 3228.--In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Madras and their workmen, which were received by the Central Government on 18-10-94.

[No. L-12012/179/88-D.III(A)/IR(B.I)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU
MADRAS

Monday, the 22nd day of August, 1994

PRESENT

Thiru K. Ponnasamy, M.A., B.L., Industrial Tribunal
Industrial Dispute No. 16/89

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workman and the Management of State Bank of India, Madras).

BETWEEN

Shri P. S. Ramachandran,
No. 7, Rangier Street,
Thyagaraya Nagar,
Madras-600 017.

AND

The Chief General Manager,
State Bank of India,
I.H.O., 21, Rajaji Salai
Madras-600 001.

REFERENCE :

Order No. I 12012/179/88-D.III(A), dt. 7-2-89. Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi.

This dispute come on this day for final disposal in the presence of Tvl. T. S. Gopalan P Ibrahim Kalifulla S. Ravindran and N.C. Srinivasa Varadhan, Advocates appearing for the Management, upon perusing the reference, claim and counter statements and other connected papers on record, and the workman being absent, this Tribunal passed the following :

AWARD

This dispute between the Workman and the Management of State Bank of India, Madras arises out of a reference by Government of Tamil Nadu for adjudication of the following issue:

"Whether the Management of State Bank of India Madras is justified in dismissing without notice the services of Shri P. S. Ramachandran, Head Clerk w.e.f. 15-04-1986? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

Now the time is 3.15 p.m. There is no representation for the petitioner. Petitioner's Counsel is absent. Petitioner is called. He is absent. This Industrial dispute is posted today for enquiry as last chance. Hence this Industrial dispute is dismissed for default. No costs.

Dated, this the 22nd day of August, 1994.

THIRU K. PONNUSAMY, Industrial Tribunal.

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1994

का. आ. 3229.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास के प्रबन्धन के संयुक्त नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-41012/88/89-आई आर (डीयू)/बी I]

श्री. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th October, 1994

S.O.3229.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Integral Coach Factory, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on 18-10-94.

[No. L-41012/88/89-IR(DU) B.I.]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU, MADRAS

Wednesday, the 27th day of July, 1994

PRESENT :

Thiru K. Ponnusamy, M.A.B.L., Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 73/90

"(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workman and the Management of Integral Coach Factory, Madras).

BETWEEN :

Shri T. P. Krishnaswamy,
5/23, Vasantha Garden Street,
First Lane,
Madras-600 023.

AND

The General Manager,
Integral Coach Factory,
Madras-600 023.

Reference: Order No. L-41012/88/89-IR(DU), dated 23-8-90, Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Wednesday, the 29th day of June, 1994 upon pursuing the reference, Claim and Counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru R. Lawrence, Advocate appearing for the workman and of Thiru B. T. Seshadri, Advocate appearing for the Management, and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

This reference has been made for the adjudication of the following issue :

"Whether the Management of Integral Coach Factory, Madras is justified in terminating the services of Shri T. P. Krishnasamy, Khalasi? If not, what relief the concerned workman is entitled to?"

2. The claim of the petitioner briefly stated is as follows :

The petitioner entered into the service under the respondent as Mali on 13-10-1965. He was posted as Khalasi in Shop-10 under the respondent. Due to his mental disorder, he gradually lost his memory power. He was roaming aimlessly at various places. His brother-in-law traced him and brought him to his residence. He took some native treatment. He was informed by his co-workers that he was removed from service. He sent a letter dated 22-2-1984 to the Works Manager M.II/Shell, Integral Coach Factory (hereinafter will be referred as I.C.F.) requesting him to supply copy of charge sheet, enquiry proceedings and penalty advice, the finding of the Enquiry Officer since they were not supplied to the petitioner. But copy of the charge sheet, enquiry advices, and enquiry proceedings were not supplied to the petitioner. He preferred an appeal dated 26-12-84 to the Additional Chief Mechanical Engineer. The Deputy Chief Mechanical Engineer/Shell, ICF, has not received any reply from the Appellate Authority. He approached the Deputy Chief Mechanical Engineer's office several times. But he was informed that his file is with the Appellate Authority. He approached the Regional Labour Commissioner (Central) Madras in 1984 for conciliation proceedings. But he was advised to take up his matter through permanent negotiating machinery which is functioning in railways. Hence he was unable to submit his application for conciliation proceedings in time. He filed his application dated 31-10-1988, before the Assistant Labour Commissioner (Central-I), Madras under Section 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947 challenging his removal from service with effect from 22-2-83. Conciliation notice was issued to both the

petitioner and the respondent fixing conciliation proceedings on 6-4-89 and 2-5-89 and on both the occasions respondent failed to attend. The petitioner attended the conciliation proceedings. The Assistant Labour Commissioner (Central-I) issued failure report dated 2-6-89 and letter to Central Government Industrial Tribunal dated 23-8-90 of the Ministry of Labour, New Delhi. He was removed from service with effect from 9-7-83. In the ex parte enquiry no notice was taken by the Enquiry Officer. The findings of the Enquiry Officer are vitiated as per Rule 9(17) of the Railway Service (Discipline and Appeal) Rules, 1968. The finding of the Enquiry Officer is perverse. The Enquiry proceedings conducted against the petitioner is arbitrary. The removal of the petitioner from service is illegal and unlawful and against the canons of natural justice and as such he is entitled to be reinstated in service with effect from 9-7-83.

3. The defence of the respondent briefly stated is as follows :

The petitioner absented himself from duty for 133 days from 18-5-81 to 30-9-81. The petitioner's absence was not covered by proper medical certificate nor did he get prior sanction of leave. Charge sheet dated 9-2-82 was issued to the petitioner to submit his explanation. The reference to the imputation of the charge is unauthorised absence from duty. The charge sheet dated 9-2-82 was sent to the petitioner to the address given by him to the respondent. The said address was the last known place of residence of the petitioner. Article 1 of the charge sheet relates to the absence of the petitioner from duty. In the aforesaid charge sheet, communication dated 9-2-82 was sent to No. 19B, Vasantha Garden Street, Ayanavaram, Madras-600 023 which is the address which has been given by the petitioner. The said letter was returned with the endorsement 'left'. No reply was received from the petitioner. Notice dated 21-10-82 fixing the enquiry was sent to the petitioner. That communication was also returned with endorsement 'No such person'. The Enquiry Officer called for the records and found from the records that the petitioner absented himself from duty from 18-5-81 to 30-9-81. The absence of the petitioner from duty is supported by the written report of the Time Superintendent/Shell. Gate attendance card of the petitioner, was also examined. It was found that no pay was drawn for the aforesaid period. The records do not show any prior sanction of leave on account of medical grounds. The Enquiry Officer came to the conclusion that the absence of the petitioner from duty during the relevant period was unauthorised. A copy of the enquiry findings was sent to the petitioner which was returned with the endorsement, 'No such person'. Order of removal dated 4-7-83 was issued to the petitioner that he was removed from service with effect from 9-7-83. No appeal was filed against the orders of petitioner's removal from service. A letter from the Ministry of Railways, New Delhi issued by the Ministry of Labour, regarding the reference of the matter to the Industrial Tribunal for adjudication was received. Then only respondent became aware that the petitioner has challenged the order of 2471 GI/94-16.

removal from service. The order of removal of the petitioner from service is not liable to be set aside as the enquiry was conducted in a fair and proper manner. The absence of the petitioner from duty and he did not get prior sanction of leave not he produced any medical certificate is not disputed. The only conclusion that could be reached is that the absence of the petitioner from duty was unauthorised. Notice of the enquiry was sent to the petitioner and the cover was returned with the endorsement 'No such person'. All the communications were sent to the aforesaid address. When the communication was returned on the ground that such person was not available, the respondent had no other option but to proceed with ex parte enquiry. The Enquiry Officer considered the records produced before him. The records show that the petitioner absented himself from duty during the aforesaid period and his absence was not supported by any medical certificate or leave certificate so the petitioner was rightly removed from service. The Enquiry Officer came to the conclusion that the absence of the petitioner was unauthorised. The removal of the petitioner from service is based on the findings of the enquiry officer, is perfectly valid. The allegation that due to the mental upset the petitioner lost his memory before and was roaming aimlessly at various places is false. The allegation that his brother-in-law traced him and brought him to residence and the petitioner took some native treatment, is false. The respondent is not aware of the aforesaid allegations. Even assuming without conceding that the copies of the documents have not been supplied after the order of removal from service would not in any way vitiate the findings of the Enquiry Officer. The allegation that the enquiry findings and enquiry proceedings have not been supplied to the petitioners is meaningless and unwarranted. The allegation that the petitioner had sent an appeal dated 26-12-84 addressed to the Additional Chief Mechanical Engineer is false. No such appeal was received by the Appellate Authority. The allegation that the petitioner approached the Deputy Chief Mechanical Engineer's office many times, is false. The allegation regarding the conciliation proceedings, is false. No communication was received from the Regional Labour Commissioner regarding the alleged conciliation. There was no conciliation proceedings and as such the failure to send the report does not arise. The matter has been referred to this Tribunal. The respondent received a communication from the Ministry of Labour. The allegation that no documents were marked, and relied upon, is false. All the documents were produced before the Enquiry Officer and he relied upon the documents, produced before him. Oral evidence is not necessary since the matter is supported by documents and the Enquiry Officer looked into the records and his findings that the petitioner unauthorisedly abstained himself from duty is supported by records. It is not the case of the petitioner that he was present during the aforesaid period. The petitioner's absence from duty was not covered by medical certificate or by prior sanction of leave. The petitioner evaded to receive the notice. It is not open to the petitioner to challenge, and say that no opportunity was given to him to participate

in the enquiry. The claim of the petitioner is unsustainable.

4. The point for determination is: "Whether the Management of Integral Coach Factory, Madras is justified in terminating the services of Shri T. P. Krishnaswamy, Khalasi? If not, what relief the concerned workman is entitled to?"

5. The Point: The petitioner served as a Khalasi under the respondent, is borne out by Ex. M. 1. Admittedly the petitioner was unauthorisedly absent from duty from 18-5-81 to 30-9-81 for 133 days without obtaining the prior permission or leave from the respondent. The petitioner's absence from duty in the above said period, is not supported by medical certificate. The address of the petitioner is No. 2, Vasantha Garden, Cinna Sambar, Perambur Pakkam, is made out by Ex. M. 2. The petitioner belongs to Adhi Andhra Community, is evidenced by Ex. M. 3. The petitioner was charge sheeted on 9-2-82 for his unauthorised absence from duty, during the relevant period. Domestic enquiry was ordered and conducted. The domestic enquiry was fixed at 11.00 a.m. on 23-5-83 and notice for the enquiry was sent to the petitioner by Registered Post acknowledgement due, is established by Exs. M. 5 and M. 6 and the notice returned as unserved as there is no such person, is made out by Ex. M. 7. Somebody signed in the postal acknowledgement Ex. M. 8. Notice for the enquiry to be conducted on 28-10-82, was sent to the petitioner by registered post and was not served. Thiru Subramaniam ASS. 20 was nominated as the Enquiry Officer to conduct the enquiry, is borne out by Ex. M. 10. The explanation of the petitioner was called for by the respondent for his unauthorised absence from duty, to the address of the petitioner is borne out by Ex. M. 12 and it was not served on the petitioner, is substantiated by Ex. M. 13. Address of the petitioner was obtained from Assistant Shop Superintendent/Shop No. 21. The notice for the enquiry to be conducted at 2.00 p.m. on 21-10-83 was sent by registered post with acknowledgement due, by the respondent to the address of the petitioner given by the Shop Superintendent, is made out by Ex. M. 14. The notice for the domestic enquiry to the petitioner's last known residential address was sent by registered post with acknowledgement due, is evidenced by Ex. M. 15. If there is any change in the address of the petitioner, it is his duty, to intimate the same, to the respondent. The petitioner failed to inform his last known residential address to the respondent. The petitioner failed to give the reasons and circumstances for his unauthorised absence from duty. Enquiry Officer after carefully considering the documents, Enquiry Officer after carefully considering the documents from the petitioner guilty of the charge levelled against him, is borne out by Ex. M. 15. The petitioner was unauthorisedly absent from duty from 18-5-81 to 23-5-81 and 27-5-81 to 30-9-81 is established by Ex. M. 11. The disciplinary authority after carefully scrutinising the report of the Enquiry Officer and accepting his findings, came to the conclusion that the petitioner is not a fit person to be

retained in service and terminated his service with effect from 9-7-83, is proved by Exs. M. 4 and M. 6. The petitioner was unauthorisedly absent M. 6. The petitioner was unauthorisedly absent from duty, for many occasions, prior to his dismissal from service and 7 punishments were awarded, is borne out by Ex. M. 17. Show Cause Notice should be issued as per amendments to Railway service (Department and Administrative Rules) 1968. Ex-parte domestic enquiry was conducted by the enquiry officer, is evidenced by Ex. M. 18. The petitioner produced the Doctor Certificate Ex. W-1. In Ex. W-1 the date of issue of the same is not stated. The private doctor certificate must be verified and attested by the Railway Medical Officer. The Railway Medical Officer must certify that the petitioner is fit for duty, is evidenced by Ex. M. 19. The petitioner sent the letter Ex. W-3 to the Works Manager-Mechanical-2/S, ICF Madras that he came to understand that he was removed from service. The petitioner was not at Head quarters due to some mental worries, is not proved by any satisfactory and acceptable evidence.

6. The petitioner purposefully evaded to receive the notice for the domestic enquiry and for other purposes, with ulterior motive. Copy of the penalty advice and the copy of the findings of the enquiry officer containing the charge framed against the petitioner were sent to the petitioner by registered post with acknowledgement due, is evidenced by Ex. W-4. The petitioner preferred an appeal against the order of his dismissal from service by the Disciplinary Authority to the Asstt. Chief Mechanical Engineer Shell, Integral Coach Factory, Madras, is evidenced by Ex. W-5. The petitioner sent the petition to Assistant Labour Commissioner (Central) Shastri Bhavan, Madras that he has lost his mental power and his removal from service was informed to him by his co-workers, is made out by Ex. W-6. The petitioner's petition sent to the Assistant Labour Commissioner (Central), cannot be entertained unless, it is accompanied by the Board's direction, is made out by Ex. W-7. Notice was sent to the petitioner to attend the Conciliation Proceedings by the Assistant Labour Commissioner (Central-I), Madras is borne out by Ex. W-8. Notice was sent to the petitioner to attend the enquiry, to arrive at an amicable settlement, was sent to the petitioner by registered post with acknowledgement due by the Assistant Labour Commissioner (Central-I), Madras is borne out by Ex. W-9. The Conciliation failed since the respondent did not attend the enquiry and as such the question of referring the matter for voluntary arbitration or joint reference for adjudication did not arise, is borne out by Ex. W-10. The disciplinary authority accepted the findings of the Enquiry Officer, and passed order terminating the services of the petitioner is borne out by Ex. M-4.

7. If the charge sheet sent by registered post is returned unserved, as the employee was not found in the address, the dismissal of the employee is invalid as held in 1961 1-ILJ SC p 303 BATA SHOE CO. PVT. LTD Vs. GANGULI (D. N. & OTHERS). In the present case, the petitioner purposely evaded to receive the notice and the order of dismissal. So, the aforesaid case has no application to case on hand. The petitioner has not exhausted the remedy

before the Appellate Authority. This Tribunal has no power to reappreciate the evidence and disregard the findings of the Enquiry Officer. This Tribunal is not an Appellate Authority. This Tribunal cannot sit over the findings of the Enquiry Officer. The Enquiry Officer followed, the procedure prescribed by the law, the provisions of the law, the Standing Orders, the principle of natural justice, good conscience and equity. The findings of the Enquiry Officer are based on legal evidence. This Tribunal can disregard the findings of the Enquiry Officer, provided the findings are perverse. The findings of the Enquiry Officer are not perverse and as such this Tribunal cannot interfere with the findings of the Enquiry Officer. The domestic enquiry was conducted properly and fairly. The domestic enquiry is just and proper. The domestic enquiry does not suffer from any infirmity or impropriety. The findings of the Enquiry Officer are not vitiated by any irregularity or any fault or mistake. The domestic enquiry was conducted in accordance with the Standing Orders, the procedure prescribed by law, the provisions of law, principles of natural justice, good conscience and equity. The petitioner was given reasonable opportunity, to participate in the domestic enquiry, cross-examine the witnesses, produce his documents and examine his witnesses and he has not availed the opportunity by evading the service of notice and the order of dismissal. The domestic enquiry conducted by the Enquiry Officer is fair and just. There is no proof that the petitioner is fit for work. The dismissal of the petitioner from service is just and proper. The petitioner was given opportunity to explain the past records of service. The petitioner was requested to come to the office of the Disciplinary Authority and receive one month wages. But the petitioner failed to receive the one month salary. The petitioner evaded the service of the order of dismissal and the copy of the present petition, with ulterior motive. The petitioner was warned twice for his unauthorised absence from duty. The petitioner is unfit to be retained in service. His appeal to the Chief Mechanical Engineer Integral Coach Factory, Madras was dismissed. The unauthorised absence of the petitioner from duty, caused inconvenience to the administration of the respondent. Prima facie case has been made out, against the petitioner. The charge levelled against the petitioner is proved by legal evidence.

8. By taking the aforesaid facts into consideration, this Tribunal comes to the irresistible conclusion that the Management of Integral Coach Factory, Madras is justified in terminating the services of T. P. Krishnaswamy, Kalasi, and the concerned workman is not entitled to any relief. The point is found against the petitioner.

In the result, an award is passed that the Management of Integral Coach Factory is justified in terminating the services of Shri T. P. Krishnaswamy, Khalasi. No costs.

Dated, this the 27th day of July, 1994.

THIRU K. PONNUSAMY, Industrial Tribunal
WITNESSES EXAMINED

For Workman :

W.W.1 : Thiru T. P. Krishnaswamy (Petitioner-workman).

For Management :

M.W.1 : Thiru P. Marachi.

For Workman :

- Ex. W-1 : Doctor Certificate issued to Petitioner-workman.
- Ex. W-2|18-5-1981 : Doctor's Prescription issued to the Petitioner-workman.
- Ex. W-3|22-2-1984 : Letter from Petitioner workman to the Management (Xerox copy).
- Ex. W-4|10-4-1984 : Reply by the Management to Ex. W-3 (Xerox copy).
- Ex. W-5|20-12-1984 : Appeal preferred by Petitioner-workman to the Management (Xerox copy).
- Ex. W-6|31-10-1988 : Petition u/s. 2-A of the I.D. Act filed by the Petitioner-workman before the Assistant Labour Commissioner (Central), Madras-6 (Xerox copy).
- Ex. W-7|11-11-1988 : Reply by the Assistant Labour Commissioner (Central), Madras-6 to Ex. W-6 (Xerox copy).
- Ex. W-8|2-3-1989 : Letter from Assistant Labour Commissioner (Central), Madras-6 to the Petitioner-workman (Xerox copy).
- Ex. W-9|21-4-89 : Letter from Assistant Labour Commissioner (Central-1), Madras to the Petitioner-workman (Xerox copy).
- Ex. W-10|2-6-1989 : Conciliation Failure Report (Xerox copy).

For Management :

- Ex. M-1|2-10-1964 : Application for the post of Garden Khalasi applied by the petitioner-workman.
- Ex. M-2|21-9-1965 : Birth certificate of petitioner-workman issued by Corporation of Madras.
- Ex. M-3|20-6-1961 : School leaving Certificate issued to Thiru T. P. Krishnaswamy (Petitioner-workman) by The Sanathana-dhram School, Agaram, Perambur (copy)
- Ex. M-4|4-7-1983 : Letter from Management to Petitioner-workman.
- Ex. M-5|10-5-83 Enquiry Notice enclosing returned cover and acknowledgement card addressed to the Petitioner-workman.
- Ex. M-6|10-5-1983 : Enquiry Notice issued to Petitioner-workman.
- Ex. M-7 : Returned cover addressed to the Petitioner-workman.
- Ex. M-8 : Returned acknowledgement card addressed to the petitioner.
- Ex. M-9|21-10-1982 : Order of Assistant Works Manager for appointment of Enquiry Officer.
- Ex. M-10|11-9-1982 : Office note regarding conduct of enquiry against petitioner-workman.

- Ex. M-11 : Statement of Articles of charges framed against petitioner-workman (copy).
 Ex. M-12/9-2-1982 : Charge sheet issued to Petitioner-workman.
 Ex. M-13 : Returned cover addressed to Petitioner-workman.
 Ex. M-14/9-2-1983 : Enquiry Notice issued to Petitioner-workman.
 Ex. M-15/24-5-1983 : Findings of the Enquiry Officer.
 Ex. M-16/4-7-1983 : Order of removal issued to Petitioner-workman.
 Ex. M-17/9-8-1989 : Letter from General Manager, I.C.F., to the Secretary Railway Board, New Delhi (copy).
 Ex. M-18/26-5-1983 : Office Note.
 Ex. M-19/12-2-1989 : Circular issued by General Manager (P), I.C.F., Madras-38 (Xerox copy).

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1994

नं. ए. 3230.—आयोगिक विवाद अधिनियम, 1917 (1917 में 11) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नरसी नाट प्रेस, नासिक के प्रबन्धन के संबंध में निम्नलिखित आयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार आयोगिक अधिनियम नं. 1, बम्बई के पंजाब का प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 19-10-94 का प्रज्ञा हुआ था।

[महाराष्ट्र एल-16012/9/89-आई आर (डो. यू.)]
 क. वा. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th October, 1994

S.O.3230.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Currency Note Press, Nasik and their workmen, which was received by the Central Government on 19-10-1994.

[No. L-16012/9/89-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
 INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer.
 REFERENCE NO. CGIT-65 OF 1990

PARTIES :

Employers in relation to the management of Currency Note Press, Nasik.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Management.—Shri Masurkar, Advocate.
 For the Workman.—Shri Dharap, Advocate.

INDUSTRY : Security Printing. STATE Maharashtra.
 Bombay, dated the 12th day of September, 1994.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by letter dated 23-8-1990 made following reference for adjudication under Section 10(1)(a) read with sub-section 2A of the Industrial Disputes Act, 1947.

“Whether the action of the management of Currency Note Press, Nasik in terminating the services of Shri L. S. Khode token No. 525 w.e.f. 9-11-87 is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled to?”

2. It is an admitted position that Shri Khode was an employee of the Currency Note Press having joined on 14-6-1960. He owns a Chawl at Nasik, wherein one Smt. Pushpa Wamanrao Sonar has been residing. On 22-3-1983, an incident took place for which Pushpabai and her daughter Minakshi filed complaint for an incident of assault on her. Shri Khode was tried before the Chief Judicial Magistrate, Nasik, who convicted him alongwith others under Section 323 read with Section 34 of the Indian Penal Code and sentenced him to pay fine of Rs. 300 in default to suffer rigorous imprisonment for one month. He was also convicted under Section 324 read with Section 34 of the Indian Penal Code and Sentenced to pay fine of Rs. 800 in default to suffer rigorous imprisonment for one month. He was acquitted however, for offences punishable under Section 504, 506 read with Section 34 of the Indian Penal Code. Out of the amount of fine realised Rs. 400 were to be given to the complainant Smt. Pushpabai as compensation.

3. This order was challenged in an appeal, Learned Additional Sessions Judge dismissed the same. He preferred a Criminal Revision Application in High Court and as copy of the order shows the High Court maintained the order of conviction but instead of sentencing him ordered him to be released on probation.

4. The management, however, considering the order of conviction and the decision in appeal gave him show cause notice and passed an order of removal from service on 9-11-1987.

5. According to him, on 20-11-1987 he had informed the management through his advocate Shri S. S. Jajpe to grant an opportunity to him and informed the management of the pendency of Criminal Revision Application in the High Court and requested the management to reinstate him.

6. He submitted a demand for reinstatement on 28-12-1987 and thereafter approached the Asst. Labour Commissioner. The conciliation efforts failed and reference has come to be made to this Tribunal for adjudication.

7. He has contended that there has been a violation of provisions of Section 23N of the Industrial Disputes Act, that there has been violation of provisions of the Industrial Model Standing Orders and that penalty of termination of services is disproportionate.

8. Management has filed written statement. It has been contended therein that he was found guilty and also fined Rs. 800 by the Chief Judicial Magistrate and the appeal to the Session Court came to be dismissed. It is admitted that Shri Khode has sent the reply to the show cause notice stating that he had filed a Revision Application bearing No. 474 of 1986 in the High Court. He however, did not produce any additional information deserving consideration. Because he had been convicted of a criminal offence which is unbecoming of a Government servant as per Government of India Instruction No. 2 under rule 19 of C.C.S.(C.C.A.) Rules 1965 he was removed from service by office order dated 9-11-1987.

9. It is thereafter, stated that the fact of conviction was concealed by the Applicant and this act of applicant violated the provision of C.C.S. (Conduct) Rules. He was given an opportunity of making representation on the penalty proposed by the show cause notice dated 8-9-1987. He did not give reply to the show cause notice and also failed to appear for preliminary enquiry. He was then given an opportunity to plead his case and to produce material with a view to decide the quantum of punishment, but he failed to appear and failed to produce necessary documents. It is then stated that the employees are governed by C.C.S.(Conduct) Rules and since he was involved in a criminal case, this attracted provision of Rule 19 of C.C.S. Rules and according to these rules and Government of India instructions he had committed cognizable offence and attracted dismissal from Government service. The action of his termination from Government service therefore, is neither void, illegal nor bad in law. He is not governed by the Standing Orders but by the C.C.S. (C.C.A.) Rules. Since he was convicted of a criminal charge his conduct amounted to misconduct and in breach of rules. However, he was given opportunity to be heard on the point of quantum of punishment. In substance, the contention is that the action is justified.

10. As stated earlier there is no dispute on the point that he was convicted by the Chief Judicial Magistrate that his appeal to the Sessions Court failed and that even in the High Court order of conviction remained undisturbed. Documentary evidence in that behalf is produced on behalf of the management. However, it is not necessary to refer to that in greater details. Sufficient to say that they support the facts stated above and which are also not in dispute.

11. The fact that he has been given benefit of Probation of Offenders Act cannot come to the rescue of appellant and fact that he has not been sentenced inspite of the conviction will not by itself obliterate the effect misconduct of the accused so as to debar the Disciplinary Authority from imposing penalty under the rules against an employee who has been convicted for misconduct. The learned counsel appearing on behalf of the management rightly relied upon a decision of the Supreme Court in the case

of Divisional Personnel Officer Vs. T. R. Challappan, respondent reported in AIR 1975 Supreme Court 2215.

12. However, the point that arises for consideration is whether the action of the management in terminating the services of Shri Khode is justified. It has to be noted that there has been a conviction by Criminal Court and upheld by the Court of Sessions and the High Court. That is one under Section 323 read with Section 34 and 324 read with Section 34 of the Indian Penal Code. Since he had been convicted by Criminal Court the provisions of Rule 14 are not required to be followed. That is what Rule 19 so far as is relevant provides. It states "notwithstanding anything contained in Rule 14 to Rule 18, where any penalty is imposed on a Government servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge of the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit." Therefore, where the Government servant is sought to be visited with penalty in departmental proceeding on the ground of conduct which has led to a conviction an elaborate enquiry contemplated by Rules 14 to 18 is not necessary. However, what is necessary is provided by the proviso and it states thus "provided that the Government Servant may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made in a case under clause (i)." This has been done and there cannot be any dispute on the point because the relevant record is produced. That notice is dated 8-9-1987 and it is seen that the delinquent Shri Khode has replied to it by letter Annexure 'B'. Thereafter, the final impugned order has been passed on 9-11-1987. Compliance of therefore, Rule 19 is made and compliance with the Rule 14 to 18 is dispensed with by Rule 19 itself.

13. However, what is to be considered is whether the conduct which led to the conviction and for which the penalty of termination of services is imposed was called for in this particular case. It is needless to say that the provisions of Section 11A of the Industrial Disputes Act provides that if the order of discharge or dismissal was not justified, it may, by its award, set aside the order of discharge or dismissal and direct reinstatement of the workman on such terms and conditions, if any, as it thinks fit, or give such other relief to the workman including the award of any lesser punishment in lieu of discharge or dismissal as the circumstances of the case may require. In the Supreme Court's decision in the case of Divisional Personnel Officer (Supra) it is observed "the rule making authority deliberately used the word 'consider' and not 'determine' because the word 'determine' has a much wider scope. The word 'consider' merely connotes that there should be active application of the mind by the disciplinary authority after considering the entire circumstances of the case in order to decide the nature and extent of the penalty to be imposed on the delinquent employee on his conviction on a criminal charge. This matter can be objectively determined only if the delinquent employee is heard and is given a chance to satisfy the authority regarding the final orders that may be passed by the said authority. In other words, the term

'consider' postulates consideration of all the aspects, the pros and cons of the matter after hearing the aggrieved person. Such an enquiry would be a summary enquiry to be held by the disciplinary authority after hearing the delinquent employee....". It is further observed "This provision confers power on the disciplinary authority to decide whether in the facts and circumstances of a particular case what penalty, if at all, should be imposed on the delinquent employee. It is obvious that in considering this matter the disciplinary authority will have to take into account the entire conduct of the delinquent employee, the gravity of the misconduct committed by him, the impact which his misconduct is likely to have on the administration and other extenuating circumstances or redeeming features if any present in the case and so on and so forth." Considered from this point of view it is necessary to examine the facts which led to Shri Khode's prosecution and conviction. Of course I will have to restrict myself to the facts which are on record. Judgment of Learned Judicial Magistrate gives those facts and therefrom it is seen that there is a dispute between the Landlord and the complainant and the prosecution arose out of an incident that took place between the two. It is also an admitted position that civil suit filed against complainant was then pending. There has been a incident between the parties and complaints have been lodged by both parties against each other. The incident involving present delinquent employee consisted of the employees giving a blow to the complainant resulting in a bleeding injury to her left hand. He has also allegedly given a blow to Minakshi resulting in injury on the nose and yet another blow to the complainant Pushpabai. So far as the injuries are concerned it is found that Pushpabai has made an attempt to word off the blow which fell on the hand causing bleeding injury. Minakshi came to the rescue of Pushpabai, a blow fell on the nose of Minakshi causing a bleeding injury to her. This is the nature of evidence so far as the assault resulting in injuries is concerned. It has to be noted that the Disciplinary Authority is expected to take into the consideration the conduct of the delinquent which has led to conviction. The conduct consists of assault against Pushpabai and her daughter and which incident arose because of strained relations between the parties. In the show cause notice given to the delinquent, it has been mentioned that it was revealed that he was charged with the offence of assaulting a woman with an iron bar and further it is stated that "whereas the undersigned is convinced that Shri Khode, T. No. Nos. 525 had committed a criminal act unbecoming of a Government Servant." In the order of termination of service it has been mentioned that "Now therefore, the undersigned as a Disciplinary Authority, after careful examination of the case comes to the conclusion that the said Shri L. S. Khode, T. No. Nos. 525 has been found guilty and had committed a criminal offence which is unbecoming of a Government Servant, and now therefore, the undersigned as a disciplinary authority orders removal from service of Shri L. S. Khode, T. No. Nos. 525 with immediate effect. Therefore it appears that the Disciplinary Authority was of the view that this act on the part of the delinquent was unbecoming of a Government Servant. It is true that it is the function of the management to find out of

what penalty would be adequate in the given circumstances. But in my opinion, in this particular case it is rather difficult to see justification for the extreme penalty of termination of service for this act or conduct of the delinquent which has led to his conviction. In the judgement to which reference has been made above the Supreme Court has observed "It may be that the conviction of an accused may be for a trivial offence where a stern warning or a fine would have been sufficient to meet the exigencies of service" and in the given case authority may even refuse to order any penalty if offence is too trivial. If the delinquent employee is a youthful offender who is not convicted of any serious offence and shows poignant penitence or real repentance he may be dealt with as lightly as possible. In this particular case before me I find that the said circumstances in which the alleged offence of which he has been held guilty was committed did not call for the extreme penalty of termination of service. He has been dealt with by the Criminal Court and the High Court in the facts and circumstances of the case while upholding order of conviction gave him benefit of Probation of Offenders Act. Though he cannot contend that the disqualification would be automatically obliterated, he could certainly plead that as the circumstance to show that the offence was not such which merited severe penalty. In my opinion the penalty of termination of service is required to be set aside and it will have to be substituted by one of the minor penalties. It may be noted that Shri Khode states that he had an unblemished service record. It is not shown that he had a past bad record. He has been also let off under the provisions of the Probation of Offenders Act after his conviction was up-held. The alleged incident is because of the dispute between a landlord and his tenant. After considering all these factors, in my view the warning would have been sufficient, and is substituted for penalty of termination of service. He is entitled to reinstatement and obviously with back wages. Award accordingly.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

सई दिनी, 20 अक्टूबर, 1994

क्र.पा.3231—संघीयता विचार अधिनियम, 1917 (1947 का 14) का प्रा. 17 के अन्वये में, केन्द्रीय सरकार ऐसीकम डिस्ट्रिक्ट लेबर, कल्याण के प्रबन्धन के संवर्धनविशेष आर एन एन कार्यकारी के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार आयोजना प्रवर्धन, सं. 1, बम्बई के संवर्धन को सम्बन्धित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 19-10-94 में प्राप्त हुआ था।

[प्रा.पा.क्र-40011/91-आ. आर (टी. नं.)]

न. नं. वा. 3231, एक अधिकारी

New Delhi, the 20th October, 1994

S. O. 3231.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No.1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the

management of Telecom Distt. Manager, Kalyan and their workmen, which was received by the Central Government on 19-10-94.

[No. L-40011/8/91-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 BOMBAY

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer
REFERENCE NO. CGIT-93 OF 1991

PARTIES :

Employers in relation to the management of
Telecom Distt. Manager, Kalyan

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Management.—Shri Chalase, Advocate
For the Workmen.—Shri M.B. Anchan, Advocate

INDUSTRY : Telecommunication

STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 8th day of September, 1994

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi has made the following reference by letter dated 19-11-1991/5-12-1991, to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) read with Section 2A of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the Act.

“Whether the action of the management of Distt. Telecom Engineer, Kalyan in retrenching the workmen as per the list enclosed (Annexure ‘B’) from service and in not maintaining the seniority list is legal and justified? If not, what relief the workmen concerned are entitled to?”

2. The Statement of claim filed by the Bharatiya Dak Tar Mazdoor Manch (hereinafter referred to as the Union) goes on to state :

“The management i.e., the Telecom District Manager, now, the General Manager, Telecom Kalyan had engaged 246 Casual Labourers since 1982, most of them have completed 240 days of continuous service and that the department terminated their services without any notice, and without payment of retrenchment compensation. The termination therefore, is, illegal, and invalid. The department also did not maintain any seniority list of the Casual Labourers, and the principle of last come first go was not followed. While reappointing the seniority was not considered, and the juniors were appointed ignoring the claim of the seniors. Unfair labour practice was followed while re-engaging them.

3. The retrenchment being illegal, the Union raised an industrial dispute before the Asst. Labour Commissioner (C) Bombay. While the matter was pending before the Conciliation Officer, the department reinstated about 165 persons as stated in Annexure ‘A’ to the Schedule. (Such a Schedule is not forthcoming). Even though they were reinstated, they were not paid back wages from the date of termination of their services, till the date of reinstatement. Remaining 81 labourers were however, not reinstated in services. Therefore, these 165 labourers reinstated are entitled to back wages, because, their earlier termination was illegal and invalid. The department did not comply with the provisions of Section 25F of the Act, inasmuch as they have not been given one month's notice, retrenchment compensation. Their services came to be terminated abruptly, and therefore, they are deemed to be in continuous service and entitled to back wages for the period they were out of employment, i.e., between the illegal termination and the reinstatement. The Conciliation Officer has in his report dated 2/9-1990, recorded that those who have completed 240 days of continuous service, and terminated their services without complying the provisions of law should be paid the wages for the idle period, and that their services should be treated as continuous service. The Union therefore, submits that, these 165 employees have completed 240 days of continuous service and therefore, they are entitled to the wages for the idle period.

4. With regard to the remaining 81 employees, the Union submits that though they might not have completed 240 days, because they were not provided with work, while their juniors were reinstated by providing them with work, these 81 persons are also entitled to back wages and reinstatement. It is the promise of the Union that the seniority list of the Casual Labourers were not followed, and last come first go was not observed. Had it been maintained, these 81 employees would have been able to complete 240 days of continuous service, which they could not do. The Union therefore, submits that these 81 employees are also entitled to reinstatement and back-wages.

5. Prayer therefore made, is, that all the 246 employees are entitled to reinstatement and backwages from the date of their earlier illegal termination, till the date of reinstatement.

6. The management has filed written statement denying the allegations. It is stated therein, that the present reference is, vexatious, malicious, and not tenable in law. Prayer for rejecting it in limine is therefore made.

7. It is stated that, the workman who had not completed 240 days of continuous services within the meaning of the provisions of the Industrial Disputes Act, were not entitled to the protection of Section 25-F of the Act, when they were retrenched. Nor are they entitled to claim reinstatement much less back wages. It is, therefore, submitted that the present reference suffers from non application of mind and is liable to be rejected on that ground also. It is further contended that the ministry was informed about this, by the Management's Advocate by his

letter dated 9-5-1992, but no action was taken on that letter.

8. It is then however, admitted that the management employs Casual Labourers to meet the exigencies, when there is work which is essentially of a casual nature, and that they could not be provided with work for more than 240 days and since it was so, they cannot claim the benefits of the provisions under the Industrial Disputes Act, 1947. It is specifically denied that the 81 workmen whose case is being now espoused, had not completed 240 days of continuous service, in a year preceeding the date of their alleged termination. It is contended that the management reinstated 165 casual workmen as a matter of settlement and the Union agreed that they were prepared to work without any back wages. The question of payment of backwages to those reinstated therefore does not arise. So far as the dispute with regard to the 25 casual workmen is concerned and who have not been reinstated, the contention is that they had not completed 240 days of continuous work. The 57 workmen who had completed 240 days of continuous work have already been reinstated during the conciliation proceedings and there is no dispute now surviving with regard to them. It is denied that their juniors were engaged to work, and that the seniors were denied an opportunity to complete 240 days. It is also denied that no seniority list was maintained.

9. On behalf of the workmen, Shri Subramaniam filed his affidavit. He happens to be the Organising Secretary of the Union, which has raised the present dispute before the Asst. Labour Commissioner (Central) Bombay, and was according to him, conversant with the facts of the case. There are a great deal of discrepancies between the statement of claim filed by the workman and the affidavit filed on his behalf. I will first deal with the case that has been made out in the statement of claim. It is stated that in all, 246 casual labourers were engaged and that out of them most of them had completed more than 240 days of continuous service. Yet, their services were terminated without following the provisions of Section 25F of the Act, inasmuch as they were not given one month's notice, nor were they paid any compensation in lieu of such notice. It is thus seen from the statement of claim, that it is not the case that all the 246 workmen had completed 240 days of continuous service in period of 12 months preceeding the date of termination of their services. Those 165 employees who had completed 240 days of continuous service were reinstated during the conciliation proceedings. It is the case of the workmen, that those reinstated during the pendency of the conciliation proceedings have not been paid back wages, and claim is made in respect of those 165 workmen for back wages for the intervening period between the date of their earlier termination and the date of their reinstatement.

10. Now it is seen that the reference that has been made to this Tribunal for adjudication is with regard to the justness of the action of the management in retrenching the workmen as per the list in annexure 'B'.

11. It is seen from the list that it is with regard to the 83 workmen, and it does not deal with the case of

the 165 workmen who have been retrenched and re-instated. The legality or justification of the action of retrenchment so far as these 165 Casual Labourers is concerned, is not referred to this Tribunal for adjudication. In the circumstances, in view of this position, the union cannot claim back wages for and on behalf of the 165 workmen who were retrenched and reinstated before the conciliation proceedings. It appears therefore, for the reasons that the Government of India while making the present reference did not except this Tribunal to adjudicate upon the dispute with regard to these 165 persons.

12. It appears that a committee consisting of the representatives of the management and the Union was constituted to look into the problems of the Casual Workers and that committee, after examination the position, gave its report. It appears that the Union representatives in that committee had made specific verification and that they further agreed that they will not raise any dispute with regard to the casual labourers. A joint report was therefore submitted and that report has been signed by the representatives of the union and the management and that this fact has been admitted by Shri Subramaniam in course of his cross examination.

13. The dispute that is then raised is that the 81 workmen out of the 246 have not been reinstated. That is at the stage of filing the statement of claim. It is mentioned in para four of the statement of claim that though these persons have not completed 240 days of work, the reason assigned is that they were not provided with work, and that they were not allowed to complete 240 days. Admittedly, they have not completed 240 days. If that be so, they cannot be deemed to have been in continuous service for a period of one year before the termination of their services and in that event, they will not be entitled to the protection of Section 25-F of the Act. The retrenchment if any, of such workmen, therefore, will not be illegal or unjustified. The fact that they were not allowed to complete 240 days will not be a subject matter of adjudication in the present reference.

14. However, Shri Subramaniam in the course of his affidavit has come out with a different case altogether. He stated in para two of his affidavit, that, the department reinstated "about 157 labourers" and in para 3 he says that a Casual Labour Committee was appointed to confirm the number of days of continuous service put in by each casual labourer from the records available with the department. And thereafter, as per the report of the Committee, the department, reinstated all those Casual Workers who had completed 240 days of continuous service. Therefore, it is clear that, those who had completed 240 days of continuous service within a period of one year, came to be reinstated during the conciliation proceeding. If that be so, no dispute remains for adjudication. If at all, the dispute would be with regard to the non-payment of back wages for the idle period between the earlier retrenchment and the reinstatement. As I stated earlier these Casual Labourers are not entitled to it particularly, when the same has not been referred for adjudication to this Tribunal.

15. Thereafter, he says that the remaining 83 Casual Workers, whose case has been referred to this Tribunal were reinstated w.e.f. 1-1-1990, and 26 out

of them were again terminated w.e.f. 1-7-1990 following the report of the Casual Labour Committee. He admitted that they had not completed 240 days of continuous service. Now, therefore, it is the case of only 26 workmen whose services were terminated w.e.f. 1-7-1990 needs adjudication. It is further contended in para 6, that those 62 Casual Workmen, who had not completed 240 days. Though it is stated that, they were infact not allowed to complete 240 days, as stated earlier, the fact remains that they had not completed 240 days, and therefore, cannot claim the relief or the protection under Section 25F of the Act. Section 25-B, which defines continuous service for one year states that a person who has worked for not less than 240 days will be deemed to have been in continuous service for one year. It does not deal with the case of those workmen who have not been allowed to work for 240 days. In the circumstances, it is rather difficult to appreciate the contentions raised on behalf of the union, that the termination of these 26 casual workers was unjustified because of non-compliance of the provisions of Section 25F of the Act.

16. It has been also argued on behalf of the management, it appears that this is the case that the management is trying to make out that it is admitted in the course of cross examination by Shri Subramaniam that he had mentioned in his affidavit that the services of 26 Casual Workers once again came to be terminated w.e.f. 1-7-199, after the report of the Casual Labour Committee, on the ground that they had not completed 240 days service. In the circumstances, I do not find as to how it could be said that the services of these 26 workmen were terminated illegally and unjustly.

17. In my opinion therefore, there is no relief to which the workmen listed in annexure B to the schedule is entitled.

18. I may however, at this stage mention that, the Union has not produced any material in support of case, and that the management has stated that a Casual Labour Committee consisting of the representatives of the union as well as the management was constituted, and that committee enquired into the question of the Casual Workers, and thereafter prepared a list of Casual Labourers, showing the date of entry and particulars of each casual labourers' service in the department. In the light of this material it is difficult to say that the action of the management was illegal and unjust. I would therefore, pass an award accordingly.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1994

का. अ. 3232—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कन्टोनमेंट बोर्ड, पुणे के प्रबन्धन के संबंध में निवेदित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 1, बंबई के पक्षों को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-13012/11/90-आई. आर. (डी. यू.)
के. बी. बी. उण्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th October, 1994

S.O. 3232.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Cantonment Board, Pune and their workmen, which was received by the Central Government on 19-10-1994.

[No. L-13012/11/90-IR (DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, AT BOMBAY

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-1/78 of 1991

PARTIES :

The Employers in relation to the management of
the Cantonment Board, Pune.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employer.—Shri Kulkarni, Advocate.

For the Workmen.—Shri Sathe, Advocate.

INDUSTRY : Cantonment STATE : Maharashtra
Bombay, dated the 12th day of September, 1994

AWARD

The following reference has been made to this Tribunal by the Government of India, Ministry of Labour, by letter dated 19-09-1991, for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947. (Hereinafter referred to as Act, for short.)

“Whether the action of the management of Cantt. Board, Pune, in denying the seniority to Shri S. G. Jadhav w.e.f. 2-7-1965 as junior clerk and not giving him promotion, is justified? If not, what relief the workman concerned is entitled to?”

2. Statement of claim has been filed by the General Secretary, Pune Cantonment Board Karmachari Sangh, on behalf of the workman. The admitted position is, that, he was appointed with effect from 2-7-1965 as Tax Collector in the Cantonment Board of Pune. Admittedly, he is a non-matriculate. His grievance is, that, though he was senior and eligible for promotion, he was not given his due place in seniority, and denied promotion on unjustified grounds, and his juniors were promoted. According to him, the National Industrial Tribunal headed by Shri Jeejeebhoy, recommended that promotion should be given strictly on the basis of seniority, and

no other criteria should be applied for grant of promotion. His contention is, that, it was directed by the Award delivered by Jeejeebhoy National Industrial Tribunal, that, whenever a new post is to be created or a vacancy has to be filled, all things being equal, the seniormost shall be entitled to be appointed thereto. He has in the course of statement of claim stated that, inspite of this award, he has been denied promotion, and when he asked for reasons, he was told that he was not matriculate, and others were matriculates. His grievance is, that, that should not have been the criteria, because the Award provided that seniority should be the criteria. He therefore, stated instances where non-matriculates have been promoted. His grievance is, that, a vacancy arose on 07-07-1970 and that should have been given to him.

He has however, stated that he came to be promoted to the post of Senior Clerk with effect from 26-09-1983, though he continued to be a non-matriculate, and, if the contention of the management was right, he could not have been given promotion even in 1983.

He raised the dispute on 23-08-1988 before the Asstt. Labour Commissioner (Central) Pune, through the Pune Cantonment Board Karmachari Sangh, and the matter came to be referred to this Tribunal for adjudication as result of the failure of the conciliation proceedings. He has also alleged malpractices on the part of the Executive.

Written statement has been filed on behalf of the Cantonment Board, by the Joint Cantonment Board Executive, Shri S. S. Shahal. It appears from the written statement that Shri Jadhav was appointed initially as a Coolie in the Fire Brigade Workshop, to the post of a Pound Keeper in the pay scale of Rs. 45-1-55-EB-4-105-5-115 with effect from 02-07-1965. According to the management, he was posted as a Junior Clerk in the same pay scale with effect from 06-01-1977, and continued as such till 25-09-1983. Pay Scale for the Tax Collector and the Junior Clerk was the same, i.e. Rs. 46-3-85-EB-4-105-115. It is however, denied that the post of Shri Jadhav on 02-07-1965 was equal to the post of Junior Clerk, as he was not having the minimum qualification required, i.e., S.S.C. or Matriculation, and hence could not be equated with the post of the Junior Clerk. According to the statement, he was non-matriculate and other matriculars were to start with the pay of Rs. 55 in the pay scale of Rs. 46-3-85-EB-4-105-5-115. This is the justification for not counting his seniority with effect from 02-07-1965 in the cadre.

An admission given so about the promotion given to other persons, but the justification is that they were matriculates, while Shri Jadhav was not. It is further contended that pursuant to the Award, there has been an agreement between the All India Cantonment Board Employees' Federation and the Employees working in various Cantonment Boards in India, executed under Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947, on 13-05-1967. Clause 4 of the said memorandum of settlement stated that :—

“Where a Cantonment post is indirectly equated to the State Government Post, he will be

entitled to the Pay Scale mentioned in Column 4 of the Schedule, provided he holds the qualifications prescribed, if any by the Cantonment Board, at the time he was appointed to that post.....”

It is admitted that the 7 employees were promoted to the posts like, Revenus Superintendent, Accountant Etc., It is contended that it was so done on the basis of seniority and merit. Employment to the post of Asst. Fire Brigade Superintendent is concerned, the person eligible should know fire fighting, and should qualify himself by the appropriate course in the field. It is on that basis that, Shri Mane, came to be promoted to the post of Asst. Fire Brigade Superintendent. It is denied that some persons mentioned by Shri Jadhav have been given promotion after the delivery of the National Industrial Tribunal's Award of 1958 purely on the basis of seniority. The contention, therefore, is, that the promotion was given on the basis of seniority-cum-merit, competency in the field and ability and capacity to perform the duties expected of him. Shri Jadhav cannot demand benefit of any wrong done in the past, if at all done. The fact remains that he did not possess the requisite qualifications for the promotional post, and hence he was not promoted.

It is further stated that the service conditions of the Cantonment Board's Employees are governed by the Cantonment Fund Service Regulations, 1937, as amended from time to time, and Rule No. 5-B(3) of the said Rule deals with the requirements for promotion. It reads :

“No person who had not been declared medically fit by the authorised Medical Attendant and who does not possess the minimum qualification and experience as may be specified for each post by the Office Commanding in Chief, the Command shall be appointed to any service under the Board provided that the minimum qualification specified as aforesaid shall not operate for the disadvantage of the existing servant for continuance in the post in which he has been appointed, or, for appointment on promotion.”

It appears from all this, that the main defence of the Cantonment Board, is, that, he was not qualified to be appointed to the promotional post of Senior Clerk even in the year 1988. Therefore, though he was considered for promotion, he was not given promotional post, since he did not possess the requisite qualification.

Rejoinder has been filed on behalf of the workman, and written argument have been also filed on behalf of either side. No oral evidence has been adduced.

The following points arises for my determination, and my findings are also mentioned alongwith the same.

ISSUE	FINDING
1. Whether the action of the Cantonment Board, Pune in denying promotion to Shri S. G. Jadhav, in the year 1976 is justified ?	No.

2. If not, what relief the concerned workman is entitled to, in the circumstances of the case ?

NO RELIEF

It is to be noted that the Cantonment Board Karmachari Sangh has raised this dispute after a long time, and it is to be further noted that it was done after the retirement of Shri Jadhav from the services on superannuation with effect from 31-10-1992. It may also be mentioned that, at the time of making the statement of claim, it is mentioned that ;

"I am here not concerned with the individual case, but with the general principle which labour claims should be applied, namely, that promotions should be given strictly according to seniority and that a seniority list should be maintained."

Reliance has been placed upon the awarded given by Shri F. Jeejeebhoy, and the issue No. 2 framed therein and the observation made by the learned judge Shri Jeejeebhoy. The issue is, "Whether promotions be given strictly according to seniority of the workman ? If not, that should be the criteria for promotion and what should be seniority list in each category of workmen ?"

It is observed that :

"On this issue, I propose to give the same directions which has been given by the Tribunals in the past, namely, that whenever a new post is created or a vacancy is to be filled, all things being equal, the senior most shall be entitled to be appointed thereto"

A little later, it is observed :

"As regards the preparation of the seniority list, it is not necessary. Seniority will count according to an employees' length of service in the line of promotion and the terms line of promotion connotes the steps which naturally lead from one grade to another, for instance, a Clerk may seek promotion in the line leading to the Superintendent or to the Tax Superintendent or Revenue Superintendent."

Therefore, the Jeejeebhoy's award clearly rules out the possibility of promotion being given only on the basis of seniority. However, there is a rider provided, and that is, all things being equal. The communication, which is on record, addressed by the Director, Defence Lands and Cantonments, to the Cantonment Executive Officer also says that the post of Senior Clerk is only a promotional post and not a selection post, and hence it has to be filled up strictly as per seniority amongst Junior Clerks, subject to rejection of unfits in accordance with Rule 5(b)(8) of the Cantonment Fund Servants Rules 1937.

Rule 5(B)(8) of the Cantonment Fund Servants' Rules, 1937 provided that ;

"All appointments to promotion posts shall be made on the basis of seniority list maintained for this purpose by the Board, subject to rejection to those considered unfit.

It further provides that promotion on selection posts shall be made on the basis of seniority cum merit. Therefore, it is clear, that, so far as non-selection posts are concerned, seniority is material, and if the senior is to be rejected, for promotion, it is on the ground of unfitness. The question of merit is not relevant, except in the case of appointment to selection posts. It is therefore, clear from the Jeejeebhoy Award, as well as under the Cantonment Fund Servants' Rules 1937, and also clarified by the Director's letter to which reference has been already made above. Therefore, the management will not be justified in denying the post of Senior Clerk, unless it is stated that he was considered and found unfit and the reasons assigned. At this stage, I may mention that in the statement of claim, it has been mentioned that he was promoted as Tax Collector, and it is the case of the management that he was initially appointed as a Coolie, in the Fire Brigade Work Shop and promoted to the post of Pound Keeper with effect from 2-7-1965 upto 5-1-1977, and thereafter posted to work as a Junior Clerk with effect from 6-1-1977 upto 25-9-1983. According to Shri Jadhav, he was promoted as Tax Collector, with effect from 2-7-1965, and the Tax Collector as well as the Junior Clerk were clubbed together alongwith other categories of employees of the same pay scale of Rs. 46-115. This does not appear to be in dispute, because in the written statement, it has been contended that the Pay Scale of both Junior Clerks and Tax Collector is Rs. 46-115. What is however, contended is, that Mr. Jadhav was not eligible since he had not passed SSC examination which was a pre-requisite for appointing him as a Junior Clerk. I do not see any merit in this line of arguments advanced on behalf of the Cantonment Board. What appears to be the position is, that the person who is to be appointed as Junior Clerk in the scale of 46-115 if he happened to be a Matriculate or SSC passed, he was to get an additional pay of Rs. 15/- in the same scale. In my opinion, it is rightly urged on behalf of Shri Jadhav, that seniority will not depend upon the pay drawn by him, nor will it depend upon the aspect whether he was a matriculate or SSC passed candidate. It is submitted that he would be in the same pay scale, and his seniority would depend upon the date of joining, in the pay scale, and his qualification such as non matric will not place him lower in rank than a matriculate appointed in that very scale later than him. Seniority will have to be therefore, reckoned from the date of appointment, and in my opinion, the action of the management will not be justified.

In this particular case, this is what has happened, as can be seen from the seniority list circulated, and that this aspect is also not disputed that his name has been shown in the junior clerks' list. It is submitted on behalf of the Cantonment Board, that, it was so, because he had not passed Matriculation/SSC examination, and has evidence in support of this.

According to the management, there has been a settlement reached between the parties, on 13-5-1967. It appears that pursuant to this settlement, and to which reference has been made even by the workman Shri Jadhav, the necessary qualification for appointment to the post of Senior Clerk

was prescribed as Matriculation|SSC. The said letter dated 9-12-1980 is addressed to all Executive Officers of the Cantonment Boards, including Pune, I have already stated above, that Shri Jadhav was not a matriculate, and, therefore, he could not be promoted to the post of Senior Clerk. However, according to Mr. Jadhav, this circular was pursuant to the settlement of 1976, and at that time, there was no such requirement for appointment to that post of Sr. Clerk. According to him, therefore, at that time, considering his seniority, on the basis of his appointment in that scale, of Junior Clerks, and Tax Collectors, he was senior to others, and was eligible for promotion. As I stated earlier, if matriculation was not a pre-requisite for appointment to the promotional post of Senior Clerk, refusing promotion on the ground that he was not a matriculate will not be justifiable.

In addition to the oral submissions, the written arguments have been also adduced on behalf of the Cantonment Board, and it has been stated therein, that he was not found fit for the appointment to the relevant post, and therefore, he was not considered for the same. The point of fitness and unfitness, is not introduced in the first written statement filed on 30-6-1993. Therein, the stand taken by the Cantonment Board is, that, he was not qualified for that post, and therefore was not considered. It is therefore, difficult to fall back upon the contention that he was a Tax Collector, not a Junior Clerk, and that he was drawing lesser pay being a non-matriculate, and therefore, was junior to those who were matriculates, and there is not even a whisper that he was not found fit for promotion and therefore was not promoted. I therefore find that the action of the management of Cantonment Board Pune, in not promoting Shri Jadhav when his juniors were promoted was not justified. It is the case of the workman that Shri Mukadam who joined the services as Tax Collector on 2-8-1965 was promoted as Sr. Clerk on 7-7-1976, and Shri K. P. Nair, whose joining date was 7-12-1966 was promoted as Senior Clerk with effect from 24-10-1978. Therefore, since he had joined the services as a Junior Clerk prior to Mr. Mukadam, he was entitled to the promotion in the year 1976 itself.

He had also made a mention in para 11 of his statement of claim, to the case of those persons whose names are at Sl. No. 2 to 7, and according to him were given promotion as Senior Clerk. Two of them were promoted as Sr. Clerk, and one was promoted as Accountant, and one as Revenue Supdt., one as Asst. Revenue Supdt., and one as Fire Brigade Supdt., and one as Store Keeper, all in the same grade of Senior Clerks. Shri Jadhav was however promoted in 1983, after all these promotions were made, and according to him, even in 1983, he had not passed SSC/Matriculation. This fact has also been not disputed by the management of Cantonment Board. I therefore, find that there is no substance whatsoever, in the contentions raised on behalf of the Cantonment, and the action of the Cantonment Board in denying promotion to Shri Jadhav on the ground that he was not a matriculate is not justified.

In the course of the written statement, the management has contended that the present dispute has been raised by the delinquent after a lapse of a long time, and in fact at present there is no industrial dispute, existing, which requires adjudication by this Tribunal. It was further, submitted that in spite of the fact, that he did not possess the necessary qualifications, the management gave him the promotional post, purely on sympathetic consideration of his case. He is, therefore, in fact, barred from making a grievance about his seniority and non appointment to the promotional post in the year 1976, and thereafter in the years 1981 and 1982.

On behalf of the management, certain authorities have been relied upon. The first one relied upon is, one in the case between the Manager, M/s. P. K. Porwal, Vs. Labour Court Nagpur, reported in the Maharashtra Law Journal, 1968, page 1. I find that it was dealing with a case under Section 33(C)(2) of the Industrial Disputes Act, 1947, and the one in hand is under Section 10(1)(d) of the Act. With respect I find that the decision relied upon will be of no assistance to the learned counsel appearing on behalf of the Cantonment Board. Another decision reported in A.I.R. 1977, page 282, between the Kerala State Electricity Board, and Shri Kunhaliumma was relied upon. That again was a case not under Section 10(1)(d) of the Act, and therefore, will not have any bearing on the present dispute. The last decision however, in the case between Shri R. Ganeshan, and the Union of India reported in 1993--I CLR, page 697 deals with a case under Section 10(1)(c) and 12(5) of the Industrial Disputes Act, 1947. Therein an application for making reference was made by the workman after inordinate delay, and the same was refused. It has been held, that the Government was justified in refusing to make a reference on the ground of delay. The Central Government passed an order dated 11-1-1989 refusing to make the reference on the ground of delay. The industrial dispute raised by the Petitioner in the year 1987 was with respect to his dismissal by the Air India Corporation in the year 1980, for certain alleged misconduct, for which approval was granted under Section 33(2)(b), on 24-5-1984. The High Court of Bombay dismissed the Writ Petition and observed therein that :—No industrial dispute existed which required adjudication. It was held that :

“The petitioner was dismissed way back on 8-10-1980. As far as the petitioner is concerned, the order of dismissal came into effect on 8-10-1980. Nothing prevented him from raising dispute soon thereafter. His departmental appeal was even dismissed on 3-1-1981. Even if it is held that the order of dismissal was finally confirmed when the approval under Section 33(2)(b) was granted on 24-5-1984, there was no cogent and satisfactory explanation for the inaction for the period between 24-5-1984 to 12-11-1984.”

I find that the claim of the Karmachari Saugh is that Shri Jadhav should have been promoted with effect from 7-7-1976, but was promoted in the year 1983. Therefore, he should be paid the difference in pay for the intervening period between 1976 and

1988. In my opinion, the Karmachari Sangh will not be justified in claiming the same, because the workman and Association had kept quiet allowing the things to happen as they did and he has not performed the duties of the promotional post during the intervening period, and he has raised this dispute only after his retirement on superannuation. Therefore, in view of the facts and circumstances, of this case, the workmen will not be entitled to any relief under this reference.

Award accordingly. I make no order as to costs.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1994

का.प्र. 3233—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) का धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रिय सरकार मद्रास टेलीफोन, मद्रास के प्रबंधन में संलग्न दिशाओं और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकार, मद्रास के पचास को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रिय सरकार को 19-10-91 को प्राप्त हुआ था।

[रिफरेंस नं. 40012/25/86-डी-2 (बी)]

के. वी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th October, 1994

S.O. 3233.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Madras Telephone Madras and their workmen, which was received by the Central Government on 19-10-94.

[No. L-40012/25/86-D.II(B)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL,
TAMIL NADU MADRAS

Monday, the 1st day of August, 1994

PRESENT:

THIRU K. PONNUSAMY, MABL
INDUSTRIAL TRIBUNAL
INDUSTRIAL DISPUTE NO. 40/88

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workman and the Management of Madras Telephones, Madras-1.)

Between

Shri P. Pachiappan,
No. 14, Teetes Garden,
1st Lane, Perambur,
Madras—600011.

AND

The General Manager,
Madras Telephones,
Telephone House,
Madras—600001.

Reference Order No. L-40012/25/86-D.II(B), dated 25-3-88/27-6-88, Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi

This dispute after remand, coming on for final hearing on Thursday, the 14th day of July, 1994 upon perusing the reference, Claim and Counter Statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru T. Fenn Walter, Authorised Representative for the workman and of Thiru S. Seshadri, Central Government Pleader appearing for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following:—

AWARD

1. The case of the petitioner briefly stated is as follows : The petitioner entered into service of the respondent in the year 1963. He was carrying on his works faithfully and efficiently. During the relevant period, he was working as S. G. Gateman at Kellys under the direct control of the Assistant Engineer, Crossbar Exchange Maintenance, 22, Kellys Road. Charge sheet was issued to him making false allegations that he received illegal gratification of Rs. 400 from Mohilal promising to get permanent telephone connection. He received an illegal gratification of Rs. 200 from Amarnath to change the telephone wires from Aluminium to Copper at his residence. The charges are vague and ambiguous. The date of the alleged incident is not stated in the charge sheet. He has no power to do any of the aforesaid things. Second charge sheet was issued to him that he accepted illegal gratification of Rs. 200 from Dr. S. Navaneetham Nursing Home, promising to get temporary telephone connection in September 1983. The date and other particulars and the place were not mentioned in the charge sheet. He has no power or authority to give connection to anybody. It is quite impossible for him to make arrangements to give telephone connection and change the wires. The statement was obtained from him by Junior Engineer, his superior and he was forced to sign in the statement. He does not know the contents of the statement. The domestic enquiry was ordered. The statement obtained from him was used against him as statement of confession, though he was never informed. The statement obtained from him cannot be used against him for any purpose. The appointing of Enquiry Officer and the Presenting Officer are contrary to the rules and they ought not to have functioned in that capacity. In the domestic enquiry Mohilal was not examined which vitiates the principles of natural justice and has vitiated the entire enquiry. In the domestic enquiry, the Prosecuting Agency was not able to place any document in support of the charges. The only basis of evidence is so called confession statement which is not a legal evidence. Navaneetham was examined in the domestic enquiry and he was not able to state on what date, under what circumstances Rs. 200 was paid by him to the petitioner, Gopal Krishna Gupta and Sankarasubbu are not cited as witnesses in the charge sheet. They were examined as witnesses in the domestic enquiry to the shock and surprise of the petitioner and as such he was not in a position to cross-examine them and that is contrary to CCA Rules under Section 14 of the CCA Rules. He was

not given any facility to inspect the documents relied upon by the Prosecuting Agency. The copies of the documents were not furnished to him and it has grossly vitiated his defence. The copy of the enquiry proceedings was not furnished to him. The enquiry was conducted in contravention to Rule 14 of CCS (CCA) Rules and Section 14 of the Rules. He was not called upon to state his defence. He was not given any opportunity to file his written statement. His helper defence, does not know to read and write English. The domestic enquiry was conducted in unsustainable, improper and illegal manner and in contravention of the Rules. The findings of the Enquiry Officer are perverse and contrary to the evidence recorded. The non-examination of the above witnesses has vitiated the entire enquiry proceedings. He was drawing a salary of Rs. 1000 per month at the time of removal from service. He sent a notice through his counsel seeking his reinstatement in service with all benefits. The respondent has failed to send any reply. His compulsory termination from service is contrary to various provisions of Industrial Disputes Act.

2. The defence of the respondent briefly stated is as follows : The telephone department does not come under the purview of the Industrial Disputes Act. Respondents are limbs of Union of India, Ministry of Telecommunication, and an essential service organisation and not a profit making organisation, and on this score alone, the petition is liable to be dismissed. On receipt of written complaints from two reputed doctors against the petitioner on receipt of illegal gratification, charge sheet, was issued on 27-2-1985. The domestic enquiry was ordered and conducted and the enquiry officer found the petitioner guilty of charges. The dismissal authority by his order dated 31-1-86 compulsorily retired the petitioner service. The petitioner has not preferred an appeal as permitted under CCS (CCA) Rules. On this score also the petition may be dismissed in limine. Petition is not maintainable. The allegations are not false. Since the charge sheet was issued on the basis of complaints from subscribers. In the complaints, the place and period are mentioned. The charges are not vague and ambiguous. The petitioner gave confession on his own volition. The allegation that he does not know the contents of the confession statement is not true since it is written in Tamil. The petitioner knows to read and write Tamil. He understood the contents of the confession statement. Enquiry was conducted in accordance with the appropriate CCS(CCA) Rules. Charges were framed on the basis of the written complaints received from the Subscribers and petitioners confession statement. The petitioner was given ample opportunity to defend himself. The petitioner utilised the service of Shanmugham, SG Group D. Technical Coordination (North) Unit as defence assistant who could do all the cross-examination on behalf of the petitioner and peruse the relevant records. The allegation that Mothilal was not examined in the domestic enquiry and it violates the principles of natural justice is incorrect. The evidence of Dr. Navaneetham clearly proves that the petitioner had received Rs. 100 from Navarathnam under threat and the provisions of CCS (CCA) Rules are not violated. The order of com-

pulsory retirement was issued in accordance with the rules and is not in violation of the Industrial Disputes Act or the CCS (CCA) Rules. The question of reinstatement of the petitioner in service with back wages and other attendant benefits does not arise. The petition is devoid of merits.

3. The points that arise for consideration are:

1. Whether this Tribunal has jurisdiction to entertain the complaint ?

2. Whether the reference is maintainable ?

3. Whether the action of the General Manager, Madras Telephones, Department of Telecommunications, P and T Phones House, Madras in ordering compulsory retirement of the workman Shri P. Pachappan, SG Gateman of Kellys Cross Bar Telephone Exchange, with effect from 31-1-1986 is justified ? If not, to what relief P. Pachappan is entitled to ?

4. Points 1 and 2 : The respondent filed Original Application No. 1608/92 in the Central Administrative Tribunal. The learned Tribunal has remanded the matter to this Tribunal for disposal expeditiously. Admittedly the petitioner entered into the service as a watchman under the respondent. Subsequently, the petitioner served as a Gateman at Kellys Cross bar Telephone Exchange in the year 1986. Mothilal gave a written complaint to the Assistant Engineer, Kellys Internal Madras-10 that to get a temporary connection for his brother-in-law gave Rs. 400 to the petitioner and he also paid Rs. 200 to the petitioner to change the Telephone aluminium wires to copper wires is evidenced by Ex. M.1. The respondent sent a memorandum to the petitioner charging that he received illegal gratification of Rs. 600 from Mothilal for the aforesaid purposes and called for written statement within 10 days from the date of receipt of memorandum is borne out by Ex. W-1. The petitioner sent a notice to the respondent and two others through his counsel to reinstate him with continuity of service, with back wages and attendant benefits, and he is innocent and the charges are false and baseless. Since the explanation submitted by the petitioner was unconvincing and unsatisfactory, domestic enquiry was ordered and it was conducted by the Assistant Engineer S. Muthusamy. The Enquiry Officer submitted his findings that the petitioner is guilty of the charges levelled against him. The Disciplinary Authority agreed with the findings of the Enquiry Officer and after careful scrutiny of the evidence and consideration of the documents compulsorily retired the petitioner with effect from 31-1-1986, afternoon is borne out by Ex. W-2. The petitioner voluntarily gave confession statement admitting the charges, to the Assistant Engineer. The confession statement of the petitioner was not obtained by threat, or coercion or duress. The petitioner voluntarily gave the confession statement. The petitioner knows the contents of the above statements and its consequences.

5. The second charge that the petitioner received illegal gratification of Rs. 100 from Dr. Navarathnam, is proved by the evidence of Dr. Navarathnam, Gopalakrishna Gupta and Sankara Subbu. The finding of the Enquiry Officer is that first two charges are proved. The disciplinary authority after careful

scrutiny of the evidence and consideration of documents, came to the conclusion that the petitioner is guilty of two charges levelled against him. The petitioner is a Central Government employee. He comes under the definition of worker as defined under Section 2(iv)(s) of the Industrial Disputes Act. This Tribunal has got jurisdiction. The petitioner was proceeded under Section 14 of the CCS (CCA) Rules of the Central Administrative Tribunal. The petitioner ought to have approached the Appellate Authority for redressal of his grievance. But, he has not one so. He has not exhausted his remedy before the Appellate Authority. So, the present petition is not maintainable. The reference is maintainable. This Tribunal has got jurisdiction to entertain the complaint. Points 1 and 2 are found in favour of the Claimant.

6. Point 3 : The petitioner was given sufficient and reasonable opportunity to defend his case. He had assistance in the domestic enquiry conducted by the Enquiry Officer. The power of this Tribunal is limited in nature. The Tribunal has no power to reappreciate the evidence and disregard the findings of the Enquiry Officer unless the findings of the Enquiry Officer, are perverse. The findings of the Enquiry Officer, are not perverse. This Tribunal is not an Appellate Authority sitting over the findings of the Enquiry Officer. The Enquiry Officer conducted the enquiry fairly and properly. The domestic enquiry conducted by the Enquiry Officer is just. The domestic enquiry was conducted in accordance with the rules, procedures, provisions of Law, equity, good conscience and the principles of natural justice. Prima facie case has been made out against the petitioner. The aforesaid aspects have been duly complied with in the domestic enquiry conducted by the Enquiry Officer. The order of compulsory retirement of the petitioner from service is just and proper and is proportionate to the misconduct committed by the petitioner. The punishment inflicted upon the petitioner is not illegal, void and arbitrary.

By taking all the aforesaid aspects into consideration, this Tribunal comes to the irresistible conclusion that the action of the General Manager, Madras Telephones, Department of Telecommunications P&T, Phones House, Madras in ordering compulsory retirement to workman Shri P. Pachappan, SG Gateman of Kellys Cross Bar telephone exchange with effect from 31-1-86 is justified. The petitioner P. Pachappan is not entitled to any relief as prayed for by him. The point is found against the petitioner.

In the result, an award is passed negating the claim of the petitioner to reinstatement in service and justifying the compulsory retirement of the petitioner. No costs.

Dated, this the 1st day of August, 1994.

THIRU K. PONNUSAMY, Industrial Tribunal

WITNESSES EXAMINED

For Workman :

W.W. 1 : Thiru P. Pachappan.

For Management :
None.

2471 GI/94-19

DOCUMENTS MARKED

For Workman:

Ex. W-1|27-2-85 : Memorandum of Assistant Engineer (Phones) Kellys Cross Bar Exchange, Madras issued to Thiru P. Pachappan, proposing to hold an enquiry against him.

Ex. W-2|Series : Proceedings of the Disciplinary Authority dated 20-1-86 and findings of the Inquiring Authority dated 3-1-86 (Xerox copy).

Ex. W-3|13-3-86 : Petition from Thiru T. Fenn Walter, Advocate, addressed to the Secretary, Ministry of Communications, Govt. of India, New Delhi, Post Master General, Madras-2 and General Manager, Telephone House, Madras-1 intimating the non-furnishing of copy of enquiry proceedings to Thiru P. Pachappan.

For Management :

Ex. M.1|23-2-85 : Confession statement given by Thiru P. Pachappan, to the Assistant Engineer, Kellys Internal, Madras-10.

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1994

का.आ.3234:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एम टी एन एल बम्बई, के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 1, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/168/92-आई.आर. (डी.यू.)]

के.वी.बी. उष्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th October, 1994

S.O. 3234.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of MTNL, Bombay and their workman, which was received by the Central Government on 19-10-1994.

[No. L-40012/168/92-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer
ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I AT BOMBAY
PRESENT :—

Shri Justice K. G. Sindhakar, Presiding Officer
Reference No. CGIT-92 of 1993

PARTIES :—

Employers in relation to the management of
MTNL, Bombay

AND

Their Workmen

APPEARANCES :—

For the management:—No appearance

For the workman:—No appearance

INDUSTRY : Telephones

STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 13th day of September, 1994

AWARD

This reference has been made by Government of India, Ministry of Labour under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of the following dispute.

“Whether the action of the management of Mahanagar Telephone Nigam Limited, Bombay in terminating the services of Shri Ravikant R. Tondle, Mazdoor w.e.f. October 1986 without either holding domestic enquiry or complying the provisions of I.D. Act, 1947 is just, proper and legal? If not, to what relief is the workman entitled to?”

2. The parties have been served with notice of this proceeding. The workman has not however filed any statement of claim so far which the management has filed written statement.

3. It is contended by the management that the abandoned duly voluntarily relinquished his job by absenting himself from 24-10-1986

4. Since there is even no statement of claim of filed by the workman, I am unable to find out under what circumstance he contended that there is termination of service and that too unjustifiably. No relief the workman entitled is to.

Award accordingly.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1994

का.प्र. 3235:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धन के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 33-क के अन्तर्गत दायर शिकायत में, अनुबंध में निदिष्ट राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या डा०-1179/94-आर्. आर. (बी-2)]

वी. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st October, 1994

S.O. 3235.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the National Industrial Tribunal, Bombay as shown in the Annexure in the complaint filed against the management of L.I.C. of India under Section 33-A of the said Act which was received by the Central Government on 18-10-1994.

[No. Dy. 1179/94-IR (B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE NATIONAL INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

PRESENT :—

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer
COMPLAINT NO. NTB-2 OF 1988

(Arising out of Ref. No. NTB-1 of 1987)

PARTIES :—

Mr. Amod Prakash Gupta ..Complainant

Vs.

1. Divisional Manager,
L.I.C. of India,
Jeevan Prakash, Prabhat Nagar,
Meerut (U.P.)

2. L.I.C. of India,
Yogakshema, Fort,
Bombay. .. Respondents

APPEARANCES :—

For the Complainant.—Shri Dharap, Advocate.

For the Respondents.—Shri Bukhari, Advocate.

INDUSTRY : Insurance **STATE :** Uttar Pradesh

Bombay, dated the 12th day of September, 1994

AWARD

This is a complaint under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947, filed by Shri A. P. Gupta. I shall briefly state the grievance of the complaint. The Complainant was appointed as an Assistant in the office of the Life Insurance Corporation of India, at Rampur, (U.P.) in the year 1973. He came to be transferred to Chandausi, U.P. in the year 1979 and was subsequently selected as Cashier with effect from 1-2-1983. He came to be charge sheeted and ultimately dismissed from the services of the LIC of India. This dismissal is challenged in this present complaint.

2. He further contends that, at the time of passing of this order of dismissal, there was a proceeding under Section 33A of the Act, and therefore, approval of this Tribunal was necessary to the dis-

missal in view of the pendency of the said proceedings which was not sought by the Corporation and therefore, there has been a breach of the provisions of Section 33(2)(b) of the Industrial Disputes Act, 1947. It is on these allegations, that he files the present complaint under Section 33-A of the Act.

3. The management has filed written statement, and the allegations with regard to wrongful and illegal dismissal are denied while stating that the same has been in accordance with the provisions of law and principles of natural justice.

4. With regard to the contention, that, the provisions of Section 33(2)(b) of the Act are violated, the management contends that the same was not true.

5. According to the management of LIC of India, the reference was under Section 36A of the Act, and was for the purpose of interpretation of an Award passed by this Tribunal and therefore, it was not necessary to seek approval of this Tribunal for the action of the management. It is also contended on behalf of the management that he is not a "concerned workman", and therefore the provisions of Section 33(2)(b) were not attracted. In short, the submission is, that the complaint is liable to be rejected. It is further contended on behalf of the management, that in any even, the management has a right to establish that the dismissal order was legal and justified.

6. Rejoinder has been filed by Shri Gupta, and he stated therein that he was a concerned workman, and that the provisions of Section 33(2)(b) of the Act were attracted in the present case.

7. I have heard the learned counsel appearing on either side. On behalf of the complainant, written submissions have been also filed.

8. The complainant filed an affidavit, and he has been subjected to cross examination on behalf of the management. The Corporation also examined the Enquiry Officer Shri Ajit Kumar Mehta, who has been also cross examined on behalf of the complainant.

9. The first point that has been raised by Shri Bhukari, appearing on behalf of the Corporation is, that the provisions of Section 33(2)(b) are not attracted inasmuch as, there was no proceeding pending in respect of an industrial dispute. His submission is that, the proceeding pending was Under Section 36-A of the Act, and that was for the limited purpose of interpretation of certain provisions of an Award of the National Industrial Tribunal. In this connection, he has relied upon the decision of the Patna High Court in a case between Sendra Bansjora Colliery Co. P. Ltd. and Shantilal M. Bhatt and another, reported in 1963-II LLJ. page 331. It was held in that case, that a complaint under Section 33-A of the Act, before an Industrial Tribunal before which, a proceeding under Section 36-A of the Act is pending must be incompetent, and not maintainable since the proceedings under Sections 36-A are not with regard to Industrial disputes, and are references made by the Central Government for

interpretation of the Award, either the entire award or a part thereof. Considering the provisions of Sections 36-A, 33(1), 33(3), 10, 11 and 15 of the Act, as well as Section 20(3) of the said Act, the Patna High Court held that the reference made by the appropriate Government under Section 36A of the Act, is not a reference in respect of an industrial dispute, within the meaning of Section 33(1) of the Act, and that the Central Government Industrial Tribunal had no jurisdiction to entertain a complaint under Section 33-A of the Act.

10. It so happened in this case before me, that the Central Government made a reference to this Tribunal on 20-5-1985 and the dispute referred as mentioned in the schedule was "What should be the wages and other conditions of service of Badli, Temporary and part-time workman of the Life Insurance Corporation of India, as well as the conditions of their absorption into regular cadre?" This reference made to this Tribunal under Section 10(1)(d) of the Act, was answered by this Tribunal by its Award dated 17-4-1986. Thereafter, the reference made was about the interpretation of certain clauses of the Award and its implementation, and therefore, the Central Government, in exercise of its powers under Section 36-A of the Act, referred the question to the National Industrial Tribunal for decision and Shri Justice M. S. Jamdar, the then Presiding Officer of the said Tribunal was called upon to interpret the Award. The reference made under Section 36-A by the Central Government was as under :—

"Can the award dated 17-4-1986 with special reference to paragraphs 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 64 and 66 and the interim order dated 14-3-1986 be interpreted to mean that the Central Office of the LIC of India is empowered to issue instructions/guidelines as contained in their circulars issued in this behalf to implement the directions of the award. If not, what could be the correct interpretation of various directions covered by the said paragraphs in the circumstances of the case? Whether the term 'absorption' referred to at various places in the award can be interpreted to mean 'recruitment'?"

It is during the pendency of this reference made under Section 36-A of the Act, the workman came to be dismissed on 3-6-1988, for which according to the workman, no approval was sought by the management under Section 33(2)(b) of the Act, and therefore, he filed this complaint on 19-7-1988. The ruling of the Patna High Court, with respect, I find squarely applies to the facts of the present case, and in my opinion provisions of Section 33(2)(b) were not attracted. Approval under Section 33(2)(b) was not sought for the simple reasons that the proceeding pending was not in respect of an industrial dispute and that the proceeding pending was in respect of interpretation of certain clauses of the award given in reference No. NTB-1 of 1985 by this Tribunal and therefore the approval of this Tribunal under Section 33(2)(b) of the Act was not necessary.

11. The learned counsel appearing on behalf of the workman Shri Gupta relied upon the decision in the case between New India Motors P. Ltd., and Mr. Moris K. T., reported in 1960-1 LLJ. page 551. That was a case, in which the point that raised for consideration before the Supreme Court was interpretation of the word "workman concerned in a dispute". The Supreme Court held that there was no justification for holding that the workman concerned must be a workman directly or immediately concerned in such dispute, and no justification for adding the further qualification of directly or immediately concerned, which the narrow construction necessarily assumes. With respect, I find that the point raised in this case is, directly covered in the decision in Sandra Banssora Colliery Company and Shantilal M. Bhatt, (Supra). I therefore, find that the pendency of a reference under Section 36-A would not attract the provisions of Section 33.

12. The next contention raised on behalf of the Corporation is that, Shri Gupta was not a concerned workman, and that therefore also, the provisions of Section 33(2)(b) were not attracted. The argument advanced is that, the dispute referred to this Tribunal was with regard to the wages to be paid to the category of Badli Employees, Temporary and part-time employees engaged by the LIC of India, as well as their conditions of service and absorption into regular service. It was this reference which was answered by the Tribunal by its award in reference No. NTB-1 of 1985, and that the subsequent reference made under Section 36A was for clarification clauses of that award.

13. So far as Shri Gupta is concerned he is admittedly not a badli, temporary, or a part-time employee, and therefore, the wages and other service conditions of such workmen being the subject of the reference. In this connection the answers given by Shri Gupta in the course of his cross-examination have been referred to and relied upon. He contended that he was a permanent employee of the Corporation, and that in 1984, or any time prior to his suspension, he did not work as Temporary/Casual or Badli workman, nor did he work as a part time employee. In 1973 he was made permanent as an Assistant, and in 1982 he was appointed as Cashier, which was equivalent to the Assistant's post. However, the decision in the case between New India Motors (P) Ltd. and Morris (K.T.) reported in 1960(1) LL-51 the Supreme Court held that the term should not be construed to mean workman directly or actually concerned in such dispute. In view of this decision I find that the contention that Mr. Gupta is not a concerned workman cannot be accepted. In view of my finding on the point that Section 33(2)(b) is not attracted and there is no contravention of Section 33(2)(b) of the Act. The complaint is liable to be rejected Complaint rejected.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1994

क्र.सं. 2236:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दक्षिण रेलवे मद्रास के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों

और उनके कर्मचारों के बीच, संघर्ष में निश्चित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/48/87-डी-II(बी) आई आर (बी-I)]

वा. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st October, 1994

S.O. 3236.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Southern Railway, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 19-10-94.

[No. L-41012/48/87-D.II(B)/IR(B-I)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL TAMIL-NADU, MADRAS

Monday, the 1st day of August, 1994

PRESENT :

Thiru K. Ponnusamy, M.A. B.L., Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 114/92

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workman and the Management of Southern Railway, Madras)

BETWEEN

Shri S. Marimuthu,
2, Adhishesha Nagar,
6th Street, Perambur
Madras-600 012.

AND

The General Manager,
Southern Railway,
Madras-600 001.

REFERENCE :

Order No. L-41012/48/87-D.II(B), dated 21-12-1992, Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Tuesday, the 12th day of July, 1994 upon perusing the reference, Claim and Counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Tvl. T. K. Ramkumar, R. S. Varadharajan, Ravikumar and V. Parthiban, Advocates appearing for the workman, and of Thiru R. Venugopalan,

Advocate appearing for the Management, and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following :—

AWARD

This reference has been made for the adjudication of the following issue :

"Whether the Management of Southern Railway in relation to the Carriage and Wagon Workshop, Perambur, Madras is justified in removing Shri S. Marimuthu, T. No. 735, Fitter from service w.e.f. 16-7-1982? If not, what relief the concerned workman is entitled to?"

2. The case of the Petitioner briefly stated is as follows.—The petitioner entered into the service under the respondent in the year 1949. The petitioner had been carrying on his duties and functions without any blemish ever since he entered into service. He worked as Fitter under the control of the Deputy Chief Mechanical Engineer (Carriage, Workshops) Southern Railway, Perambur, Madras in the year 1978. While he was faithfully carrying on his duties, to his shock and surprise charge sheet dated 9-10-78 was issued to him. He submitted a detailed explanation denying the charges as baseless and false. Despite his explanation domestic enquiry was ordered and conducted. The charges are not proved by legal evidence. The procedure adopted by the Enquiry Officer is not in accordance with principles of natural justice. There is no direct evidence to connect the petitioner with charges. He is not guilty of the charges framed against him. In spite of lack of competent evidence to prove the charges, the Enquiry Officer's finding that the Petitioner is guilty of charges is erroneous. The findings of the Enquiry Officer is not supported by either oral or documentary evidence. The Disciplinary Authority concurred with the findings of the Enquiry Officer, and removed the petitioner from service with effect from 22-6-1981. He preferred an appeal dated 31-7-1981 and it was rejected without considering the various objections raised by him. The rejection of his appeal is a non-speaking order. He preferred a revision to the General Manager. The General Manager ordered reinstatement of the petitioner by his order dated 14-6-1982 without prejudice to the fresh D.A.A.R. action. He was reinstated in service. He was removed from service arbitrarily with effect from 16-7-1982. On 15-7-1982 by the Disciplinary Authority. No fresh opportunity was given to the petitioner. No fresh enquiry was conducted. His removal from service is illegal. He preferred an appeal dated 27-8-1982 pointing out the infirmities in the order of the Appellate Authority, and they were rejected without any reason. The order passed in the appeal is cryptic and it was communicated to him. He preferred a revision. It received the same fate. Amazing irregularities and infirmities are to the conduct of the domestic enquiry. The order passed by the Disciplinary Authority is a non-speaking order. The order of his dismissal dated 10-1-85 is illegal arbitrary and void. The charges are flimsy, undergrounded and is not proved by any legal evidence. The principles of natural justice is not followed in the domestic enquiry. He was not given

an opportunity to prove his innocence. The Enquiry Officer failed to appreciate that the admission of the petitioner was obtained by force and intimidation and as such if cannot be relied upon as an evidence. The finding of the Enquiry Officer is biased. It has caused prejudice to the petitioner. The finding of the Enquiry Officer are perverse and is based on presumptions and assumptions. The finding of the Enquiry Officer is based on conjecture and surmises and is unsupported by fact of law. The order of removal of the petitioner from service, dated 12-6-1981, based on the perverse finding of the Enquiry Officer, is arbitrary and illegal. The order of removal passed by the Disciplinary Authority suffers for want of bonafides and non-application of mind. The rejection of the appeal is contrary to the established principles and the provisions of Railway Service Disciplinary and Administrative Rules. The rejection of the revision petition is illegal and arbitrary since no reason is given for its rejection. His removal from service is disproportionate.

3. The defence of the respondent briefly stated as follows.—The petitioner was in unlawful possession of railway property of 15-1/2 kgs. of brass pieces concealed in a gunny bag in back of his bicycle while passing through the gate. He voluntarily gave confession statement and it was recorded. The brass pieces were seized under a mahazar. He was placed under Suspension from 29-4-1978 and it was revoked on 29-10-1978, without prejudice to the D.R. case being taken against him. Charge sheet was issued for major penalty and D.A.R. enquiry was conducted. The petitioner and his defence helper attended the domestic enquiry. The petitioner was given ample opportunity and all facilities to defend him. The Enquiry Officer submitted his report finding the petitioner guilty of the charge levelled against him. Copy of D.A.R. enquiry report was furnished to the petitioner. After receiving the penalty advice, the petitioner was removed from service with effect from 23-6-1981 by W.M. Carriage Works who is the competent authority. The petitioner preferred an appeal to the Appellate Authority and revision petition to the General Manager. As per the orders of Chief Personnel Officer, Madras CEE ordered reinstatement of the petitioner in service, setting aside the order of removal on technical ground. The petitioner was placed under suspension after reinstatement till the issue of the fresh penalty advice of the Deputy Chief Mechanical Engineer|CW|Per. The intervening period between the removal from service i.e. 23-6-1981 and to reinstatement on 17-6-82 was treated as duty with pay. The petitioner joined duty on 17-6-1982. The DCMF|CW|PER, has reconsidered the issue and agreed with the finding of the Enquiry Officer. Fresh penalty advice removing the petitioner from service with effect from 16-7-1982 was passed since offence is a serious one involving moral turpitude. Petitioner acknowledged the order of his removal from service. He preferred an appeal to the ACME|CW|PER. But the ACME|CW|PER has confirmed the punishment by passing a speaking order. The General Manager considered the revision petition but he rejected it. The petitioner challenged his removal from service by filing OS No. 5357/85 on the file of the City Civil Court, which was transferred to CAT, Madras as T.A.

548|86. The said Appellate Tribunal dismissed the petition as withdrawn. The petitioner has raised the industrial dispute before the Assistant Labour Commissioner (Conciliation), Madras. The removal of the petitioner from service is justified.

4. The point for determination is.—“Whether the Management of Southern Railway, in relation to the Carriage and Wagon Workshop, Perambur, Madras is justified in removing Shri S. Marimuthu, T. No. 735, Fitter from service with effect from 16-7-82? If not to what relief Thiru Marimuthu is entitled to?”

5. The Point.—The petitioner entered the service under the respondent in the year 1949. In the year 1978, the petitioner worked as Fitter under the Control of the Deputy Chief Mechanical Engineer (Carriage Workshop), Southern Railway, Perambur, Madras. The petitioner was charge sheeted on 14-4-1978 that he was in unlawful possession of 46 broken pieces of brass guide roller, four wheels of various sizes of the same thickness, and width weighing about 13-1/2 kgs. concealed in a gunny bag on his bicycle, is borne out by Ex. W-1. The petitioner submitted his explanation denying the charges levelled against him is, baseless and false. Since his explanation was unconvincing and unsatisfactory, the domestic enquiry was ordered and conducted by the Enquiry Officer appointed by the Disciplinary Authority is evidenced by Ex. W-2. The Enquiry Officer after carefully scrutinising and hearing the oral evidence and considering the documents, found the petitioner guilty of the charge framed against him, is made out by Ex. W-3. There is some discrepancy with regard to the availability of electric light to the workers on the workspot does not militate against the case of the respondent. The said articles do not possess the mark of Southern Railway does not mean that they do not belong to the Southern Railway since the petitioner has not produced any document and there is no proof on his side that the articles do not belong to the Southern Railway. The said articles were seized at the gate by the Security Guard is established by Ex. W-1. The petitioner voluntarily gave the confession statement admitting the charge. His confession statement was obtained by force or by intimidation. The charge framed against the petitioner is proved by the circumstantial evidence is substantiated by Ex. W-4. The disciplinary authority after carefully scrutinising the evidence and consideration of the documents, concurred with the finding of the Enquiry Officer and past records, dismissed the petitioner from service with effect from 23-6-1981 afternoon is established by Ex. W-4. The petitioner preferred an appeal to the Assistant Mechanical Engineer and it was dismissed is, borne out by Exs. W-5 and W-6. The petitioner preferred an appeal to Assistant Chief Mechanical Engineer is evidence by Ex. W-9. That appeal was dismissed is borne out by Ex. W-10. He was removed from service with effect from 16-7-1982 is made out by Ex. W-8. He preferred a review petition to Chief Works Manager and his removal from service was set aside and the period of his removal from service was treated as non-duty

period without prejudice to take fresh action and he was reinstated is borne out by Ex. W-7. He reported to duty on 16-7-1982. The Deputy Chief Mechanical Engineer reconsidered the revision and accepted the finding of the Enquiry Officer. He was removed from service on 16-7-1982. The petitioner preferred a revision to the General Manager and it was dismissed on the ground that misconduct on the part of the petitioner is a serious one, is made out by Ex. W-11. After reinstatement fresh action was taken against the petitioner. The Disciplinary Authority based on materials already placed, before him came to the conclusion that, the petitioner is guilty of the charges levelled against him. Fresh domestic enquiry is not necessary. The petitioner was given reasonable opportunity to defend his case. The finding of the Enquiry Officer is supported by sufficient materials placed before him and legal evidence. The domestic enquiry does not suffer from any irregularities and infirmities. The finding of the Enquiry Officer is not perverse.

6. The power of this Tribunal is limited, in nature. The Tribunal has no power to reappreciate the evidence and disregard the finding of the Enquiry Officer, unless his finding is perverse. The finding of the Enquiry Officer is not perverse. This Tribunal is not an Appellate Authority sitting over the finding of the Enquiry Officer. The Enquiry Officer conducted the enquiry fairly and properly. The domestic enquiry was conducted by the Enquiry Officer is just. The domestic enquiry was conducted in accordance with the rules, procedure, provisions of law, equity and good conscience and the principles of natural justice. The aforesaid aspects have been duly complied with in the domestic enquiry conducted by the Enquiry Officer. Prima facie case has been made out against the petitioner. The removal of the petitioner from service by competent authority i.e. appointing authority, the punishment is proportionate to the crime committed by the petitioner. The removal of the petitioner from service is just and proper. The removal of the petitioner from service is neither illegal nor improper. The removal of the petitioner from service is justified.

7. By taking all the aforesaid aspects into consideration, this Tribunal comes to the irresistible conclusion that the Management of Southern Railway in relation to the Carriage-workshop, Perambur is justified in the removing Shri S. Marimuthu, T. No. 735, Fitter from service with effect from 16-7-1982 and S. Marimuthu is not entitled to any relief as prayed for by him. The point is found against the petitioner.

In the result, an award is passed rejecting the claim of the petitioner to reinstatement in service and justifying the removal of the petitioner from service by the Southern Railway. No costs.

Dated, this the 1st day of August, 1994.

THIRU K. PONNUSAMY, Industrial Tribunal.

WITNESSES EXAMINED

For both sides : None.

DOCUMENTS MARKED

For Workman :

- Ex. W-1|9-10-1978.—Charge memo issued to Petitioner-workman Thiru S. Marimuthu.
- Ex. W-2| —Proceedings of the Enquiry Officer.
- Ex. W-3|30-4-1981.—Findings of the Enquiry Officer with enclosures.
- Ex. W-4|22-6-1981.—Order of removal issued to the Petitioner-worker.
- Ex. W-5|3-12-1981.—Order of Appellate Authority.
- Ex. W-6|22-1-1982.—Revision petition filed by the Petitioner-workman before the General Manager, Southern Railway, Madras-3.

Ex. W-7|14-6-1982.—Order of reinstatement.

Ex. W-8|15-7-1982.—Order of removal issued to the Petitioner-worker.

Ex. W-9|27-8-1982.—Appeal preferred by the Petitioner-worker before the Additional Chief Mechanical Engineer, Carriage and Wagon Works, Southern Railway, Madras-23.

Ex. W-10|21-10-1982.—Order of Appellate Authority.

Ex. W-11|24-11-1982.—Revision petition filed by the Petitioner-workman before the General Manager, Southern Railway, Madras-3.

For Management :
Nil.

